3 राजधानी
हरे फलदार पेड़ों की कटाई पर रोक

6 अभिमत
दीर्घकालीन विकास को लक्षित बजट

10 राष्ट्रीय
कर्नाटक सरकार ने बदला रामनगर जिले का नाम

11 विदेश
जयशंकर मिले रूसी विदेश मंत्री से

RNI NO.UPHIN/2010/36547
वर्ष 14 अंक 274
लखनऊ, शनिवार, 27 जुलाई, 2024
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
लखनऊ
नगर संस्करण

लखनऊ, नई दिल्ली और रायपुर से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com

मुझे नेतृत्व करना अच्छा लगता है

स्पोर्ट्स-12

पाकिस्तान ने अतीत से कोई सबक नहीं सीखा: प्रधानमंत्री

मोहित कंधारी। जम्मू

25वें कारगिल विजय दिवस समारोह के अवसर पर पड़ोसी देश को एक संक्षिप्त संदेश भेजते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय सैनिक पूरी ताकत से आतंकवाद को कुचल देंगे और दुश्मन को करारा जवाब दिया जाएगा। तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद लद्दाख की अपनी पहली यात्रा में मोदी ने पाकिस्तान को यह भी याद दिलाया कि उसने अतीत से कुछ नहीं सीखा है। बिना कोई लांछन लगाए प्रधानमंत्री ने कहा, कारगिल में हमने न केवल युद्ध जीता, बल्कि सच्चाई, संयम और शक्ति का अविश्वसनीय उदाहरण भी पेश किया। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के धोखे पर उस समय प्रकाश डाला जब भारत शांति बनाए रखने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा, सच्चाई से झूठ और आतंक को घुटनों पर ला दिया गया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद की निंदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान को अतीत में हमेशा हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान ने अपने अतीत से कुछ नहीं सीखा है और प्रासंगिक बने रहने के लिए आतंकवाद और छद्म युद्ध की आड़ में युद्ध छेड़ रखा है।

द्रास में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल वार मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित की।

कर्तव्य का पालन करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आज मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आका सीधे मेरी आवाज सुन सकते हैं। मैं इन्हें बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा, आतंकवाद के संरक्षकों के नापाक इरादे कभी सफल नहीं होंगे। हमारे सैनिक पूरी ताकत से आतंकवाद को कुचलेंगे और दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने दोहराया, भारत विकास के रास्ते में आने वाली सभी चुनौतियों पर काबू पा लेगा, चाहे वह लद्दाख हो या जम्मू-कश्मीर। 26 जुलाई, 1999 को, भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय की सफल परिणति की घोषणा की, जिसमें लगभग तीन महीने की लंबी लड़ाई के बाद कारगिल क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के भारतीय पक्ष पर पाकिस्तानी घुसपैठियों/सेना के नियमित लोगों द्वारा कब्जा किए गए स्थानों को पुन: प्राप्त कर लिया गया। अग्निपथ योजना पर बढ़ रही राजनीतिक ताकत का जवाब देते हुए, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि अग्निपथ का उद्देश्य सेनाओं को युवा और लगातार युद्ध के लिए तैयार रखना है।

प्रधानमंत्री ने इस संवेदनशील विषय के घोर राजनीतिकरण का जिक्र करते हुए कहा, सच्चाई तो यह है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश को सक्षम युवा भी मिलेंगे। निजी क्षेत्र और अर्धसैनिक बलों में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणा की गई है। अग्निपथ योजना के पीछे पेंशन का बोझ बचाने की मंशा को मुख्य कारण बताए जाने वाले दुष्प्रचार को खारिज करते हुए प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि आज भर्ती होने वाले सैनिकों की पेंशन का बोझ 30 साल बाद आएगा, इसलिए इसके पीछे का कारण यह नहीं हो सकता। योजना। उन्होंने कहा, हमने सशस्त्र बलों द्वारा लिए गए इस फैसले का सम्मान किया है क्योंकि हमारे लिए देश की सुरक्षा राजनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के युवाओं को गुमराह करने वालों को अतीत में सशस्त्र बलों के प्रति कोई सम्मान नहीं था। वन रैंक वन पेंशन पर पिछली सरकारों द्वारा किए गए झूठे वादों को याद करते हुए, प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि यह वर्तमान सरकार थी जिसने इस योजना को लागू किया जहां (शेष पेज 9)

ओलंपिक समारोह का रंगारंग उद्घाटन

भाषा। पेरिस

खूबसूरत सीन नदी पर नावों में खिलाड़ियों ने परेड की और परंपरा से हटकर हुए 33वें ओलंपिक खेलों के रंगारंग उद्घाटन समारोह में शुक्रवार को फ्रांस ने अपनी सांस्कृतिक विविधता, क्रांति के इतिहास, वास्तुकला की शानदार विरासत की बानगी दुनिया के सामने पेश की। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैन्युअल मैकरोन और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रमुख थॉमस बाक के साथ मौजूद थे जब फ्रांस के महान फुटबॉलर जिनेदीन जिदान को पहले से रिकॉर्ड किए गए वीडियो में ओलंपिक मशाल के साथ पेरिस की सड़कों पर दौड़ते दिखाया गया।

पेरिस में ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में फ्रांस के ध्वज के रंगों वाला उठता धुआं

छह किलोमीटर की परेड आस्टरलिज ब्रिज से शुरू हुई जिसमें 85 नावों में 205 देशों के 6800 से अधिक खिलाड़ी सवार थे और एक शरणार्थी ओलंपिक टीम भी थी। भारी संख्या में खिलाड़ियों ने कल स्पर्धाएं होने के कारण उद्घाटन समारोह में भाग नहीं लिया। फ्रांस की वर्णमाला के क्रम के अनुसार टीमों का आगमन हुआ। पहले ओलंपिक खेलों के जनक यूनान का दल आया जिसके बाद शरणार्थी टीम आई।

भारतीय दल की अगुवाई दो ध्वजवाहकों दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पी वी सिंधू और टेबल टेनिस दिग्गज अचंत शरत कमल ने की। नावें शहर की ऐतिहासिक इमारतों कैथेड्रल आफ नोत्रे डेम, लावरे म्युजियम और कुछ आयोजन स्थलों से होकर गुजरी। अमेरिकी पॉपस्टार लेडी गागा ने अपने सुरों से समा बांधा। उद्घाटन समारोह का निर्देशन थॉमस जॉली ने किया था। रंगारंग समारोह के बीच एक रहस्यमय मशालवाहक भी आकर्षण का केंद्र रहा जो शहर के मशहूर स्मारकों के पास से मशाल लेकर गुजरा। शहर में उद्घाटन समारोह के लिए दो लाख से अधिक मुफ्त टिकट दिए गए थे जबकि एक लाख से अधिक टिकट बिके थे। आयोजकों ने सुरक्षा और लॉजिस्टिक की चुनौतियों से पार पाते हुए पूरे शहर को उद्घाटन समारोह का हिस्सा बनाकर अभूतपूर्व नजारा पेश किया। भारत के 117 खिलाड़ी इन खेलों में भाग ले रहे हैं जिनमें 47 महिलाएं हैं। आयोजकों ने दावा किया है कि यह खेलों के इतिहास का सबसे बड़ा समारोह होगा जिसे तीन लाख से अधिक लोग सीन नदी के किनारे और अरबों लोग टीवी पर देखेंगे। पेरिस में 1900 और 1924 के बाद तीसरी बार ओलंपिक हो रहे हैं।

समारोह की सुरक्षा के लिए भारी तादाद में इंतजामात किए गए। शहर की सड़कों पर नाकेबंदी की गई और भारी संख्या में पुलिसकर्मी गश्त लगा रहे थे। इसके साथ ही सीन नदी के आर पार धातु के सुरक्षा बैरियर लगाए गए हैं। ओलंपिक की सुरक्षा के लिए 45000 से अधिक पुलिसकर्मी और 10000 सैनिक तैनात किए गए हैं। ओलंपिक वालिंटियर , कर्मचारियों और खेलों से जुड़े बाकी लोगों को मिलाकर कुल दस लाख लोगों की पृष्ठभूमि की जांच की गई। इसके अलावा सीन नदी के किनारे कड़ी सुरक्षा वाले इलाकों में प्रवेश के लिए पास का आवेदन करने वालों की भी पृष्ठभूमि की विस्तार से जांच की गई है।

कांवड़ मार्ग पर नेमप्लेट मामले में कोर्ट ने अंतरिम रोक बढ़ाई

पीटीआई। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को भाजपा शासित उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश द्वारा जारी उन निर्देशों पर रोक लगाते हुए 22 जुलाई के अपने अंतरिम आदेश को बरकरार रखने का निर्देश दिया, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित भोजनालयों को मालिकों, कर्मचारियों के नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने के लिए कहा गया था। हिंदू कैलेंडर के श्रावण महीने के दौरान शिवलिंगों पर जलाभिषेक करने के लिए विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में भक्त गंगा से पवित्र जल की कांवड़ लेकर आते हैं। कई श्रद्धालु इस महीने में मांस खाने से परहेज करते हैं, जिसे वे पवित्र मानते हैं। कई लोग तो प्याज और लहसुन युक्त भोजन भी नहीं खाते।

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि वह 22 जुलाई के आदेश पर कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं करेगी, क्योंकि हमने अपने 22 जुलाई के आदेश में जो कुछ कहा जाना था, वह कह दिया है। हम किसी को नाम उजागर करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। पीठ ने मध्य प्रदेश और

उत्तराखंड सरकारों से उनके संबंधित निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा। पीठ ने याचिकाकर्ताओं को राज्य सरकारों के जवाबों पर प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दी और मामले की अगली सुनवाई पांच अगस्त के लिए तय की। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों के अलावा मध्य प्रदेश के उज्जैन में भाजपा शासित नगर निकाय ने भी दुकान मालिकों को इसी तरह का निर्देश जारी किया था। उज्जैन में भगवान शिव का प्रसिद्ध महाकाल मंदिर है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने (शेष पेज 9)

सुप्रीम कोर्ट ने विधेयकों पर बंगाल, केरल के राज्यपालों के सचिवों व केंद्र से जवाब मांगा

पीटीआई। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत विपक्षी दलों द्वारा शासित केरल और पश्चिम बंगाल की उन अलग-अलग याचिकाओं पर विचार करने पर शुक्रवार को सहमत हो गया जिनमें आरोप लगाया गया है कि संबंधित विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी नहीं दी गई। केरल ने यह भी आरोप लगाया कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कुछ विधेयक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे थे और उन्हें अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने याचिकाओं पर संज्ञान लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय और केरल के राज्यपाल खान एवं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस के सचिवों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह के भीतर उनसे जवाब मांगा है। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने तृणमूल कांग्रेस नीत पश्चिम बंगाल सरकार को भी निर्देश दिया कि वह याचिका में गृह मंत्रालय को भी पक्ष बनाए। केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) नीत वाम (शेष पेज 9)

अग्निवीरों को पुलिस और पीएसी में देंगे वेटेज: योगी

● नीति आयोग की बैठक में शामिल होने मुख्यमंत्री गए दिल्ली

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि देश की सेवा करके लौटने वाले अग्निवीरों को यूपी पुलिस और पीएएसी बल में वेटेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों के रूप में देश को ट्रेंड और अनुशासित युवा सैनिक मिलेंगे। सीएम योगी ने अग्निवीर मुद्दे पर विपक्ष की राजनीति को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि विरोधियों का काम हर प्रगति और रिफॉर्म वाले कार्य में अड़ंगा लगाने, टांग अड़ाने और अफवाह फैलाने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। बीते 10 साल में भारत में बेहतरीन रिफॉर्म हुए हैं। सीएम योगी ने कहा कि भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और इसके साजो-सामान के मामल में हम आत्मनिर्भरता की ओर से बढ़ रहे हैं।

नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में शामिल होने से

लखनऊ में कारगिल दिवस पर कार्यक्रम में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

पहले शुक्रवार शाम यहां अपने सरकारी आवास पर सीएम योगी मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी भी देश और समाज के लिए प्रगति और समृद्धि के नित नये प्रतिमान स्थापित करने के लिए समय-समय पर होने वाला रिफॉर्म अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हर फील्ड में पिछले 10 साल में बेहतरीन रिफॉर्म हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने और दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में लाने के लिए कार्य किये गये हैं। एक तरफ हम समृद्धि के नित नये सोपान छू रहे हैं, तब हमें राष्ट्रीय सुरक्षा को भी उतना ही महत्व देना होगा। सेना और उनके साजो सामान में आत्मनिर्भरता के लिए उठाये गये कदम हों या आधुनिकिकरण के लिए लिए गये त्वरित निर्णय, आज अत्याधुनिक फाइटर प्लेन भारत के पास हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी और तमिलनाडु में डिफेंस इंडस्ट्रियल कारीडोर विकसित हो रहा है। यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के 6 नोड में हजारों करोड़ का निवेश आया है। चाहे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का कार्य हो या ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की दिशा में प्रगति, हमने लंबी छलांग लगाई है। सेना भी हमारी इस गति के साथ आगे बढ़ रही है। अग्निवीर की योजना भारतीय सेना में इसी दृष्टि से आगे बढ़ाई गई है। इसे लेकर युवाओं में उत्साह है। 10 लाख अग्निवीर भारतीय सेना के अग्निपथ पर मजबूत जवान के रूप में अपनी सेवा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दुर्भाग्य है कि कुछ राजनीतिक दलों के लिए स्वयं की राजनीति देश से बड़ी हो गई है। वो देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। वह हर रिफॉर्म और प्रगति वाले कार्य में टांग अड़ाने, गुमराह करने और बयानबाजी करने जैसे कृत्य करते रहते हैं। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर लगातार युवाओं को गुमराह कर रहा है। योगी ने कहा कि आज अग्निवीर में युवा उत्साह के साथ भर्ती हो रहे हैं। इसके बाद उन्हें पैरा मिलिट्री और सिविल पुलिस में समायोजित करने की व्यवस्था की जा रही है। यूपी सरकार ने भी कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे-जैसे आगे बढ़ती है और जब ये युवा अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम यूपी पुलिस और पीएसी बल में इनके समायोजन की सुविधा और वेटेज देंगे। अग्निवीरों के रूप में ट्रेन्ड और अनुशासित युवा हमें मिलेंगे। इसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

एनटीए ने घोषित किए नीट-यूजी के अंतिम परिणाम

पीटीआई। नई दिल्ली

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने विवादों से घिरी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी के अंतिम परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद भौतिकी के एक प्रश्न के अंकों को ध्यान में रखते हुए परिणाम घोषित किए गए। एनटीए ने कहा था कि इस प्रश्न के दो सही उत्तर हैं। एनटीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पुन: संशोधित स्कोर कार्ड को अब घोषित कर दिया गया है। पहले टॉपर घोषित किए गए 67 उम्मीदवारों में से 44 ने उस विशेष भौतिकी प्रश्न के लिए दिए गए अंकों के कारण पूरे अंक प्राप्त किए थे। बाद में टॉपर की संख्या घटाकर 61 कर दी गई थी, क्योंकि एजेंसी ने कुछ परीक्षा केंद्रों पर समय के नुकसान की भरपाई के लिए छह उम्मीदवारों को दिए गए कृपांक वापस ले लिए थे। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) 2024 के असफल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने इस परीक्षा को रद्द करने और दोबारा कराने के अनुरोध वाली याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया था। न्यायालय ने कहा था कि परीक्षा की विश्वसनीयता के व्यवस्थित तरीके से प्रभावित होने और अन्य गड़बड़ियों को दर्शाने वाली कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) नीट-यूजी 2024 में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहा है।

क्रिकेट पिच पर बेटियों ने फिर दिखाया दमखम

● गत एशिया कप चैंपियन भारत फिर फाइनल में, एकतरफा सेमीफाइनल में बांग्लादेश को हराया, स्मृति और रेणुका चमकीं

पीटीआई। दाम्बुला

तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ने शुरूआती ओवरों में तीन विकेट चटकाकर बांग्लादेश की पारी को झकझोरा तो वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने ताबड़तोड़ नाबाद अर्धशतकीय पारी खेलकर महिला टी20 एशिया कप के सेमीफाइनल में भारत को 10 विकेट की शानदार जीत दिलाई। भारत ने बांग्लादेश को आठ विकेट पर 80 रन

पर रोकने के बाद 11 ओवर में बिना किसी नुकसान के 83 रन बनाकर एकतरफा जीत दर्ज की। मंधाना ने 39 गेंद में नौ चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 55 और शेफाली वर्मा ने 28 गेंद में दो चौके की मदद से नाबाद 26 रन का योगदान दिया। दोनों की आक्रामक बल्लेबाजी से भारत को 54 गेंद शेष रहते लक्ष्य हासिल करने में कोई परेशानी नहीं हुई।

भारतीय टीम के सामने रविवार को खेले जाने वाले फाइनल में श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता की चुनौती होगी। लक्ष्य का पीछा करते हुए मंधाना और शेफाली ने मैदान के चारों ओर मन मुताबिक शॉट लगाए। टीम ने पावरप्ले में बिना किसी नुकसान के 46 रन बनाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। शेफाली को 21 रन के स्कोर पर राबिया खान ने कैच टपकाकर जीवनदान दिया तो वहीं जहांआरा आलम की गेंद पर मंधाना के 35 रन के स्कोर पर कैच आउट होने के बाद गेंद नो बॉल करार दी गई। इस वामहस्त बल्लेबाज ने कुछ शानदार कवर ड्राइव लगाए जिसमें मारुफा अख्तर की गेंद पर खेला गया शॉट दिलकश था। उन्होंने जहांआरा के खिलाफ डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का भी जड़ा। भारत की जीत पर लगभग उसी समय मुहर लग गई थी जब गेंदबाजों ने बांग्लादेश को महज 80 रन पर रोक दिया था। प्लेयर ऑफ द मैच रेणुका को स्पिनर राधा यादव (14 रन पर तीन विकेट) का शानदार साथ मिला। रेणुका ने पारी की शुरुआत में लगातार चार ओवर (शेष पेज 9)

असम के मोइदम को यूनेस्को का विश्व धरोहर टैग

अर्चना ज्योति। नई दिल्ली

असम के ऐतिहासिक खजाने चराइदेव मोइदाम शाही दफन परिसर और लगभग 600 वर्षों तक पूर्वोत्तर राज्य पर शासन करने वाले अहोम राजवंश द्वारा निर्मित मंदिरों को प्रतिष्ठित यूनेस्को टैग प्राप्त हुआ है, जो इस सम्मान को प्राप्त करने वाला क्षेत्र का पहला सांस्कृतिक स्थल है। इसकी घोषणा भारत में 46वें विश्व धरोहर समिति सत्र के दौरान की गई। इस अतिरिक्त के साथ, भारत अब गर्व के साथ 43 विश्व धरोहर स्थलों की मेजबानी करता है। असम के चराइदेव जिले में मोइदाम अपनी आकर्षक पिरामिड जैसी संरचनाओं के साथ राज्य के शाही अतीत को दर्शाता है, और साथ ही ताई-अहोम राजवंश के इतिहास, वास्तुकला और लोककथाओं का एक आकर्षक मिश्रण पेश करता है। यूनेस्को टैग

ताई-अहोम राजवंश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक योगदान की वैश्विक सराहना को उजागर करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोइदम्स के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक मूल्य पर प्रकाश डालते हुए, शामिल किए जाने पर गर्व और खुशी व्यक्त की। जबकि केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फैसले को स्वर्णिम अक्षरों में अंकित दिन कहा।

मोइदम्स को वर्ष 2023-24 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए भारत के नामांकन के रूप में प्रस्तुत किया गया था। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, चराइदेव में मोइदाम गौरवशाली अहोम संस्कृति को प्रदर्शित करता है, जो पूर्वजों के प्रति अत्यधिक श्रद्धा रखता है। मुझे उम्मीद है कि अधिक लोग महान अहोम शासन और संस्कृति के बारे में सीखेंगे। खुशी है कि मोइदाम विश्व विरासत सूची में शामिल हो गया है। मोइदम एक टीला दफन प्रणाली है जो अहोम राजाओं और रानियों के लिए विश्राम स्थल के रूप में कार्य करती थी। इनका निर्माण ईंटों, पत्थर या मिट्टी से बनी खोखली तिजोरी के ऊपर मिट्टी का आवरण प्रदान करके किया गया था।विश्व धरोहर समिति के सलाहकार निकाय, आईसीओएमओएस के एक प्रवक्ता ने कहा, निर्दिष्ट साइट में विभिन्न आकारों के 90 मोइदाम हैं, जो 600 वर्षों की अवधि में बनाए गए थे, और इसमें औपचारिक रास्ते और पानी की निकासी जैसी अन्य सांस्कृतिक विशेषताएं शामिल हैं। रिपोर्टों में कहा गया है कि वास्तव में 150 से अधिक मोइदाम हैं, (शेष पेज 9)

सांसदों, विधायकों से मिले मुख्यमंत्री

तैयार होगी क्षेत्रीय विकास की कार्ययोजना

● अपने-अपने क्षेत्र में हो रही दिक्कतों और जनता की अपेक्षाओं को जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष किया प्रस्तुत

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी 18 मंडलों के जनप्रतिनिधियों संग लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों को लेकर विस्तार से समीक्षा बैठक पूरी कर ली है। तकरीबन 20 दिन तक चली मंडलवार बैठकों में सांसदगण, विधायकगण और एमएलसी सीएम के समक्ष अपने क्षेत्र की समस्याओं और जन अपेक्षाओं को लेकर उपस्थित हुए। वहीं मुख्यमंत्री ने भी सभी जनप्रतिनिधियों को धैयपूर्वक सुनते हुए तथा उनकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय विकास की नई रणनीति तैयार की जाए। 7 जुलाई को देवीपाटन और अयोध्या मंडल से शुरू हुई मंडलवार समीक्षा बैठक शुक्रवार को लखनऊ मंडल के साथ समाप्त हो गई है।

मंडलवार बैठक में पहुंचने वाले जनप्रतिनिधिगणों ने खुलकर अपनी बात कही है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी विस्तार से भी की बातों को सुनने के बाद आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जीत का मंत्र भी दिया। सीएम योगी ने संवाद, सक्रियता और सोशल मीडिया पर सर्वाधिक फोकस करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि सभी जनप्रतिनिधिगण अपने अपने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों को जनता तक जरूर पहुंचाएं। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क लगातार बनाए रखें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि विपक्ष की ओर से सोशल मीडिया के जरिए फैलाए जा रहे अफवाहों और सामाजिक ताने-बाने को नष्ट करने के प्रयास का मुखर होकर विरोध करें। सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए विपक्ष के हर झूठ को बेनकाब करें और जनता के बीच सच लेकर जाएं।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र में युवाओं और महिला संगठनों से संपर्क और संवाद स्थापित करें। युवाओं को बताएं कि बिना किसी रिश्वत और जाति, मत, मजहब के भेद के निष्पक्ष तरीके से सरकारी नौकरियां प्रदान की जा रही है। ऐसे युवाओं से संपर्क स्थापित करें जिन्हें बिना भेदभाव और रिश्वत के नौकरियां मिली हैं। इसके साथ ही अपने अपने क्षेत्र के खिलाड़ियों से भी लगातार संपर्क बनाए रखें।

मुख्यमंत्री ने इसके अलावा सभी जनप्रतिनिधियों को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से जुटने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा है इस लोकसभा चुनाव में आपके क्षेत्र में हुए मतदान का बारीकी से एनालिसिस करें और इसी के आधार पर अपनी कार्ययोजना तैयार करें। सीएम योगी ने सभी जनप्रतिनिधियों को यह भी कहा कि शासन के लोककल्याणकारी कार्यों को धरातल पर उतारने में कोई भी अधिकारी हीलाहवाली करे तो उसकी लिखित शिकायत करें, कार्रवाई निश्चित की जाएगी।

पूर्व विधायक इंदल रावत को न्यायिक हिरासत में भेजा जेल

विधि संवाददाता। लखनऊ

धोखाधड़ी एवं ढाई करोड़ की ठगी के एक मामले में एमपीएमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पूर्व विधायक एवं कांग्रेसी नेता इंदल रावत को सात अगस्त तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

विशेष अदालत के समक्ष इंदल रावत को पुलिस की भारी सुरक्षा में पेश किया गया था। इसके बाद इंदल रावत की ओर से कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई। इस पर अभियोजन की ओर से बहस के लिए समय की मांग की गई। साथ ही इंदल का आपराधिक इतिहास मंगाए जाने का भी अनुरोध किया गया। विशेष कोर्ट ने अपराधिक इतिहास तलब करने का आदेश देते हुए यह भी कहा कि जमानत प्रार्थना पत्र को नियमित अदालत के पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश किया जाए। इंदल रावत के विरुद्ध राज इंफ्रा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राजेश पांडेय के पक्ष में फर्जी दस्तावेज तैयार कर रजिस्ट्री कराने एवं दो करोड़ 52 लाख रूपए हड़पने का आरोप है। इस मामले में राजेश पांडेय की अर्जी पर विशेष कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश थाना गोमती नगर पुलिस को दिया था।

बैंक ऑफ इण्डिया Bank of India BOI

अधिग्रहण सूचना

यद्यपि प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (12) और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की सपठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना जारी की गई थी तथा ऋणी की माँग सूचना में उल्लेखित धनराशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है, भुगतान सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया था। ऋणी के द्वारा यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी और सर्वसाधारण को एतत्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त एक्ट की धारा 13 (4) सपठित उप नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्तियों का सांकेतिक आधिपत्य ग्रहण कर लिया गया है। ऋणी को विशिष्ट रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से एतत्द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार (क्रय-विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और निम्नलिखित सम्पत्ति का किसी प्रकार से कोई क्रय-विक्रय बैंक ऑफ इण्डिया सूरतगंज के पक्ष में देय बकाया राशि, ब्याज एवं अन्य व्यय के भार के अधीन होगा। ऋणी को सुरक्षित परिसम्पत्ति के आधार पर धारा 13 के उपधारा (8) के प्रावधान के अन्तर्गत दिये गये समय में आमंत्रित कर रहे हैं।

क सं	उधारकर्ता/जमानतकर्ता का नाम एवं पता	बंधक अचल सम्पति का विवरण/ सम्पत्ति मालिक का नाम	बकाया धनराशि (रू.) धारा 13 (2) के अनुसार मांग सूचना/अधिग्रहण की तिथि शाखा
	सूरतगंज शाखा		
1.	श्री शिव ओम मिश्रा पुत्र राज कुमार मिश्रा और श्री हरी ओम मिश्रा पुत्र राज कुमार मिश्रा	संपत्ति का वह सारा हिस्सा और पार्सल जिसमें भूमि और भवन शामिल है, जिसका क्षेत्रफल 0.0885 हेक्टेयर है, जो गांव बरैया, परगना और तहसील रामनगर, जिला बाराबंकी में खसरा नंबर 372 मिनट पर स्थित है। घिरा हुआ उत्तर में खड़ंजा द्वारा दक्षिण में राम सिंह के खेत द्वारा पूर्व में बिटाना पश्चिम में दुर्गा दयाल के खेत द्वारा	रु. 8,94,620.64/- + ब्याज एवं अन्य खर्चे मांग सूचना दिनांक. 13.05.2024 कब्जा नोटिस दिनांकः 23.07.2024

दिनांकः 27.07.2024 स्थानःसूरतगंज प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इण्डिया

सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है समाजवादी पार्टीः अखिलेश

● आरक्षण अधिकार दिवस पर सपा अध्यक्ष ने पार्टी मुख्यालय में स्थापित किया 'संविधान मान स्तम्भ'

पायनियर समाचर सेवा। लखनऊ

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को 'आरक्षण अधिकार दिवस' के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय लखनऊ में एक सादगीपूर्ण कार्यक्रम में 'संविधान मान स्तम्भ' की स्थापना की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के सभी जिला एवं महानगर कार्यालयों में भी आज संविधान मान स्तम्भ की स्थापना के कार्यक्रम होंगे।

संविधान मान स्तम्भ का अनावरण करने के पश्चात् अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान मान स्तम्भ में स्थापित भारत का संविधान पीडीए प्रकाश स्तम्भ के रूप में हमारे लिए सदैव सामाजिक न्याय का मार्ग प्रकाशित और प्रशस्त करता रहेगा। यादव ने इस अवसर पर कहा कि समाजवाद का नाम इकलौती समाजवादी पार्टी में जुड़ा है। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। उन्होंने आज के दिन कारगिल के शहीदों का भी स्मरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण अधिकार दिवस को समाजवादी पार्टी ने संविधान मान स्तम्भ के स्थापना दिवस के रूप में मनाने का विनम्र निर्णय लिया है क्योंकि 26 जुलाई सन् 1902 को महात्मा ज्योतिराव फुले जी द्वारा संकल्पित आरक्षण को कोल्हापुर के श्रीमंत महाराज राजर्षि छत्रपति साहूजी महाराज ने अपने राज्य में लागू करके आरक्षण का शुभारम्भ किया था। उनका उद्देश्य सभी को संख्या के अनुपात में आरक्षण देना था। यादव ने कहा कि सामाजिक न्याय की भावना को आरक्षण के रूप में इसी दिन अमल में लाया गया था जो आगे चलकर बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सद्प्रयासों से हमारे संविधान में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने का मूल आधार बना और देश के लोकतंत्र की स्थापना का मूल सिद्धांत बना। उनका उद्देश्य हजारों सालों से प्रतिनिधित्व वंचित लोगों को राजनीतिक जमात बनाने हेतु उनमें से ही प्रशासक वर्ग निर्माण करना था। आज भाजपा सरकार निजीकरण करके, नौकरियों में आरक्षण का अमल न करके इसे समाप्त कर रही है। यह सरकार युवाओं को नौकरियां भी सिर्फ इसलिए नहीं दे रही है जिससे कहीं आरक्षण न देना पड़ जाए और दलित, पिछड़े, वंचितों को उनका हक न मिल पाए। समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। पार्टी का मानना है कि जाति के आधार पर जनगणना हो ताकि समानुपातिक आधार पर सबको सम्मान और हक हासिल हो सके। डॉ. राममनोहर लोहिया ने सबके विकास के लिए पिछड़ों को विशेष अवसर दिए जाने की मांग उठाई थी। संविधान और आरक्षण खत्म करने का खतरा अभी टला नहीं है। जनता के संकल्पित प्रयास से संविधान विरोधियों को मात देने का सिलसिला रूकने वाला नहीं। हम सब लामबंद होकर नफरत का खेल खेलने वालों को सफल नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का वैचारिक संघर्ष जारी रहेगा।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने शहीद मनोज पांडेय के आवास पर जाकर जाना उनके पिता का कुशलक्षेम

पायनियर समाचर सेवा। लखनऊ

कारगिल युद्ध के 25 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कारगिल युद्ध के नायक परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन मनोज पाण्डेय के आवास पर जाकर उनके पिता से मिलकर उनका कुशलक्षेम जाना तथा उन्हें अंगवस्त्र देकर आर्शीवाद लिया। राय ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास शहादत का रहा है और हम शहादत का मोल समझते हैं। कारगिल विजय के 25 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस पार्टी उन सभी शहीदों को नमन करती है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिये। उनकी शहादत से सुरक्षित हैं इस देश की सीमाएं, सुरक्षित हैं हम। आज कांग्रेस पार्टी कारगिल युद्ध के सभी शहीदों को नमन करती है और उस युद्ध के शूरवीर शहीद कैप्टन मनोज पाण्डेय के घर जाकर उन सभी शहीदों की शहादत को याद करते हुए भारतीय सेना के जज्बे को सलाम करती है।

इंडियन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) Indian Bank (A Govt. of India Undertaking)
इलाहाबाद ALLAHABAD

कब्जा नोटिस (अचल सम्पत्ति हेतु)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन)अधिनियम 2002 के नियम–8(1) के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **इंडियन बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002, (धारा 54, 2002) की धारा 13 (12) प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (प्रवर्तन) की सपठित नियम 3, 8 व 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋणी को मांग सूचना पत्र से यहाँ विस्तृत रूप से नीचे दी गयी राशि 60 दिनों के भीतर लौटाने के लिए निर्गमित किया।

ऋण–ग्रहिता / जमानतकर्ता के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋण–ग्रहिता / जमानतकर्ता और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है की अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) सपठित उक्त नियम के नियम 8 व 9 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में निम्नलिखित सम्पत्तियों का आधिपत्य ग्रहण कर लिया गया है। ऋण–ग्रहिता / जमानतकर्ता को विशिष्ट रूप से और सर्व–साधारण को सामान्य रूप से एतद्द्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार (क्रय–विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त संपत्ति का किसी भी प्रकार से क्रय–विक्रय **इंडियन बैंक** के अधीन रहेगा।

उधारकर्ता / जमानतकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

यह सूचना इस अधिग्रहण के आयोजन के सम्बन्ध में कर्जदारों, जमानतकर्ताओं और बंधककर्ताओं को बकाया जमा करने के लिए कहा जा रहा है।

विवरण निम्नुसार हैं:–

क्र. सं.	ऋणी / प्रोपराइटर / जमानतकर्ता / बंधककर्ता का नाम एवं पता	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि / कब्जा की तिथि / बकाया धनराशि
	शाखाः FODS		
1.	1. मेसर्स श्री सिद्ध विनायक पिंडी इंटरप्राइजेज प्रोपराइटर श्रीमती गिरजा त्रिपाठी (ऋणी), कार्यालय का पताः एसएस–123, सेक्टर ई, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ 2. मेसर्स श्री सिद्ध विनायक पिंडी इंटरप्राइजेज प्रोपराइटर श्रीमती गिरजा त्रिपाठी (ऋणी / जमानतकर्ता), आवासीय पताः एसएस–123, सेक्टर ई, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ 3. श्रीमती चंद्रावती तिवारी पत्नी स्व0 श्री कृष्ण कुमार तिवारी (जमानतकर्ता / बंधककर्ता), पताः एसएस–123, सेक्टर ई, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ	मकान स्थित एसएस–123, सेक्टर ई, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, मालिकः श्रीमती चंद्रावती तिवारी, संपत्ति का क्षेत्रफलः 416.41 वर्ग फीट चौहद्दीः उत्तरः मकान सं. एसएस–122, दक्षिणः 20 फीट चौड़ी सड़क, पूर्वः मकान सं. एसएस–124, पश्चिमः 20 फीट चौड़ी सड़क	09.11.2022 22.07.2024 रु. 12,68,119.00 एवं उसपर ब्याज

दिनांकः 27.07.2024 स्थानः लखनऊ प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

अचानक गाड़ी रुकवाकर मोची से मिले राहुल गांधी, बगल में बैठकर जाना हाल

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को सुलतानपुर जिले में लंबित कानूनी मामले में तारीख पर पहुंचे। इस मौके पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश अविनाश पाण्डेय, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय तथा उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा 'मोना' सहित भारी संख्या में कांग्रेस जन यात्रा में साथ रहे। यात्रा के दौरान राहुल गांधी का रास्ते में कई जगहों पर कांग्रेसजनों तथा सामान्य नागरिकों खासतौर पर युवाओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। न्यायालय में प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद राहुल गांधी ने सुल्तानपुर में लोको पायलट्स से मुलाकात की। नार्दन रेलवे इंप्लाइज यूनियन इकाई सुल्तानपुर लोको पायलट का एक प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी से मिला और अपनी मांगों को एक पत्र सौंपते हुए अपनी समस्याओं को वर्तमान सरकार के समक्ष रख उनके निराकरण कराने हेतु निवेदन किया। तदोपरान्त राहुल गांधी ने रास्ते में गाड़ी रुकवाकर मोची का काम करने वाले परिवार से लगभग आधे घंटे की मुलाकात कर उनकी रोजमर्रा की समस्याओं को समझने का प्रयास किया। राहुल गांधी ने मोची परिजनों से कहा कि हम मेहनतकश लोगों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सड़क से संसद तक आपकी आवाज उठा रहे हैं।

जातिगत जनगणना कराने व आरक्षण के मुद्दे पर 10 लाख हस्ताक्षर इकट्ठा करेगी कांग्रेस

● राष्ट्रीय भागीदारी सम्मेलन में कांग्रेस ने बुलंद की आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की पाबंदी हटाने की मांग

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

जातिगत जनगणना कराने और आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत की पाबंदी हटाने की मांग को लेकर अल्पसंख्यक कांग्रेस, ओबीसी कांग्रेस और फिशरमैन कांग्रेस प्रदेश भर से 10 लाख हस्ताक्षर इकट्ठा करेगा। यह अभियान मण्डल आयोग की रिपोर्ट के लागू किये जाने के वर्षगांठ 7 अगस्त तक चलेगा। यह निर्णय शुक्रवार को प्रदेश कार्यालय पर छत्रपति साहू जी महाराज द्वारा 26 जुलाई 1902 में कोल्हापुर रियासत में लागू किये गए 50 प्रतिशत आरक्षण के वर्षगांठ पर आयोजित राष्ट्रीय भागीदारी सम्मेलन में किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने सामाजिक न्याय की जो आवाज बुलन्द की है उसे उत्तर प्रदेश में मजबूती से उठाया जाएगा। अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने कहा कि भाजपा के अंदर जो अगड़ों और पिछड़ों के नाम पर उठा पटक का नाटक हो रहा है वो सिर्फ़ पिछड़ों के कांग्रेस की तरफ उम्मीद से देखने से हुई है।

शुभम्
शुभम् हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कं. लि.
कॉर्पोरेट कार्यालयः 425, उद्योग विहार फेज IV, गुड़गांव–122015 (हरियाणा)
फोनः 0124-4212530/31/32, ई–मेलः customercare@shubham.co वेबसाइटः www.shubham.co

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित
प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत नोटिस (इसके बाद इसे "अधिनियम" कहा गया)

इस नोटिस के द्वारा आपके ध्यान में लाया जाता है कि आपका ऋण खाता सुरक्षित ऋणदाता शुभम् हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 608 - 609, 6 वीं मंजिल, ब्लॉक-सी अंसल इंपीरियल टॉवर, कम्युनिटी सेन्टर, नारायणा विहार, नई दिल्ली-110028 (इसके बाद इसे 'एसएचडीएफसीएल' कहा गया है) के द्वारा एनपीए घोषित कर दिया गया और आप एसएचडीएफसीएल को अपने ऋण के विरुद्ध कुल बकाया का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। आप आकस्मिक खर्चों, लागत, शुल्कों आदि के साथ उपरोक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी हैं, इसलिए, हम आपसे इस नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर एसएचडीएफसीएल के प्रति अपनी पूरी देनदारियों का निर्वहन करने का आह्वान करते हैं, ऐसा न करने पर एसएचडीएफसीएल को अधिनियम की धारा 13(4) के तहत शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार होगा। **उधारकर्ताओं और सुरक्षित आस्तियां का विवरण इस प्रकार है:**

क्र. सं.	ऋण खाता नं. (कर्जदार का नाम)	आवेदक का पता	मांग सूचना की तिथि और राशि	सुरक्षित आस्तियां
1.	0LKW1907000005021807, पंकज कुमार अग्रहरि, दीक्षा	मकान नं. 58/245 राम मंदिर लेन, हुसैन गंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226001	रु. 5,61,473/- & 20/07/2024	मकान सं. (सी), खसरा सं. 153 और 155 पर निर्मित, रीमनगर दुदौली प्लॉट सं. 68 और 69 फैजुल्लागंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001 में स्थित
2.	0LKO2204000005046299, रवि प्रकाश मिश्रा, काजल तिवारी	मुक्कम खिजराबाद, पोस्ट बरवारी पुर, खिजरा बाद प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश-228145	रु.13,80,762/- & 20/07/2024	प्लॉट संख्या 08 का हिस्सा, गाटा सं. 271मिन, ग्राम रसूलपुर, कायस्थ, परगना-महोना, बीकेटी जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226021 में स्थित
3.	0GKP2301000005056924, & 0GKP2307000005066900, संतोष कुमार, सोनम	डुमरी खास, डुमरी शिव मंदिर के पास, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273202	रु.13,41,420/- & रु. 8,17,665/- & 20/07/2024	आराजी सं. 3670, मौजा-डुमरी खास टप्पा केवटली, परगना हवेली, तहसील चौरी चौरा एवं जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273202 में स्थित
4.	0VRN2202000005044283, शिव कुमार, अर्चना मौर्य	N10/39 A-1-K-J, लखराव बजरडीहा केवी होटल लखराव, वाराणसी उत्तर प्रदेश - 221109	रु. 9,11,260/- & 20/07/2024	मकान सं. एन 10/39- ए-1-के-जे, आराजी सं. 435 मौजा लखराव, ककरमत्ता, वार्ड-नगावा, परगना-देहात अमानत, तहसील-सदर वाराणसी उत्तर प्रदेश-221106
5.	0ALB2308000005068146, मो अखलाक, शाइस्ता परवीना	92, चकदोंदी नैनी बीड़ी कारखाना के पास, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश-211008	रु. 4,88,804/- & 20/07/2024	प्लॉट आराजी 75 का भाग, मौजा इरादतगंज परगना अरैल, तहसील बारा, जिला प्रयागराज, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश-212111
6.	0ALB1906000005020571, शैलेश कुमार वर्मा, संजू देवी वर्मा	122/93, मलाका राज बैरहना शिव पार्क इलाहाबाद उत्तर प्रदेश-211003	रु. 3,37,407/- & 20/07/2024	मकान नं. 122/93, मलाकराज परगना और तहसील सदर, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश - 211003
7.	0LKO2007000005028697, सीमा अग्रवाल, मानस अग्रवाल, आशीष अग्रवाल	फ्लैट नं. 117 चौथी मंजिल एसएम अपार्टमेंट न्यू मानस ग्रेन मार्केट हनुमान मंदिर के पास, गणेशगंज लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226018	रु.18,57,078/- & 20/07/2024	फ्लैट नं. ई-117, संपत्ति सं. 96/88 पर, चौथी मंजिल पर पुराना नं. 96/76 एस.एम अपार्टमेंट जोकि ग्रेन मार्केट, ओल्ड गणेशगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश -226001 में स्थित

स्थानः गुड़गाँव,
तिथिः 26.07.2024
प्राधिकत अधिकारी,
शुभम् हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लि.

पायनियर वर्गीकृत

सूचना

मै माता प्रसाद यादव पुत्र श्री खुशीराम यादव निवासी 587/156, गॉधीनगर,तेलीबाग लखनऊ शपथ पूर्वक यह सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार योजित सिंह यादव जन्म तिथि 29 नवम्बर 2009 है। कतिपय जगह पर मेरे पुत्र का नाम योजित यादव अंकित है। मेरे पुत्र को भविष्य में योजित सिंह यादव के नाम से ही जाना पहचाना जाए।
माता प्रसाद यादव

आवश्यकता है

विशेश्वर दयाल महाविद्यालय
कोन्सर चौराहा, बिसवां, सीतापुर–261201
आवश्यकता
बी.ए. (चित्रकला एवं भूगोल)
एम.ए. (गृहविज्ञान एवं शिक्षाशास्त्र)
विषय हेतु शिक्षक की।
योग्यता एवं वेतनमानः यूजीसी/राज्य सरकार/लखनऊ विश्वविद्यालय के मानकानुसार। इच्छुक अभ्यर्थी अपना बायोडाटा, शैक्षिक प्रमाणपत्र एवं नवीनतम 4 फोटोग्राफ महाविद्यालय के पते पर रजिस्टर डाक द्वारा अविलम्ब 15 दिनों के अन्दर भेज सकते है।
प्रबन्धक–7084852752

इंग्लैंड और अमेरिका भी चखेगा कालानमक चावल का स्वाद

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

● सात दशक बाद इंग्लैंड व पहली बार अमेरिका जाएगा कालानमक

अब इंग्लैंड और अमेरिका भी चखेगा कालानमक चावल का स्वाद। करीब सात दशक बाद इंग्लैंड और पहली बार अमेरिका जाएगा कालानमक चावल। इसके पहले नेपाल, सिंगापुर, जर्मनी, दुबई आदि देशों को भी कालानमक चावल का निर्यात किया जा चुका है।

इंग्लैंड तो कालानमक के स्वाद और सुगंध का मुरीद रह चुका है। बात करीब सात दशक पुरानी है। तब गुलाम भारत में देश भर में अंग्रेजों के बड़े बड़े फॉर्म हाउस हुआ करते थे। ये इतने बड़े होते थे कि इनके नाम से उस क्षेत्र की पहचान जुड़ जाती थी। मसलन बर्डघाट, कैंपियरगंज आदि। सिद्धार्थनगर भी इसका अपवाद नहीं था। उस समय सिद्धार्थ नगर में अंग्रेजों के फार्म हाउसेज में कालानमक धान की बड़े पैमाने पर खेती होती थी। अंग्रेज कालानमक के स्वाद और सुगंध से वाकिफ थे। इन खूबियों के कारण इंग्लैंड में कालानमक के दाम भी अच्छे मिल जाते थे। तब जहाज के जहाज चावल इंग्लैंड को जाते थे। करीब सात दशक पहले जमींदारी उन्मूलन के बाद यह सिलसिला क्रमशः कम होता गया। और आजादी मिलने के बाद खत्म हो गया। इस साल पहली बार इंग्लैंड को 5 कुंतल चावल निर्यात किया जाएगा। इसी क्रम में पहली बार अमेरिका को भी 5 कुंतल चावल का निर्यात होगा। उल्लेखनीय है कि जबसे योगी सरकार ने कालानमक धान को सिद्धार्थ नगर का एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) घोषित किया है तबसे देश और दुनियां में स्वाद, सुगंध में बेमिसाल और पौष्टिकता में परंपरागत चावलों से बेहतर कालानमक धान के चावल का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। जीआई मिलने से इसका दायरा भी बढ़ा है। योगी सरकार ने इसे सिद्धार्थनगर का एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी घोषित करने के साथ इसकी खूबियों की जबरदस्त ब्रांडिग भी की। इसीके इसके रकबे उपज और मांग में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई। राज्यसभा में 17 दिसंबर 2021 को दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2019/2020 में इसका निर्यात 2 फीसद था। अगले साल यह बढ़कर 4 फीसद हो गया। 2021/2022 में यह 7 फीसद रहा। कालानमक धान को केंद्र में रखकर पिछले दो दशक से काम कर रही गोरखपुर की संस्था पीआरडीएफ (पार्टिसिपेटरी रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन) के चेयरमैन पदमश्री डा आरसी चौधरी के अनुसार पिछले दो वर्षो के दौरान उनकी संस्था ने सिंगापुर को 55 टन और नेपाल को 10 टन कालानमक चावल का निर्यात किया। इन दोनों देशों से अब भी लगातार मांग आ रही है। इसके अलावा कुछ मात्रा में दुबई और जर्मनी को भी इसका निर्यात हुआ है। पीआरडीएफ के अलावा भी कई संस्थाएं कालानमक चावल के निर्यात में लगीं हैं।डॉक्टर चौधरी के अनुसार निर्यात का प्लेटफार्म बन चुका है। आने वाले समय में यह और बढ़ेगा।

दुनियां का एक मात्र प्राकृतिक चावल जिसमें वीटा कैरोटिन के रूप में विटामिन ए उपलब्ध है। अन्य चावलो की तुलना में इसमें प्रोटीन और जिंक की मात्रा अधिक होती है। जिंक दिमाग के लिए और प्रोटीन हर उम्र में शरीर के विकास के लिए जरूरी होता है। इसका ग्लाईसेमिक इंडेक्स कम (49 से 52 प्रतिशत) होता है। इस तरह यह शुगर के रोगियों के लिए भी बाकी चावलों की अपेक्षा बेहतर है।

Bandhan Bank
रीजनल ऑफिसः नेताजी मार्ग, मीठाखली छः रास्ते के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-06. फोन : +91-79-26421671-75

सांकेतिक आधिपत्य (कब्जा) सूचना

एतदर्थ सूचना दी जाती है कि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पूर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित प्रर्वतन अधिनियम, 2002 कि धारा 13(12) एवं प्रतिभूतिहित प्रर्वतन नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढते हुए अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत प्राधिकृत अधिकारी ने खाते(अकाउंट) के सामने उल्लेखित तिथि को डिमांड नोटिस (मांग पत्र) भेजा था व नोटिस प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर राशि की मांग की गई थी। ऋणी द्वारा भुगतान करने में असफल रहने पर कर्जदार और आम जनता को नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है की अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त अधिनियम कि धारा 13 की उपधारा(4) सपठित नियम 8 के तहत नीचे लिखे लोन खातों में वर्णित बंधक सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है। अतः आप कर्जदार और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संपत्तियों के बारे में कोई व्यवहार न करें और इन संपत्तियों के साथ किसी व्यवहार पर वह राशि, ब्याज, खर्च एवं शुल्क के साथ बैंक को चुकाना होगा। सुरक्षित सम्पत्ति को रिडीम/वापस लेने के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) में उपलब्ध प्रावधानों के तहत ऋणियों का ध्यान आमंत्रित किया जाता है।

ऋणियों के नाम, गारंटर और ऋण खाता सं.	बंधक संपत्ति का विवरण (प्रतिभूती आस्तियां)	मांगपत्र की तिथि	सांकेतिक कब्जे की तिथि	कुल बकाया राशि, मांगपत्र की तारीख तक
श्री अरुण जैकोब फिलिप्स श्रीमती मोहिनी फिलिप्स 20007590000220	सभी अचल संपत्ति जो मकान नंबर 358, मौजा–बशरतपुर, हवेली परगना, तहसील सदर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश– 273004 पर स्थित है और जो आवरित हैः उत्तरः नरेश फिलिप्स का घर, पूर्वः सड़क 7 फीट, पश्चिमः सड़क 10 फीट, दक्षिणः सड़क 25 फीट	18.01.2024	23.07.2024	रू.19,31,291.41

स्थानः गोरखपुर
तारीखः 27/07/2024
प्राधिकृत अधिकारी
बंधन बैंक लिमिटेड

भारत की पहचान जबरन एकाधिकार करने वाले देश की नहीं

कारगिल विजय दिवस

कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित 'रजत जयंती समारोह' में शामिल हुए मुख्यमंत्री

● कहा, कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय जवानों के अदम्य शौर्य व साहस का लोहा दुनिया ने माना

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कारगिल युद्ध भारत पर थोपा गया था। छद्म रुप से पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ करके भारत पर युद्ध थोपने का कार्य किया था। किन्तु युद्ध का परिणाम क्या होगा यह हमारे बहादुर जवानों ने तय किया। उस समय हमारी सेना के वीर जवानों के सामने विपरीत परिस्थितियां थीं, लेकिन हमारे बहादुर जवानों के सामने कोई दुश्मन टिक नहीं पाया। उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय जवानों के अदम्य शौर्य और साहस का लोहा दुनिया ने माना।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को सेंट्रल कमांड, कैंट के सूर्या सभागार में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित रजत जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कारगिल विजय दिवस की बधाई देते हुए कहा कि जिन वीर नारियों और परिवारों ने कारगिल युद्ध में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, आज उन्हें सम्मानित कर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सीएम योगी ने कहा कि दुनिया के अंदर भारत की पहचान जबरन एकाधिकार करने वाले देश की नहीं है।

सीएम योगी ने कहा कि शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्रचिंता प्रवृत्तते यह भारत की परंपरा है। उन्होंने कहा कि बल, बुद्धि और विद्या में भारत जब दुनिया के अंदर जब सिरमौर था, तब भी हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया। परंतु किसी आक्रांता ने यहां आकर हमारी शांति और हमारी सद्भावना के हनन का दुस्साहस किया तो भारत माता के बहादुर जवानों ने मातृभूमि के रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि देश की सीमा की रक्षा करने वाले बहादुर जवानों के साथ राज्य सरकार हमेशा खड़ी है।

सीएम योगी ने कहा कि हमारा जवान किसी भी युद्ध या सीमा की सुरक्षा करते हुए शहीद होता है, तो राज्य सरकार की ओर उसके परिवार को आज 50 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। साथ ही उस परिवार के एक सदस्य की नौकरी भी व्यवस्था सुनिश्चित की है। इसके अलावा 2017 से हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि शहीद होने वाले जवान की स्मृति को आगे बढ़ाने के लिए जिस गांव, नगर, कस्बे का वह जवान होगा, वहां पर एक भव्य स्मारक, इंस्टिट्यूट या किसी मार्ग का नामकरण उस जवान के नाम पर करेंगे। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत के संकल्प को इसलिए ही आगे बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडेय के पिता, राइफलमैन सुनील जंग की माता, नायक आबिद खान की माता, नायक रामकेश चंद्र यादव की पत्नी, नायक राजेंद्र यादव की पत्नी, लांस नायक अशोक कुमार यादव के बेटे, ब्रिगेडियर अखिल कुमार सिन्हा, कर्नल प्रभात रंजन, कर्नल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह कौशिक, कर्नल क्षितिज श्रीवास्तव, नायक जितेंद्र सिंह और सिपाही विनोद कुमार दुबे को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने अमर जवानों को पुष्पचक्र चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। साथ सीएम योगी ने कारगिल युद्ध के दौरान भारत के वीर जवानों के शौर्य को प्रदर्शित करती हुई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया।

अगले तीन वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा: मुख्यमंत्री

● सीएम ने कारगिल स्मृति वाटिका में शहीदों की प्रतिमाओं पर पुष्पचक्र अर्पित किया

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगले तीन वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब है कि भारत समृद्धि के नए सोपान को स्थापित करते हुए आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड पर तेजी के साथ कार्य हो रहा है। यहां पर देश-विदेश की रक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां स्थापित कर रही हैं, जो रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं।

सीएम योगी ने शुक्रवार को कारगिल स्मृति वाटिका में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित रजत जयंती समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1999 में हुआ कारगिल का युद्ध पाकिस्तान ने छद्म तरीके से भारत पर थोपा था, जिसका हमारे बहादुर जवानों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान को चारों खाने चित कर दिया था। उस समय भारत ने कारगिल विजय की घोषणा करके पूरी दुनिया को अपने शौर्य और पराक्रम का लोहा मनवाया था। सीएम योगी ने कहा कि भारत एक शांतिपूर्ण देश है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों एवं आदर्शों में विश्वास करता है। यही वजह है कि भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आजादी के अमृत काल में प्रवेश किया है। इसको देखते हुए हमें विकसित भारत की संकल्पनाओं को पूरा करने के लिए स्व से ऊपर उठकर कार्य करने की आवश्यकता है। मेरा और तेरा के भाव को समाप्त करते हुए हमें राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण है और जब किसी देश में ऐसा वातावरण बनता है तो उस देश की समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त होता है। सीएम योगी देश की सीमा की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की स्मृतियों को नमन करते हुए पूरे प्रदेश को कारगिल विजय दिवस की बधाई दी। कार्यक्रम से पहले सीएम योगी ने कारगिल स्मृति वाटिका में लगाई गई शाहिद मेजर रितेश शर्मा, कैप्टन मनोज पांडेय, कैप्टन मनोज मिश्र, लांस नायक केवड़ा नंद द्विवेदी और राइफलमैन सुनील जंग की प्रतिमाओं पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनकी स्मृतियों को नमन किया।

विधायक बेदीराम व विपुल दूबे समेत 18 अभियुक्तों पर गैंगेस्टर में आरोप तय

विधि संवाददाता। लखनऊ

18 वर्ष पुराने गैंगस्टर के एक मामले में शुक्रवार को विधायक बेदीराम व विपुल दूबे समेत 18 अभियुक्त विशेष अदालत के समक्ष हाजिर हुए। विशेष जज पुष्कर उपाध्याय ने सभी अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 3 (1) के तहत आरोप तय कर दिया। साथ ही अभियोजन को अपना गवाह पेश करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई सात अगस्त को होगी।

गैंगेस्टर का यह मामला रेलवे भर्ती बोर्ड ग्रुप डी की परीक्षा से संबधित प्रश्न पत्र के लीक होने का है। गैंगेस्टर के इस मामले में कुल 19 अभियुक्त थे। 26 फरवरी 2006 को एसटीएफ ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। इस मामले की रिपोर्ट थाना कृष्णानगर में दर्ज हुई थी। आरोपी बेदीराम गाजीपुर की जखनियां जबकि विपुल दूबे भदोही की ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र से विधायक हैं। इससे पूर्व विशेष अदालत के समक्ष कुछ अभियुक्तों की ओर से डिस्चार्ज अर्जी दाखिल करने के लिए समय देने की मांग की गई। जबकि एक अभियुक्त ने आरोप पत्र की नकलें दिलाने की मांग की। विशेष अदालत ने सभी अर्जी खारिज कर दी। कहा कि 13 वर्ष पूर्व ही इस मामले में दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान लिया जा चुका है। अब अभियुक्तगण जानबूझकर इस मामले को और विलंबित करना चाहते हैं। यह भी कहा कि आरोप पत्र की नकलें सभी को मुहैया करा दी गई है। शुक्रवार को विशेष अदालत में विधायक बेदीराम उर्फ बेदीलाल व विपुल दूबे के अलावा अभियुक्त संजय श्रीवास्तव, कृष्णकांत, मनोज कुमार मौर्य, शैलेश कुमार सिंह, रामकृपाल सिंह, भद्रमणि त्रिपाठी, आनंद कुमार सिंह, धमेंद्र कुमार, रमेश चंद्र पटेल, मो. असलम, अवधेश सिंह, सुनील कुमार यादव, अख्तर हुसैन, दीना उर्फ दीनदयाल, शिव बहादुर सिंह व रश्मि चंद्रा हाजिर हुए थे। विशेष अदालत ने इन सभी पर गैंगस्टर एक्ट की धारा 3 (1) के तहत आरोप तय किया। कहा कि वर्ष 2006 से पूर्व अभियुक्तगणों ने लखनऊ शहर में एक संगठित गिरोह बनाया। जिसका उद्देश्य स्वयं तथा अपने गिरोह के अन्य साथियों के लिए आर्थिक व भौतिक लाभ प्राप्त करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने विभिन्न तारीख व समय पर आईपीसी के अध्याय 17 में वर्णित अपराध किए। लिहाजा अभियुक्तों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया उत्तर प्रदेश गिरोह बंद तथा समाज विरोध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम का मामला निर्मित होता है। विशेष अदालत ने एक अभियुक्त कृष्ण कुमार यादव की मौत होने के चलते उसके विरुद्ध मुकदमा समाप्त कर दिया।

संविधान हत्या दिवस' घोषित करने के मामले में हाईकोर्ट का हस्तक्षेप से इंकार

● कहा, राजनीतिक जटिलताओं में नहीं पड़ सकते

विधि संवाददाता। लखनऊ

'**संविधान** हत्या दिवस' की अधिसूचना जारी करने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है। पीठ के समक्ष एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी। पीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह सरकार का विषय है कि वह 25 जून 1975 को लगाए गए आपात काल में हुई ज्यादतियों के सम्बंध में किस प्रकार की घोषणा करती है। हम राजनीतिक जटिलताओं में नहीं पड़ सकते। पीठ ने इन टिप्पणियों के साथ ही याचिका को निस्तारित कर दिया।

जस्टिस संगीता चंद्रा एवम जस्टि श्रीप्रकाश सिंह की पीठ ने यह आदेश पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में संविधान हत्या दिवस शब्द का प्रयोग करने को अविधिक बताया गया था। कहा गया कि हत्या या मृत्यु होने पर अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए सरकार हत्या दिवस के स्थान पर किसी सकारात्मक शब्द का भी प्रयोग कर सकती थी। यह भी दलील दी गई कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपात काल लागू कर तत्कालीन सरकार ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया था। इससे देश के नागरिकों को प्रताड़नाओं का भी सामना करना पड़ा था। लेकिन यदि संविधान की हत्या हो गई होती तो देश की जनता अगले ही आम चुनाव में तत्कालीन सरकार को उखाड़ न फेंकती। इस याचिका का डिप्टी सॉलिसीटर जनरल एसबी पांडेय ने विरोध किया। कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे का ब्यौरा नहीं दिया है। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उसने अपने याचिका में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि सामाजिक कार्य करते हुए उस पर मुकदमे भी दर्ज हुए और उसे जेल भी जाना पड़ा है।

पीठ ने दोनों पक्षों की बहस के उपरांत अपने आदेश में कहा कि हम इस प्रकार की अधिसूचना जारी करने के सम्बंध में सरकार की सोच पर सवाल नहीं कर सकते।

हरे-फलदार पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

विधि संवाददाता। लखनऊ

महमूदाबाद तहसील के मुस्तफाबाद गांव में हो रहे हरे व फलदार पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अंतरिम रोक लगा दी है। पीठ ने इसके साथ ही इस मामले में एसडीएम महमूदाबाद को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश भी दिया है।

मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। जस्टिस संगीता चंद्रा एवम जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की पीठ ने यह आदेश अवधेश कुमार व अन्य ग्रामवासियों की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि गाटा संख्या 23 ग्राम सभा की जमीन है। जो 2.44 हेक्टेयर की है। इस जमीन पर हरे व फलदार वृक्ष लगे हैं। जिन्हें नीलामी करके कटवाया जा रहा है। वहीं इस मामले में महमूदाबाद के तहसीलदार की ओर से भेजी गई जानकारी में कहा गया कि ग्राम प्रधान ने उक्त जमीन पर एक अस्थाई गौशाला का निर्माण कराया है। वो गौशाला के जानवरों के लिए उसी जमीन पर चारा आदि की बुआई करना चाहता है। इसलिए उक्त जमीन पर स्थित पेड़ों की नीलामी कराई गई व उनकी कीमत 82 हजार 530 रुपए रखी गई। पीठ ने इस पर पूछा कि इतने पेड़ों की लागत मात्र 82 हजार 530 रुपए कैसे तय की गई। एसडीएम ने इस नीलामी को मंजूरी देते समय पेड़ों के कटान के लिए क्या वन विभाग से अनुमति ली है। पीठ ने इन सभी बिंदुओं पर जवाब मांगते हुए एसडीएम को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।

लोहिया विधि विश्वविद्यालय में कारगिल विजय दिवस आयोजित

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक समिति की तरफ से शुक्रवार को 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों की वीरता और बलिदान को स्मरण करते हुए काव्य प्रतियोगिता और कैंडल मार्च के साथ कारगिल विजय दिवस का भव्य आयोजन किया। इस कार्यक्रम की विशिष्ट सम्मानित उपस्थिति में पूर्व कर्नल खान महमूद और श्रीमती सैमा अनवर खान शामिल थे। उनका स्वागत प्रो. (डॉ.) अमर पाल सिंह, कुलपति, आरएमएलएनएलयू; कर्नल अग्नि सिंह, मुख्य सुरक्षा अधिकारी; प्रो. (डॉ.) वंदना सिंह, सांस्कृतिक समिति की अध्यक्ष और डॉ. शशांक शेखर, समन्वयक सांस्कृतिक समिति ने किया। काव्य प्रतियोगिता में विजेताओं का चयन करते हुए उन्हें मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वालों में क्रमशः तन्वी राय, अर्चिता गर्ग और वनीषा भंडारी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहीं। कार्यक्रम का समापन एक भावपूर्ण कैंडल मार्च के साथ हुआ, जिसमें छात्रों ने कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

345 घरों के सर्वे में डायरिया के चार मरीज मिले

लखनऊ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, लखनऊ के निर्देशानुसार डा गोपीलाल, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी एवं डा निशान्त निर्वाण, उप मुख्य चिकित्साधिकारी तथा अधीक्षक, नग. सामु. स्वा. केन्द्र इन्दिरानगर एवं उनकी चिकित्सीय टीम द्वारा शुक्रवार को मायावती कालोनी तकरोही 345 घरों का सर्वेक्षण कर 1580 लोगो की स्क्रीनिंग की गयी। जिसमें 4 हल्के दस्त एवं पेट दर्द के मरीज पाये गये। जिन्हें चिकित्सीय टीम द्वारा जिंक टैबलेट, ओआरएस पैकेट देकर उपचारित किया गया। नगरीय सामु. स्वा. केन्द्र इन्दिरानगर की चिकित्सीय टीम द्वारा क्षेत्र में चिकित्सा शिविर लगाकर 174 लोगो को स्वास्थ्य सेवायें प्रदान की गयी तथा लोगो को रोगो की रोकथाम हेतु सावधानिया बरतने हेतु जागरूक किया जा रहा है। कैम्प में कोई गंभीर रोगी नही पाया गया। क्षेत्र में एक 108 रोगी वाहन एवं नग. सामु. स्वा. केन्द्र की चिकित्सकीय टीम की तैनाती करते हुए 24 घंटे चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने एवं सतत निगरानी रखने हेतु निर्देशित किया गया।

एलयू में प्रबन्ध अध्ययन संकाय बनाने की मंजूरी, शासन से मिली एनओसी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास रहा। विवि स्तर पर संचालित प्रबन्धन से जुड़े कोर्सों को देखते हुए संकाय बनाने के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस बावत शासन स्तर पर विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने एनओसी जारी कर दी है। अभी तक व्यापार प्रशासन विभाग का संचालन वाणिज्य संकाय के अंतर्गत हो रहा था। इसी के साथ यह लखनऊ विश्वविद्यालय का 12वाँ संकाय बन गया है।

इस अवसर पर कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय प्रो आलोक कुमार राय ने कहा कि कि मैं इसे लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए एक ऐतिहासिक दिन मानता हूं। व्यापार प्रशासन विभाग में उत्कृष्ट और अपने विधा में अग्रणी शिक्षक रहे हैं और यह विभाग अपने पूर्व छात्रों के रूप में उत्कृष्ट पेशेवरों वाला एक पुराना विभाग रहा है। प्रबंधन शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा से आगे बढ़ गई है। इसलिए प्रबंधन संकाय के एक अलग संकाय की स्थापना न केवल प्रबंधन समुदाय में छात्रों की अधिक ग्रहणशीलता को मजबूत कर रही है, बल्कि विश्वविद्यालय में चल रहे विभिन्न प्रबंधन कार्यक्रमों को समेकित (एकीकृत) करने में भी मदद करेगी। बता दें कि एलयू में कुल 22,000 छात्रों में से 2200 से अधिक छात्र विभिन्न प्रबंधन कार्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं,जो विश्वविद्यालय के कुल छात्र संख्या का लगभग 10फीसद है।

आरोपी को 10 वर्ष की सजा

विधि संवाददाता। लखनऊ

छह वर्ष की बच्ची से दुराचार का प्रयास करने के मामले में दोषी करार दिए गए अभियुक्त भानु प्रताप को पॉक्सो की विशेष अदालत ने 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष जज विजेन्द्र त्रिपाठी ने इस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 25 अगस्त 2022 को इस मामले की एफआईआर पीड़िता के पिता ने थाना कृष्णानगर में दर्ज कराई थी। विशेष लोक अभियोजक अभिषेक उपाध्याय व अरुण कुमार के मुताबिक पीड़िता के घर में अभियुक्त किरायेदार था। पीड़िता व उसका भाई बरामदे में सो रहे थे। आधी रात को अभियुक्त ने मौका देखकर पीड़िता को दबोच लिया। उसके चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी दे रहा था कि पीड़िता के पिता की नींद खुल गई। देखा कि अभियुक्त बिना कपड़ों के आपत्तिजनक स्थिति में पीड़िता का गला दबाए था। उन्होंने किसी तरह पीड़िता को उससे छुड़ाया। वो मौका देखकर वहां से भाग गया।

मूल्यांकन को लेकर आगे आएं, डरे नहीं कालेज : प्रो. सहस्त्रबुद्धे

● बीबीएयू में आयोजित नैक की क्षेत्रीय कार्यशाला में नौ राज्यों के कुलपति सहित कई अधिकारी हुए शामिल

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) के चेयरमैन प्रो. अनिल सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ज्यादातर विश्वविद्यालय ने नैक से मूल्यांकन तो कराया है पर डिग्री कॉलेज के आने की रफ्तार बहुत कम है। इसका सबसे बड़ा कारण यह देखने में आया है कि कॉलेज को लगता है कि उन्हें अगर सी या डी कैटेगिरी मिला तो उनका नाम खराब होगा। वह इस डर से ही नैक मूल्यांकन के लिए सामने नहीं आते हैं। अब हमने अभी ग्रेडिंग सिस्टम हटा दिया है। अभी कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को एक्रेडिटेड या नॉट एक्रेडिट ही कहेंगे। अब कोई ए, बी, सी कैटेगरी नहीं होंगे। इस से आज जो कॉलेज सामने आने से डर रहे हैं, जो उनके मन में डर है वह बाहर हो जाएगा।

शुक्रवार को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय में आयोजित नैक की क्षेत्रीय कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए चेयरमैन प्रो. सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) से मूल्यांकन को बढ़ावा देने के लिए अब इसके नियम में व्यापक बदलाव किया गया है। मैथ के तहत ग्रेडिंग करने वाले विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों को अब ए, बी, सी और डी कैटेगरी में न रखकर, उन्हें बाइनरी कैटेगरी में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जो सिर्फ डर के मारे नहीं आ रहे हैं और वह आगे जाएंगे तो वह एक्रीडिटेशन हो जाएंगे। जो एक्रीडिटेशन नहीं होंगे, उनको कौन-कौन से पैरामीटर पर कम मार्क्स मिले हैं या जीरो मार्क्स मिले यह उनको पता लगेगा और जिसमें उन्हें अच्छा नंबर मिला है। कौन से विषय में हुआ कमजोर है। उन पर काम कर कर वह अगले बार जाकर दोबारा से एक्रीडिटेशन कर सकते हैं। प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि कई ऐसे विश्वविद्यालय नेट मूल्यांकन के लिए सामने नहीं आते हैं जो सिर्फ एक्रीडिटेशन और एग्जाम करने के लिए ही बने हैं। ऐसे विश्वविद्यालय को नैक मूल्यांकन में शामिल होने के लिए विश्वविद्यालय लेवल पर पोस्ट ग्रैजुएट कोर्सेज का संचालन कर सकता है या फिर वह ऑनलाइन कोर्सेज भी संचालित कर सकते हैं। जिसके आधार पर वह अपने मानक को पूरा करने मूल्यांकन में शामिल हो सकते हैं। ऐसे विश्वविद्यालय को अपने यहां कोई न कोई प्रावधान तो करना ही पड़ेगा। नैक के डायरेक्टर प्रो. गणेशन कन्नाबिरन ने मूल्यांकन की नयी प्रणाली का विवरण देते हुए कहा कि प्रस्तावित सुधार विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के आधार पर तैयार किये गए हैं। मूल्यांकन का नया ढांचा व्यवसाय करने में आसानी और सिस्टम में विश्वास का प्रतीक है, जो कि बिना किसी डर या अवरोध के मान्यता के लिए स्व-निर्देशित प्रेरणा को सक्षम बनाता है। नैक सदस्य प्रो. शुचिता पाण्डेय ने कहा कि शिक्षा प्रणाली में मूल्यांकन हेतु बदलाव की आवश्यकता है। जिससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को गंभीरता से लेते हुए विभिन्न विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान मूल्यांकन की प्रक्रिया में आगे आये। आगामी 5 वर्षों में देश के 90 फीसद छोटे- बड़े शिक्षण संस्थानों को नैक मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल करना ही इस नये फ्रेमवर्क का उद्देश्य है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. एन. एम. पी. वर्मा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों को नियमित रूप से अपने आंकड़ों को एकत्रित एवं व्यवस्थित करते रहना चाहिए।

अर्जित आय व निर्माण में प्रदेश में अव्वल रहा एलडीए

● अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग नितिन रमेश गोकर्ण ने एलडीए की सराहना कर जारी किया प्रशस्ति पत्र

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

एलडीए ने वित्तीय वर्ष 2023.24 में निर्माण एवं विकास व अर्जित आय के लिए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। आवास विकास मुख्यालय में आयोजित उप्र आवास एवं विकास परिषद और विभिन्न प्राधिकरणों की समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग नितिन रमेश गोकर्ण ने लखनऊ विकास प्राधिकरण की सराहना करते हुए प्रशस्ति पत्र जारी किया है। एलडीए की ओर से प्रभारी मुख्य अभियंता केके गौतम ने प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया।

शुक्रवार को एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2023.24 में अर्जित आय के लिए 1317.04 करोड़ रूपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिसके सापेक्ष एलडीए ने रिकॉर्ड प्रदर्शन करते हुए 1709ण्15 करोड़ रूपये की आय अर्जित की हैए जोकि पूरे प्रदेश में सर्वाधिक है। उन्होंने बताया कि एलडीए को सबसे ज्यादा आय ई.ऑक्शन से बेची गयी उन व्यावसायिक एवं आवासीय सम्पत्तियों से हुयी हैए जिन पर कई वर्षों से भू.माफिया का अवैध कब्जा था। एलडीए ने सिलसिलेवार तरीके से अभियान चलाकर प्राधिकरण की इन बेशकीमती सम्पत्तियों से अवैध कब्जा हटवाया। जिसके बाद इन सम्पत्तियों का साइट प्लान तैयार कराके इन्हें ई.ऑक्शन में लगाया गया। नतीजा यह रहा कि इन भूखण्डों पर दो से तीन गुना अधिक कीमत तक बोली लगी और एलडीए को निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक सफलता प्राप्त हुयी। सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023.24 में व्यावसायिक एवं आवासीय सम्पत्तियों का 06 बार ई.ऑक्शन कराया गयाए जिसमें 138 भूखण्ड व 83 दुकानों का विक्रय किया गया। इसके अलावा विभिन्न शासकीय विभागों को बल्क सेल की 08 बड़ी सम्पत्तियां आवंटित की गयी हैं, जिससे प्राधिकरण के खाते में बड़ी रकम जमा हुयी। इसके अलावा पहले आओ.पहले पाओ योजना के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में रिक्त फ्लैटों की ऑनलाइन व गोमती नगर विस्तार योजना में रिक्त फ्लैटों व भवनों को लॉटरी के माध्यम से बेचा गयाए जिसमें 175 फ्लैटध्भवन आवंटित किये गये। इस तरह से एलडीए ने अर्जित आय के लिए निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 129.77 प्रतिशत प्रगति दर्ज की है। अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि एलडीए ने वित्तीय वर्ष 2023.24 में 609ण्31 करोड़ रूपये की लागत से शहर में निर्माण एवं विकास के विभिन्न कार्य करवाये। इसमें ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत गऊघाट पर सेतु का निर्माण व आईआईएम रोड से हार्डिंग ब्रिज तक बंधा व सड़क का निर्माण और बसन्तकुंज योजना के सेक्टर.आई में प्रधानमंत्री आवास भवनों के निर्माण एवं विकास कार्य को शहर की जनता ने खूब सराहा।

विधानभवन के निर्धारित स्थानों पर होनी चाहिए क्यूआरटी की उचित व्यवस्थाः सतीश महाना

● मानसून सत्र सोमवार से, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने की उच्च स्तरीय बैठक

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

यूपी विधानसभा के आगामी 29 जुलाई से प्रारम्भ हो रहे मानसून सत्र से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शुक्रवार को आलाधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के दौरान वाहनों की जांच, आपातकाल स्थिति में विधानभवन परिरसर से सदस्यों अधिकारियों एवं नागरिकों को सुरक्षित निकालने तथा विधानभवन के निर्धारित स्थानों पर क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) आदि की भी चुस्त व्यवस्था होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विधानभवन आने वाले विधायकों के गनर और सुरक्षा कर्मियों के बैठने तथा जलपान लंच आदि की उचित व्यवस्था करने के साथ ही भविष्य में उनके बैठने की स्थाई व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान अग्निशमन उपकरणों एवं दमकल वाहनों की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही बैठक में विधानसभा भवन की वर्तमान सुरक्षा व्यवस्थाओं का आकलन करने, उसको सुदृढ़ करने, विधान सभा में दर्शकों एवं अन्य महानुभावों की प्रवेश प्रक्रिया तथा सुरक्षा आदि संबंधी अन्य बिंदुओं के विषय में विशिष्ट व्यवस्था करने पर विचार किया गया।

बैठक में प्रमुख सचिव, विधान सभा, प्रदीप दुबे, अपर मुख्य सचिव (गृह) दीपक कुमार, प्रमुख सचिव, सचिवालय प्रशासन, के. रविन्द्र नायक, एडीजी (कानून व्यवस्था) अमिताभ यश, एडीजी (सुरक्षा), रघुवीर लाल, पुलिस कमिश्नर, लखनऊ अमरेन्द्र सेंगर, जिलाधिकारी, तथा सूर्यपाल गंगवार समेत अन्य आलाधिकारी उपस्थिति थे।

बीसी सखी के माध्यम से ग्रामीणों के द्वार पर पहुंचाई जा रही बैंकिंग सेवाएं

● महिला सशक्तीकरण पर सरकार का विशेष फोकस

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किये बिना किसी भी देश, प्रदेश का समग्र विकास सम्भव नहीं है और असली भारत तो गांवों में बसता है इसलिए ग्रामीण जन जीवन की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना बहुत जरूरी होता है इस दिशा में उत्तर प्रदेश पूरी तरह गतिमान है और ग्राम्य विकास की अनेकानेक योजनाओं के माध्यम से गांवों के चहुंमुखी और बहुमुखी विकास के प्रभावी कदम उठाए गए हैं, जिसमें महिलाओं के स्वावलंबन और महिला सशक्तीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। बीसी सखी से प्रदेश की महिलायें आत्मनिर्भर हो रही हैं। बी सी सखी कार्यक्रम,देश में पहली बार बैंकों के अलावा किसी सरकारी विभाग (ग्राम्य विकास विभाग) द्वारा ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चलाया जा रहा है। ग्रामीण परिदृश्य में वित्तीय समावेशन, गरीबों, कमजोर व बुजुर्गों-समाज के अन्तिम व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाई गयी है ग्रामीण महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को घर घर पहुंचाने के लिए बीसी सखी बनाई गई। बी सी सखी के माध्यम से सब्सिडी , पेंशन, मजदूरी का भुगतान, बैंक खातों में जमा, निकासी, नए खाता खोलने आदि जैसी सुविधाएं गांवो तक पहुंचाई जा रही है। बी सी सखी द्वारा जन-धन सेवाएं,देने के साथ साथ बैंक खाते से घर- घर जाकर जमा व निकासी करवाना व स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की सेवाएं प्रदान करना है ।महिलाओं को आत्मनिर्भर व स्वावलम्बी बनाने तथा महिलाओं को रोजगार देने के लिए देश व प्रदेश में अनेकानेक महत्वाकांक्षी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

सुभारती यूनिवर्सिटी में नेट परीक्षा के दौरान हो रही धांधली का एसटीएफ ने किया खुलासा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सीएसआईआर नेट पेपर में हो रही सेंधमारी का एसटीएफ ने खुलासा किया है। एसटीएफ की टीम ने मेरठ की में सीएसआईआर नेट की परीक्षा का आयोजन किया गया है। एसटीएफ की टीम ने शुक्रवार को मेरठ में सीएसआईआर नेट के एग्जामिनेशन सेंटर सुभारती यूनिवर्सिटी पर छापेमारी की तो नकल के रैकेट का खुलासा हो गया।

एडीजी कानून व्यवस्था व एसटीएफ अमिताभ यश ने बताया कि इस मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंनेने बताया कि एक गोपनीय सूचना के आधार पर सीएसआईआर नेट के एग्जामिनेशन सेंटर सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ में एसटीएफ द्वारा एक सर्च अभियान चलाया गया। सर्च के दौरान एग्जामिनेशन लैब के सर्वर रूम से लोकल एरिया नेटवर्क के जरिए एक्स्ट्रा एडमिन कंप्यूटर मिले हैं। इसके अलावा सर्वर रूम से दो लैपटॉप भी मिले है। इसमें एनी डेस्क रिमोट एक्सेस टूल इंस्टॉल किया गया था। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश ने बताया कि एग्जाम कराने वाले कर्मचारी अरुण से एक मोबाइल मिला है। इस मोबाइल में चार अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और उनके सिस्टम की आईपी मिली है। उन्होंने बताया कि इस आईपी को सेंटर के बाहर एक व्यक्ति को शेयर किया गया था, जिससे इन अभ्यर्थियों का स्क्रीन शेयर किया गया था। अमिताभ यश ने ये भी बताया कि इनके प्रश्न पत्र को बाहर सॉल्वर के जरिए हल किया जा रहा था। इसके साथ ही 25 जुलाई यानी कल होने वाले सीएसआईआर नेट के प्रथम और द्वितीय पाली के 11 अभ्यर्थियों के नाम मोबाइल के डिलीट फाइल से मिले हैं।

रिस्पांस टाइम में पूरे देश में यूपी की एंबुलेंस सेवा पहले पायदान पर

● रिस्पांस टाइम में दूसरे स्थान पर राजस्थान तो तीसरे पायदान पर है केरल

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

यदि आपातकाल में मरीज को सही समय में हेल्थ केयर की सुविधा मिल जाए तो ऐसे लाखों मरीजों की जान बचायी जा सकती है। प्रदेश की योगी सरकार ने इस समस्या पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी एंबुलेंस सेवा 108 (इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज) के रिस्पांस टाइम को रिकार्ड स्तर पर सुधारा है। जबकि उत्तर प्रदेश देश भर में सबसे अधिक 25.74 करोड़ जनसंख्या वाला राज्य है। प्रदेश में एंबुलेंस सेवा के रिस्पांस टाइम 7.30 मिनट के साथ देशभर में पहले स्थान पर है। वहीं दूसरे स्थान पर 7.57 मिनट के साथ राजस्थान, तीसरे स्थान पर 10.45 मिनट के साथ केरल है। वहीं सबसे खराब रिस्पांस टाइम 16.02 मिनट झारखंड का है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का रिस्पांस टाइम 15.01 मिनट और दिल्ली का 13.31 मिनट है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जीएम पराग पांडेय ने बताया कि एंबुलेंस सेवा 108 का रिस्पांस टाइम वर्ष 2017-18 में 13.23 मि. और वर्ष 2018-19 में 14.46 मि. दर्ज किया गया। वहीं वर्ष 2019-20 में 17.28 मि. और 2020-21 में 18.07 मिनट रिस्पांस टाइम दर्ज किया। यह रिस्पांस टाइम वैश्विक कोरोना बीमारी की वजह से बढ़ाया गया था। इसके बाद वर्ष 2022-23 में 8.46 मिनट और वर्ष 2023-24 में 7.24 मिनट दर्ज किया गया है। वहीं वर्तमान में रिस्पांस टाइम 7.30 मिनट है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में एंबुलेंस सेवा का सबसे कम रिस्पांस टाइम उत्तर प्रदेश का ही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवल ने बताया कि एंबुलेंस सेवा 108 के रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए विभिन्न पहलुओं को काम शुरू किया गया ताकि गंभीर मरीजों को समय से अस्पताल पहुंचाया जा सके और उसकी जान बचायी जा सके।

केजीएमयू के जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट को मिलेगी नई बिल्डिंग

● 315 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

योगी सरकार ने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को आधुनिक सुविधाओं युक्त करने के साथ ही भविष्य की जरूरतों के हिसाब से मेकओवर करना शुरू कर दिया है। इसके तहत जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट को नई बिल्डिंग से युक्त करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। मेडिकल यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर ही 9.62 एकड़ क्षेत्र में 37,128.76 स्क्वेयर मीटर के बिल्ड अप क्षेत्र में 315 करोड़ रुपए की लागत से बिल्डिंग का निर्माण व विकास किया जाएगा।

परियोजना के अंतर्गत कार पार्किंग के लिए 2 मंजिला अंडर ग्राउंड बेसमेंट का विकास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ग्राउंड फ्लोर समेत कुल 7 मंजिला ऊंची बिल्डिंग का निर्माण कर इसे हॉस्पिटल व बिल्डिंग मैनेजमेंट प्रक्रिया से लैस किया जाएगा। साथ ही, एडवांस रोबोटिक सर्जरी सिस्टम, 300 बेड युक्त टीचिंग हॉस्पिटल, मॉर्चरी व ऑडिटोरियम समेत विभिन्न सुविधाओं से युक्त किया जाएगा जिसका लाभ आम लोगों के साथ ही यहां के प्रशिक्षु डॉक्टरों को प्राप्त होगा।

परियोजना के अंतर्गत नियोजन विभाग ने सभी निर्माण व विकास कार्यों को पूरा करने के लिए एजेंसी निर्धारण व कार्यावंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस कार्य को पूरा करने के लिए आवेदन भी मांगे गए हैं और अगस्त महीने में एजेंसी निर्धारण व कार्यावंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उल्लेखनीय है कि सभी निर्माण व विकास कार्यों को टर्न-की बेसिस पर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट व कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड में किया जाएगा। एजेंसी निर्धारण व कार्यावंटन के बाद सभी निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए 24 महीने की समयावधि निर्धारित की गई है। योजना के अंतर्गत ग्राउंड फ्लोर को स्टिल्ट फ्लोर के तौर पर विकसित किया जाएगा और फर्स्ट फ्लोर सर्विस एरिया होगा। दूसरे फ्लोर पर 60 बेड वाला जनरल वॉर्ड, तीसरे फ्लोर पर 60 बेड वाला जनरल वॉर्ड, चौथे फ्लोर पर 120 बेड वाला जनरल वॉर्ड, 5वें फ्लोर पर 30 बेड वाला प्राइवेट वॉर्ड, 18 बेड वाला एचडीयू, 12 बेड वाला प्री ऑपरेशन व 20 बेडेड डे केयर वॉर्ड बनेंगे। छठे फ्लोर पर 30 बेड वाला पोस्ट ऑपरेशन, 10 ओटी, एक हाइब्रिड ओटी व 12 बेडेड आईसीयू का निर्माण होगा। जबकि 7वें फ्लोर पर फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव व स्टोर ब्लॉक्स का निर्माण होगा।

कई खास सुविधाओं से लैस होगी नई बिल्डिंगः परियोजना के अंतर्गत नई बिल्डिंग को ऑडिटोरियम, यूजी टैंक, पंप रूम, मॉर्चरी, लॉन्ड्री, सर्विस फ्लोर्स, एचवीएसी, फायर अलार्म, सीसीटीवी, लिफ्ट, आईबीएमएस, टू वे ऑडियो-विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेटअप तथा ईपीबीएएक्स नेटवर्किंग सिस्टम से लैस किया जाएगा। बिल्डिंग को सौर ऊर्जा युक्त बनाने के लिए संयंत्रों की स्थापना भी होगी।

इंडियन बैंक ने स्थापना दिवस पर शुरू की रथ यात्रा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रत्येक वर्षों की भांति इस वर्ष भी इंडियन बैंक अपने स्थापना दिवस को हर्षोल्लास एवं नई ऊर्जा का संचार करते हुए अपनी नित नई उपलब्धियों के साथ उत्साहपूर्वक मना रहा है।

इस रथ यात्रा अभियान में ग्राहकों को डिजिटल जागरूकता के साथ साथ बैंक की विभिन्न उत्कृष्ट कासा उत्पादों, इण्ड स्मार्ट मोबाइल बैंकिंग एप, रिटेल एवं एमएसएमई जैसे प्रतिस्पर्धी ऋण उत्पादों के साथ जुड़ने एवं उनका लाभ उठाने को प्रेरित किया गया। इस अभियान का शुभारंभ बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री सुधीर कुमार गुप्ता, लखनऊ अंचल प्रबंधक श्री प्राणेश कुमार ने किया। यह रथ यात्रा इंडियन बैंक हजरतगंज की मुख्य शाखा से प्रारंभ होकर गोमतीनगर, इंदिरा नगर, अलीगंज, केजीएमसी एवं आलमबाग अन्य क्षेत्रों से होकर गुजरी। इस अवसर पर क्षेत्र महाप्रबंधक कार्यालय के उप महाप्रबंधक श्याम शंकर, सहायक महाप्रबंधक ईश प्रकाश शुक्ला, लखनऊ उप अंचल प्रबंधक राजेश कुमार इंस्पेक्शन सेल से उप महाप्रबंधक सुबोध कुमार पाणिग्रही, सहायक महाप्रबंधक बीनाकुमारी एम पी., एल.सी.बी. सहायक महाप्रबंधक नितेश कुमार एवं हजरतगंज मुख्य शाखा प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद दुबे उपस्थित रहे।

नारायण सेवा संस्थान का निःशुल्क लिम्ब शिविर 28 को

लखनऊ। उदयपुर का प्रतिष्ठित एवं राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त एनजीओ नारायण सेवा संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश में दिव्यांगों के कल्याणार्थ विशाल निःशुल्क शिविर का आयोजन 28 जुलाई को लखनऊ के दयाल गेटवे होटल में आयोजित होगा।संस्थान निदेशक ट्रस्टी देवेंद्र चौबीसा ने बताया कि ऐसे लोग जिन्होंने किसी हादसे में या अन्य बीमारी के चलते अपना हाथ-पैर गंवा देने से अंगविहिन हुए है, उन्हें दिव्यांगता की दुःखभरी जिन्दगी से निकालने के लिए संस्थान निस्वार्थ भाव से प्रतिबद्ध है। पदमश्री अलंकृत संस्थापक कैलाश मानव की प्रेरणा से संस्थान विगत 39 वर्षों से संस्थान मानवता और दिव्यांगता के क्षेत्र में सेवारत है। उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजनों को मदद पहुंचाने के संकल्प से विशाल निःशुल्क दिव्यांगता निवारण ऑपरेशन चयन एवं नारायण लिम्ब मैजरमेंट शिविर लखनऊ के दयाल गेटवे होटल, किसान बाजार, विभूति खंड,सिनेपोलिस मॉल के सामने गोमती नगर में रविवार 28 जुलाई को प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक चलेगा।

महिला सशक्तीकरण व योग विषयक संगोष्ठी आयोजित

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

'महिला सशक्तीकरण और योग' विषयक संगोष्ठी का आयोजन वसंत महिला महाविद्यालय वाराणसी के हिंदी विभाग द्वारा महाविद्यालय परिसर में किया गया। संगोष्ठी का संयोजन प्रो. मीनू अवस्थी द्वारा किया गया। इस संगोष्ठी में महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. अलका सिंह ने जनजीवन में योग की महत्वता पर प्रकाश डाला तथा डॉ. राजेश चौधरी ने अपनी दिनचर्या में योग की उपस्थित के महत्व के विषय पर चर्चा की एवम् डा. किरण तिवारी ने महिला सम्बन्धित रोगों के सुधार में योग के महत्व पर प्रकाश डाला । हिंदी विभाग की छात्राओं में कविता, वैष्णवी, तृषा,छवि एवं नवोदिता ने गृहणियों के जीवन में योग की आवश्कता और मानसिक तनाव से मुक्ति में योग की महत्वपूर्ण भूमिका एवम् सरकार द्वारा चलाई गई योग आधारित योजनाओं पर अपने विचार साझा किए।

कार्यक्रम का संचालन हिन्दी विभाग की छात्रा कविता सिंह के द्वारा किया गया, साथ ही धन्यवाद ज्ञापन नवोदिता त्रिपाठी द्वारा संपन्न किया गया।

मनाया गया कौशल एवं डिजिटल इनिशिएटिव्स दिवस

लखनऊ। योगी सरकार बचपन से ही छात्रों को कौशल विकास से जोड़कर उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। शुक्रवार को बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षा सप्ताह के तहत बच्चों को कौशल विकास से संबंधित जानकारियां दी गईं और उन्हें इसके लाभ बताए गए। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालयों में 22 से 28/29 जुलाई तक शिक्षा सप्ताह मना रहा है। इसके तहत प्रत्येक दिन विभिन्न गतिविधियों का आयोजन हो रहा है। शिक्षा सप्ताह के प्रत्येक दिन एक विशिष्ट गतिविधि में बच्चों को शामिल किया जा रहा है। इसी कड़ी में शिक्षा सप्ताह के पांचवें दिन, बेसिक शिक्षा विभाग ने कौशल एवं डिजिटल इनिशिएटिव्स दिवस मनाया। इस दौरान बच्चों को कौशल से जुड़ी जानकारियां दी गईं और उनके भविष्य को संवारने के लिए परिषदीय शिक्षकों ने अनूठे अंदाज में इसको प्रस्तुत किया।

इण्डियन ओवरसीज बैंक ने खोलीं 11 नई शाखाएं

● ग्राहकों के लिए 444-दिन की जमा पर अधिकतम ब्याज-दर का ऑफर

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक (आइओबी) ने तेलीबाग, अयोध्या, बलरामपुर, ललितपुर, सुगामऊ, बांदा, बिजनौर रोड, दुबग्गा, कल्याणपुर कानपुर, मोहनलालगंज, विराजखंड गोमतीनगर में 11 नई शाखाएँ खोलीं, जिनमें भौतिक रूप से दो शाखाओं तथा नौ अन्य शाखाओं का वर्चुअली उद्घाटन अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रबंध निदेशक व सीईओ, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक द्वारा पूर्ण चंद्र शतपथी, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, लखनऊ की उपस्थिति में किया गया।यह शाखाओं का विस्तार आने वाले दो वर्षों में पूरे उत्तर प्रदेश में 100 शाखाएँ खोलने की बैंक की योजना के अनुरूप है ।

उद्घाटन समारोह में बोलते हुए, इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्रबंध निदेशक व सीईओ, श्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने कहा, हम उत्तर प्रदेश के लोगों की सेवा करने और राज्य के वित्तीय समावेशन एजेंडे का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लखनऊ भर में इन नई शाखाओं के खुलने से क्षेत्र में आइओबीकी कुल शाखा संख्या 81 हो गई है । ये शाखाएँ स्थानीय समुदायों की बढ़ती बैंकिंग जरूरतों को पूरा करेंगी, जमा, ऋण, प्रेषण और बीमा सहित उत्पादों व सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश करेंगी। अब बैंक की पूरे भारत में 3,264 शाखाएँ और उत्तर प्रदेश में 231शाखाएँ हैं। इसके अलावा, बैंक अपने ग्राहकों को प्रतिस्पर्धी और आकर्षक वित्तीय उत्पाद प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए, सभी बैंकों के बीच 444 दिनों की जमा पर सबसे अधिक ब्याज दर की पेशकश भी कर रहा है। बैंक ने अपनी मजबूत वित्तीय स्थिति और विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए चालू वित्तीय वर्ष में भी अच्छा प्रदर्शन किया है।

अपनी भौतिक उपस्थिति को बढ़ाने के अलावा, आइओबीअपनी डिजिटल पेशकशों को बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। बैंक ने अपने ग्राहकों को निर्बाध बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए 'मेरा नाम मेरा खाता' और खाता पोर्टेबिलिटी जैसी कई नवीन योजनाएं शुरू की हैं।

तार टूटने से सारी रात बिजली संकट झेलते रहे साढ़े पांच हजार से अधिक उपभोक्ता

संवाददाता। मोहनलालगंज

ट्री कटिंग और जर्जर तार बदलने में बरती जा रही लापरवाही हजारों उपभोक्ताओं को बिजली संकट झेलकर चुकानी पड़ रही है। मोहनलालगंज में पूरनपुर सबस्टेशन के साढ़े पांच हजार से अधिक उपभोक्ताओं को गुरुवार की सारी रात बिजली आपूर्ति बाधित रहने से भीषण गर्मी में जागकर बितानी पड़ी। अधिकारियों और 1912 पर शिकायत के बावजूद रात में विद्युत आपूर्ति चालू नही हो सकी। जिसे लेकर एक्सइएन से लापरवाही की जांच कराकर मुआवजा दिलाने की मांग की गई है। मोहनलालगंज में पूरनपुर सबस्टेशन के कालूबीरन खेड़ा सेंवई और दहियर फीडर की विद्युत आपूर्ति गुरुवार की रात्रि लगभग 11 बजे से पूर्व ही 11 केवी लाइन के तार टूटने से बाधित हो गई।

विद्युत आपूर्ति ठप होने से परेशान तीन दर्जन गांव के उपभोक्ताओं ने जेई और एसडीओ से लेकर 1912 तक शिकायत दर्ज कराई फिर भी कई घंटे तक विद्युत आपूर्ति बहाल नही हो सकी। थकहार कर लोगों ने रात्रि करीब 2 बजे एक्सइएन एसके अग्रवाल को परेशानी बताई। तब जाकर अधिकारियों की नींद टूट सकी। रात्रि करीब ढ़ाई बजे जेई और एसडीओ भागकर पूरनपुर सबस्टेशन पहुंचे और कर्मचारियों को तीनों फीडर की विद्युत आपूर्ति शीघ्र चालू करने की हिदायत दी। जिसके बाद सुबह लगभग 5 बजे तक कालूबीरन खेड़ा और सेंवई फीडर से पोषित 28 गांव के लोगों को बिजली मिल सकी।जबकि दहियर फीडर में सूती धागे की तरह तीन जगह टूटे तार जोड़कर आधा दर्जन गांव की विद्युत आपूर्ति सुबह तकरीबन 8 बजे चालू कराई जा सकी।

भीषण गर्मी में सारी रात बेचैन रहे उपभोक्ताओं ने अधिकारियों पर जर्जर लाइन दुरुस्त कराने व ट्री कटिंग और पेट्रोलिंग में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। हालांकि एक्सइएन एसके अग्रवाल ने बताया बारिश की वजह से रात्रि में ब्रेकडाइन हुई लाइनों की मरम्मत में काफी वक्त लग गया। इस दौरान जेई और एसडीओ खुद सबस्टेशन पर मौजूद रहकर मरम्मत कार्यों की निगरानी करते रहे। जर्जर लाइनों को आरडीएसएस स्कीम के अंतर्गत दुरुस्त कराया जा रहा है। उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो इसका यथासंभव पूरा ख्याल रखा जा रहा है।

युवक ने किशोर से फायरिंग कराकर वीडियो किया वायरल

मोहनलालगंज। ग्रामीणों में दबंगई दिखाने के लिए गांव के युवक ने ही ग्राम प्रधान के बेटे से हवाई फायरिंग कराकर वीडियो बना लिया था। इसके पूर्व उसने खुद भी अवैध असलहे से फायरिंग कर वीडियो बनाया था। बाद में रौब गांठने के लिए उसी ने किशोर का फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मोहनलालगंज की एक ग्राम पंचायत की महिला प्रधान के नाबालिग बेटे का तमंचे से फायरिंग करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पूछताछ में किशोर ने गांव के बुद्धिप्रकाश पर लगभग 45 दिन पूर्व अवैध तमंचा देकर फायरिंग कराने और उसका वीडियो बनाने का आरोप लगाया। पुलिस ने किशोर न्याय अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। उधर पुलिस ने बुद्धिप्रकाश को दबोचकर पूछताछ शुरू की तो उसने दबंग छवि बनाने के लिए अवैध तमंचे से खुद और किशोर को फायरिंग कराने की बात कबूली। पुलिस को उसके पास से 315 बोर का अवैध तमंचा और दो जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। एसएचओ आलोक राव ने बताया आरोपी बुद्धिप्रकाश के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि किशोर को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है।

चिकित्सकों ने शिविर लगाकर बुजुर्गों का किया उपचार

मोहनलालगंज। कल्ली पूरब गांव में शुक्रवार को 50 शैय्या एकीकृत आयुष चिकित्सालय की ओर से वृद्धावस्था रोग निवारक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चिकित्सा अधीक्षक संदीप कुमार शुक्ल चिकित्सक आशुतोष शुक्ल और चिकित्सक प्रज्ञा साहू ने 125 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें चिकित्सीय परामर्श और दवाएं वितरित कराई। चिकित्सको ने मरीजों को स्वस्थ होने के लिए चिकित्सालय आकर उपचार जारी रखने की नसीहत दी। इस दौरान दिलीप आलोक शाल्वी पिंकी और कौशल समेत अन्य चिकित्सालय कर्मी भी पूरे मनोयोग से जुटे रहे।

गंदगी व जल निकासी की समस्या पंचायतों के लिए बनी चुनौती

संवाददाता। मोहनलालगंज

तहसील की पंचायतों में संचारी रोग नियंत्रण अभियान के दौरान गंदगी और जलनिकासी की समस्या चुनौती बन रही है। फिर भी डेढ़ दर्जन ग्राम पंचायतों में केंद्रीय वित्त की पछहत्तर लाख से अधिक धनराशि अब तक खर्च नही की जा सकी है। जिससे साफ है कि इन पंचायतों में व्यापक स्वच्छता और जलनिकासी के कार्यों को अमलीजामा पहनाने में लापरवाही बरती जा रही है।

मोहनलालगंज तहसील के गोसाईगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत अकरहदू अस्ती हुसैनाबाद दुल्हापुर कबीरपुर कासिमपुर बिरुहा महमूदपुर सेल्हुमऊ व शिवलर में पंद्रहवें वित्त की 28 लाख से अधिक धनराशि डंप है। जिसे अब तक विकास कार्यों पर खर्च नही किया जा सका है। इसी तरह मोहनलालगंज ब्लॉक की ग्राम पंचायत डांडासिकंदरपुर हुलाखेड़ा दहियर करौरा कोडरा रायपुर कुढ़ा मीरकनगर नटौली सुलसामऊ हिल्गी और सरथुआ में पंद्रहवें वित्त की 46 लाख से अधिक धनराशि अब तक खर्च नही की जा सकी है। खास बात यह है कि पंचायतों में सर्वाधिक टाइड फंड डंप है। जिसका प्रयोग कर गांवों में स्वच्छता और जलनिकासी के लिए नाली निर्माण के कार्य कराए जाने चाहिए । बारिश में इन कार्यों के लिए अधिकारियों के पास अनगिनत शिकायतें पहुंच रही हैं। फिर भी सचिव और प्रधान टाइड फंड को खर्च करने में दिलचस्पी नही ले रहे हैं। जिला पंचायतराज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया पंचायतों में डंप फंड निर्धारित कार्यों पर खर्च करने के लिए नियमित रूप से समीक्षा कर सचिवों को निर्देश दिए जाते हैं। सभी सचिवों को केंद्रीय वित्त की धनराशि से स्वच्छता और जलनिकासी के कार्य प्राथमिकता पर कराने के लिए कहा गया है।

तदर्थ शिक्ष संघर्ष समिति ने अखिलेश यादव को सौंपा ज्ञापन

लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति उप्र ने ज्ञापन सौंप कर एडेड माध्यमिक विद्यालयों में सृजित, अनुदानित व रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्त व दशकों से कार्यरत तदर्थ शिक्षकों की वर्तमान राज्य सरकार द्वारा सेवाएं समाप्त कर अपमानजनक व शोषणकारी मानदेय पूर्ण अस्थायी व्यवस्था में नियुक्ति के विरूद्ध तदर्थ शिक्षकों को न्याय दिलाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में वर्ष 1993 से अब तक नियुक्त व कार्यरत 2254 तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं 9 नवम्बर 2023 के जारी एक शासनादेश से समाप्त कर दी गयी और उन्हें पिछले 8 महीने से न तो काम करने दिया जा रहा है, न ही वेतन दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने हालिया जारी शासनादेश 8 जुलाई 2024 में यह माना है कि माध्यमिक शिक्षा में हजारों पद रिक्त हैं और शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है तथा विकल्प के रूप में सेवा समाप्त ऐसे तदर्थ शिक्षकों को सहायक अध्यक्ष 25,000 रुपए तथा प्रवक्ता 30,000 रुपए के अत्यल्प मानदेय पर कार्य करने को निर्देशित किया है।

प्रत्येक युवा को समग्र रूप से सक्षम बनाना चाहती है सरकारः भूपेश चौबे

●सदर विधायक ने छात्र-छात्राओं को बांटे स्मार्टफोन

संवाददाता। डाला, सोनभद्र

ग्राम पंचायत कोटा के परासपानी स्थित केशव राम महाविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष के छात्र-छात्राओं में शुक्रवार को 49 स्मार्टफोन वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि सदर विधायक भूपेश चौबे व विद्यालय के प्रबंधक श्रीकांत त्रिपाठी विपिन के साथ अन्य अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण कर किया गया। इसके बाद छात्राओं ने सरस्वती वंदना व स्वागत गीत प्रस्तुत किया।

अतिथियों से फोन हाथ में पाते ही छात्र-छात्राएं निहाल हो गए उनके चेहरे पर खुशी साफ-साफ झलक रही थी। मुख्य अतिथि सदर विधायक भूपेश चौबे ने कहा कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण हेतु प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी के सहयोग से जो स्मार्ट फोन वितरण हो रहा है उसका मकसद छात्र-छात्राओं को स्मार्ट बनाना है। यदि आप ठान लें तो कोई भी काम असंभव नहीं है। आज के दौर में युवाओं के लिए हर व्यक्ति चिंतित हैं युवाओं को प्रतिभावान बनाने के लिए सरकार ऐसी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे तमाम अवसर देने में लगी है। इस बजट में युवाओं को रोजगार के लिए कम दर पर बैंकों से ऋण मिलने का बजट पास हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्नातक करने वाले सभी छात्र-छात्राओं के हाथों में स्मार्टफोन देने का कार्य किया है।उन्होंने छात्र-छात्राओं से कहा कि प्रतिभावान बनकर समाज को दिशा व दशा दिखाने का कार्य करें। शिक्षा के साथ अनुशासन जरूरी है यदि आप हुनरमंद हैं तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता इसलिए आत्मनिर्भर बने मोबाइल का सही उपयोग करें।

विजय दिवस पर कारगिल शहीदों के नाम पर रखे गए चौराहों के नाम

अंबेडकर नगर। विजय दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि वीर शहीदों के स्मृतियों को चिरस्थाई बनाने, वीर शहीदों के स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने हेतु चौराहों एवं तिराहों का नामकरण किया गया है। इसी के क्रम में आज जिलाधिकारी की गौरव मय उपस्थिति में वीर शहीदों के नाम से बनाए गए दो चौक,तिराहों यथा शहीद सिपाही धनुषधारी वीरचक्र गोहन्ना चौराहा व शहीद हवलदार देवी प्रकाश सिंह वीरचक्र टांडा बाईपास तिराहा पर पहुंच कर संबंधित वीर सहित के परिजनों द्वारा फीता काट कर लोकार्पण किया गया। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि पुरानी तहसील तिराहां शहीद एमई-1 विक्रमादित्य सिंह तिराहा का कार्य प्रगति पर है।

बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि शहीदों के स्मृतियों एवं बलिदान जीवंत बनाए रखने के दृष्टिगत 9 शहीद द्वार के निर्माण के लिए 6.13 लाख रूपये का प्रस्ताव सैनिक कल्याण निदेशालय के माध्यान से उ प्र शासन लखनऊ को भेजा गया। इस दौरान उप जिलाधिकारी मोहन लाल गुप्ता , जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल बीके शुक्ला, पूर्व सैनिक, शहीदों के आश्रित, पेंशनर तथा सैनिक कल्याण के कार्मिक मौके पर उपस्थित रहे।

प्रयागराज जंक्शन एवं प्रयागराज छिवकी स्टेशनों पर चला मजिस्ट्रेट चेकिंग अभियान

संवाददाता। प्रयागराज

मंडल रेल प्रबन्धक प्रयागराज हिमांशु बडोनी के नेतृत्व में रेल यात्रियों को सुरक्षित सुखद और आरामदायक यात्रा के साथ बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रयागराज मंडल में अवैध वेंडरों गंदगी फैलाने वालों टिकट रहित और अनियमित यात्रा पर अंकुश लगाने के लिए स्टेशनों और गाड़ियों में विशेष टिकट चेकिंग अभियान चलता रहता है। गुरुवार को प्रयागराज जंक्शन एवं प्रयागराज छिवकी स्टेशनों पर मजिस्ट्रेट चेकिंग अभियान चलाया गया।

जांच अभियान में टिकट चेकिंग स्टाफ रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस मिलकर कार्य करते हुए अवैध वेंडरों गंदगी फैलाने वालों धूम्रपान अनबुक्ड लगेज टिकट रहित एवं अनियमित यात्रा करने वालों पर जुर्माना लगाया गया। जाँच अभियान में दस गाड़ियों सहित स्टेशनों की सघन जांच की गई।

अभियान में कुल 53 यात्रियों को प्रभारित कर 25650 रूपए जुर्माना वसूल किया गया। इसमें तीस बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रभारित कर 11610 रूपए 04 अनियमित यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रभारित कर 1500 रुपए 13 गंदगी फ़ैलाने वाले यात्रियों को प्रभारित कर 1700 रूपए एवं 06 बिना बुक सामान के यात्रियों से 10840 रूपए का जुर्माना वसूल किया गया। गुरुवार को ही वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबन्धक प्रयागराज हिमांशु शुक्ला के निर्देशानुसार सहायक मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक दिनेश कुमार के नेतृत्व में प्रयागराज जंक्शन एवं प्रयागराज छिवकी स्टेशन पर अवैध वेंडरों गंदगी फैलाने वालों टिकट रहित एवं अनियमित यात्रा के विरुद्ध अभियान में मण्डल मुख्य टिकिट निरीक्षक रेड दिवाकर शुक्ला ने रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस के साथ स्टेशन एवं गाड़ियों की सघन जांच की।

रक्तदान शिविर में कुल सचिव एवं शिक्षकों ने किया रक्तदान

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में शुक्रवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रक्तदान करने के लिए विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों में उत्साह बरकरार रहा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो सत्यकाम के निर्देशन में मुक्त विश्वविद्यालय में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन स्वास्थ्य विज्ञान विद्या शाखा एवं तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय प्रयागराज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। कुलपति प्रो सत्यकाम ने सरस्वती परिसर में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों अधिकारियों एवं कर्मचारियों में रक्तदान के प्रति उत्साह बरकरार रहा। शिविर में पचास से अधिक लोगों ने नामांकन कराया। जिन्होंने रक्त समूह तथा ब्लड प्रेशर की जांच कराई। रक्तदान करने वालों में कुलसचिव कर्नल विनय कुमार प्रो पी के स्टालिन प्रो श्रुति प्रो ए के मलिक डॉ शिवेंद्र प्रताप सिंह डॉ मुकेश कुमार मौर्य अनुपम अनुराग शुक्ला आशुतोष कुमार मिश्रा आदि प्रमुख रहे। कुलपति प्रो सत्यकाम ने रक्तदाताओं को प्रदेश शासन और बेली अस्पताल की तरफ से प्रशस्ति पत्र प्रदान किए और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। शिविर में स्थानीय तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय रक्तदान केंद्र की तरफ से हेमंत शुक्ला डॉ संजू अजय मिश्रा संदीप मिश्रा भूपेंद्र पांडे लवलेश शुक्ला वीरेन्द्र तथा उपासना आदि ने सक्रिय सहयोग किया।

कारगिल युद्ध के शहीदों को दी गयी श्रद्धांजलि

सोनभद्र। कारगिल युद्ध के शहीद देश के वीर सपूतों को शुक्रवार को जनपद में जगह-जगह श्रद्धांजलि दी गयी। इस दौरान उनके बलिदान को याद किया गया। कारगिल विजय दिवस पर राबर्ट्सगंज स्थित चाचा नेहरू पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। काग्रेस नेता आशुतोष दुबे ने कहा कि हमने सदियों में यह आजादी की नेमत पाई है, सैंकड़ों कुर्बानियां देकर यह दौलत पाई है। इस मौके पर अंशु मद्धेशिया, सोनू खान, सुशील कुमार, दिनेश कुमार, रोहित, राजकुमार चंद्रवंशी, श्यामलाल आदि रहे। राबर्ट्सगंज स्थित राजा शारदा महेश इंटरमीडिएट कालेज के छात्र-छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम कर कारगिल विजय दिवस पर वीर शहीदों को नमन किया। भाजयुमो जिलाध्यक्ष विशाल पांडे ने कहा कि यह जीत हमारे वीर जवानों के दम पर मिली। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता, अध्यक्ष रूबी प्रसाद, ब्लाक प्रमुख अजीत रावत, धर्मवीर तिवारी आदि रहे।

कोतवाल के फोन न उठाने से नाराज विधायक बैठे धरने पर

चन्दौली। कोतवाल के फोन न उठाने से नाराज सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण सिंह यादव शुक्रवार को कार्यकर्ताओं संग पुलिस लाइन में धरने पर बैठ गए। आरोप लगाया कि दोपहर से रात तक फोन करते रहे, लेकिन सदर कोतवाल ने उनका फोन नहीं उठाया यह शासनादेश का उल्लंघन और विधायिका की अवमानना है। इसको लेकर एसपी से मुलाकात कर कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। विधायक ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए गंभीर आरोप लगाए और धरना पर बैठ गए तो पुलिस का कहना है कि इंस्पेक्टर ने फोन उठाया था। विधायक धोखाधड़ी के आरोपियों को छोड़ने का दबाव बना रहे थे। पुलिस ने नही सुना तो वह धरने पर बैठ गए। बहरहाल एसपी चंदौली ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं।

इस बाबत एसपी आदित्य लांग्हे का कहना है कि जमीनी धोखाधड़ी से जुड़े मुलजिम व एक जमीन से जुड़े प्रकरण में विधायक ने फोन किया था इस संबंध में वार्ता हुई उनके द्वारा संज्ञान में दिए गए दोनों प्रकरण में जांच हो रही है जांच के बाद दोषी पाए जाने पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की माने तो विधायक प्रभु नारायण यादव जमीनी धोखाधड़ी से जुड़े पुराने मामले में निरुद्ध मुलजिम व जमीन से जुड़े प्रकरण में सकलडीहा विधायक ने फोन किया था। इस संबंध में कोतवाल से उनकी वार्ता भी हुई । वहीं विधायक प्रभुनरायण यादव का कहना था कि पुलिस इनदिनों लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है इससे आएदिन विवाद सामने आ रहे हैं।

लीवर स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरीः डॉ. डीके निगम

प्रयागराज। विश्व हेपेटाइटिस दिवस एक वैश्विक पहल है। जिसका लक्ष्य वायरल हेपेटाइटिस के बारे में आम जनता के मध्य में जागरूकता बढ़ाना और इस संभावित जानलेवा बीमारी को रोकने और नियंत्रित करने के उपायों को अग्रसर करना है। प्रयागराज के गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉ डी के निगम ने कहा लीवर स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जो कि समूचे शारीरिक संरचना को स्वस्थ रखने की आधारशिला है। लीवर पाचन डिटॉक्सिकेशन और पोषक तत्वों के भंडारण के लिए बेहद जरुरी शक्तिशाली अंग है। लीवर के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने से न केवल आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि आपके जीवन की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हो सकता है। फलों सब्जियों साबुत अनाज और संतुलित प्रोटीन से भरपूर आहार लीवर की बेहतरी में मदद करता है। अधिक मात्रा में शराब और वसायुक्त खाद्य पदार्थों के परहेज से फैटी लीवर सम्बंधित रोग और सिरोसिस जैसी लीवर की गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है।

मेडिकल कॉलेज प्राचार्य पर लगे आरोप को लेकर कांग्रेस महासचिव ने महानिदेशक को लिखा पत्र

मीरजापुर। डॉ बिस्वजीत दास, कुछ ही दिनों पूर्व मेडिकल कालेज मीरजापुर के प्रधानाचार्य बनाये गये हैं। ये काफी सरल स्वभाव होने के साथ ही साफ-सुथरी छवि के अधिकारी हैं। भदोही के सांसद ने डॉ बिस्वजीत दास के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता की शिकायत की है। जबकि यह सोचने का विषय है कि डा0 बिस्वजीत दास के प्रधानाचार्य बनते ही कुछ ही दिन हुए कि मेडिकल कालेज में सारी वित्तीय अनियमितता हो गयी, क्या इसके पूर्व सब कुछ ठीक था। मामला यह है कि डा0 बिस्वजीत दास द्वारा चिकित्सालय में कार्यरत कुछ ऐसे अधिकारी कर्मचारी को कार्यमुक्त किया गया है जो काफी वर्षो से तैनात थे तथा सरकारी ड्यूटी न करके चिकित्सालय की छवि धुमिल करने का कुत्सित प्रयास कर रहे थे। सांसद को भ्रमित कर झूठी शिकायत कराया गया हैं, क्या इसके पूर्व सांसद को मेडिकल कालेज में कोई भी वित्तीय अनियमितता नहीं दिखी। सांसद महोदय के शिकायत से तो यह प्रतीत हो रहा है कि सारी अनियमितताये पूर्व प्रधानाचार्य डा0 आर0बी0 कमल के समय की हैं कालेज का कोई भी कार्य प्रधानाचार्य के नियंत्रण में होता है, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य का ही होता है। इस प्रकार से सांसद महोदय द्वारा की गयी शिकायत अपने आप में ही आधारहीन एवं भ्रमित होकर शिकायत किये जाने की ओर संकेत कर रहा है।

6 अगस्त को होगा इफ्को इम्पलाइज यूनियन का चुनाव

प्रयागराज। इफ्को इम्पलाइज यूनियन की आम सभा इफ्को संयंत्र के मुख्य गेट पर आयोजित की गई। इम्पलाइज यूनियन के अध्यक्ष पंकज पाण्डेय और महामंत्री विनय कुमार यादव ने अपने कार्यकाल दो अगस्त 2021 से अब तक हुए कार्यों का ब्योरा प्रस्तुत किया तथा उपलब्धियाँ गिनाई। यूनियन के महामंत्री विनय कुमार यादव ने चुनाव की घोषणा की। सभी कर्मचारियों से इस महापर्व में भागीदारी बनने की अपील की। इफ्को इम्पलाइज यूनियन का चुनाव 06 अगस्त 2024 को सम्पन्न होगा। इम्पलाइज यूनियन का चुनाव अध्यक्ष उपाध्यक्ष महामंत्री संयुक्त मंत्री संगठन संयुक्त मंत्री प्रचार कोषाध्यक्ष सहायक मंत्री कार्यकारी सदस्य पदों पर होना है। विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा चुनाव अधिकारी की नियुक्ति के बाद की जाएगी।

घर से बाजार के लिए निकली दो चचेरी बहनें लापता

सोनभद्र। कोन थाना क्षेत्र के अन्तर्गत एक गांव की रहने वाली दो चचेरी बहनें घर से बाजार के लिए निकलने के बाद अचानक लापता हो गई। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन करने के बाद भी जब पता नही चला तो लड़की के पिता ने कोन थाने में प्रार्थना पत्र देकर पुलिस को घटना से अवगत कराया है। थाना प्रभारी निरीक्षक गोपालजी गुप्ता ने बताया कि एक व्यक्ति ने प्रार्थना पत्र देकर बताया है की उसकी बेटी और भतीजी गुरुवार को बाजार से सब्जी ले कर आने की बात कहते हुए घर से निकली। पर शाम तक घर नहीं लौटी। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर संभावित जगहों पर खोजबीन की जा रही है।

पूर्व चौकी प्रभारी व सात सिपाहियों पर पिटाई का आरोप

सोनभद्र। नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित घसिया बस्ती की रहने वाली महिला मुनिया ने चुर्क के तत्कालीन चौकी प्रभारी व सिपाहियों पर बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया है। उसने एससी एसटी न्यायालय में उनके खिलाफ अधिवक्ता रोशन लाल यादव के जरिए वाद दाखिल किया है। न्यायालय ने इस मामल में राबर्ट्सगंज कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक से छह अगस्त को रिपोर्ट तलब किया है। छह को ही इस मामले में सुनवाई भी होगी। वादिनी मुनिया ने दाखिल वाद में आरोप लगाया है कि 12/13 जुलाई की रात्रि करीब दो बजे वह अपने घर में सो रही थी तभी चुर्क चौकी इंचार्ज कमल नयन दूबे व सात सिपाही सभी पुलिस वर्दी में बस्ती में घुस आये। लात से मारकर वादिनी का दरवाजा खोलकर घर के अन्दर घुस आये। वादिनी को सभी घर के अंदर से घसीट कर बाहर लाकर निर्वस्त्र कर लाठी लाठी पीटने लगे। वादिनी के रोने चिल्लाने पर घसिया बस्ती के लोग जग गये और अपने अपने घरों से बाहर मौके पर आ गये। वादिनी को बचाने के लिये आई महिलाओं को भी बेरहमी से पीटा। उसने अन्य तरह के भी आरोप लगाए। इस मामले में न्यायालय ने रिपोर्ट तलब किया है।

चिकित्सा व इंजीनियरिंग में कैरियर बनाने में मिलेगी मदद

प्रयागराज। अपनी प्रमुख छात्रवृत्ति परीक्षा एंथे के गौरवशाली पंद्रह वर्षों को पूरा करते हुए परीक्षण तैयारी सेवाओं में राष्ट्रीय अग्रणी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड एईएसएल ने आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जाम एंथे दो हजार चौबीस के लांच की घोषणा की है। एंथे लोकप्रिय और सबसे अधिक मांग वाली परीक्षा है। जो सातवीं बारहवीं कक्षा के छात्रों को महत्वपूर्ण नकद पुरस्कारों के साथ सौ प्रतिशत तक छात्रवृत्ति अर्जित करने का मौका देती है। जिससे उन्हें चिकित्सा या इंजीनियरिंग में एक सफल करियर के अपने सपनों को हासिल करने में मदद मिलती है। इस वर्ष इसे विशेष और रोमांचक बनाने के लिए इसमें पांच उत्कृष्ट छात्रों के लिए फ्लोरिडा यूएसए में कैनेडी स्पेस सेंटर की पांच दिवसीय पूर्ण खर्च भुगतान यात्रा शामिल की गई है।

गौशाला संचालन में लापरवाही पर प्रधान की पॉवर सीज, सचिव निलंबित किये गये

●बीडीओ माधौगढ़ करेंगे जगनपुरा गौशाला के समूचे प्रकरण की जांच

संवाददाता। उरई, जालौन

गौशाला संचालन में लापरवाही बरतने वाले ग्राम प्रधान जगनपुरा व ग्राम विकास अधिकारी की करतूतों की ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी जिस पर उसकी जांच एसडीएम कोंच ज्योति सिंह ने जगनपुरा की गौशाला में पहुंचकर हकीकत देखी तो ग्रामीणों की शिकायत सच पायी गयी इसके बाद एसडीएम ने अपनी आख्या डीएम को भेज दी थी जिस पर तत्काल प्रभाव से ग्राम प्रधान के पावर सीज करने के साथ ही ग्राम विकास अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उन्हें जालौन ब्लाक कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया और पूरे प्रकरण की जांच माधौगढ़ को सौंप दी गयी। साथ ही नदीगांव बीडीओ से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

गौरतलब हो कि नदीगांव विकासखंड के ग्राम जगनपुरा में गौशाला संचालित होती है। लेकिन गौशाला में गौवंशों को न रखकर उन्हें अन्ना छोड़ दिया जाता था जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने पिछले दिनों जिलाधिकारी से की थी।

ग्रामीणों की शिकायत का डीएम ने संज्ञान लेकर एसडीएम कोंच ज्योति सिंह को जांच करने के निर्देश दिये थे। इसके बाद एसडीएम ने जगनपुरा पहुंचकर गौशाला की हकीकत देखी तो वहां पर एक भी गौवंश नहीं मिला और न ही गौशाला की देखरेख करने वाला कोई कर्मी मौके पर मिला था।

इसके बाद एसडीएम ने अपनी आख्या जिलाधिकारी के पास भेज दी थी। जिस पर शुक्रवार को एक्शन हुआ जिसमें ग्राम प्रधान जगनपुरा के पॉवर सीज करने के साथ ही ग्राम विकास अधिकारी सचिन वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर ब्लाक कार्यालय जालौन में सम्बद्ध कर दिया गया तो वहीं नदीगांव बीडीओ को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अब जगनपुरा गौशाला में बरती गयी लापरवाही की जांच माधौगढ़ बीडीओ करेंगे।

ज्ञातव्य हो कि प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल गौशालाओं के संचालन में लापरवाही बरतने वाले ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी पर कार्यवाही होने से जहां ग्राम प्रधानों में हड़कंप मच गया तो वहीं ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत अधिकारी जिन गांवों में तैनात है और वहां पर गौशाला संचालित होती है वहां की दुर्दशा को ठीक कराने के प्रयासों में जुट गये हैं।

निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठायेंः डॉ. पूजा

जालौन, उरई। मुरली मनोहर राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के तत्वावधान में आयुष आपके द्वार योजना के अंतर्गत ग्राम प्रतापपुरा में आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें स्वास्थ्य परीक्षण के बाद 327 रोगियों को निशुल्क दवा वितरित की गई। आयुष आपके द्वार योजना के अंतर्गत आयोजित स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. पूजा राजपूत ने दीप प्रज्जवलन कर व भगवान धन्वंतरि, मां भारती व स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस दौरान डॉ. पूजा राजपूत ने कहा कि आयुष आपके द्वार योजना के अंतर्गत नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का सर्वाधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्र की जनता को हुआ है।

डीएम-एसपी ने किया जिला कारागार का निरीक्षण

उरई, जालौन। शुक्रवार को जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय व पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार ने संयुक्त रूप से जिला कारागार में विभिन्न बैरकों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बंदियों से वार्ता कर उनकी समस्याएं एवं सुविधाओ के सम्बंध में जानकारी की। उन्होंने निर्देशित किया कि जेल के अंदर कोई भी प्रतिबंधित सामग्री न जाने पाए। कारागार परिसर में साफ सफाई मिलने पर संतोष व्यक्त किया और निर्देशित किया कि इसी प्रकार प्रतिदिन जेल में साफ सफाई होने चाहिए। जिलाधिकारी ने जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि कारागार परिसर में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक एवं गैरकानूनी सामान न पहुंचे इसके लिए विशेष निगरानी रखी जाए। इस दौरान उन्होंने जेल अधीक्षक को सरकार द्वारा बन्दियों को उपलब्ध कराई जाने वाली सारी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि जेल के अन्दर किसी भी दशा मे मोबाइल का प्रवेश न होने पाये इस हेतु रोस्टर बनाकर चेंकिग अभियान चलाकर चेक किया जाये

कारगिल विजय दिवस पर विद्यार्थी परिषद ने निकाली बाइक रैली, शहीदों को किया नमन

संवाददाता। जालौन, उरई

कारगिल विजय दिवस के मौके पर उरई से निकली बाइक रैली का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। स्वागत के बाद रैली को शहीद स्मारक हदरूख के लिए रवाना किया। जहां विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर उरई से बाइक रैली शहीद स्मारक हदरूख के लिए रवाना हुई। तीन मई 1999 से शुरू हुआ कारगिल युद्ध 84 दिन चलने के बाद 26 जुलाई को कारगिल में भारतीय तिरंगा लहराने के बाद समाप्त हुआ था। कारगिल शहीदों की याद व शौर्यगाथा की देश 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर उरई से पूर्व सैनिक वेलफेयर एशोसियेशन व एनसीसी के संयुक्त तत्वावधान में बाइक रैली निकाली गई। उरई से शुरू हुई रैली का नगर के प्रवेश द्वार देवनगर चौराहे पर पहुंचने पर कई संगठनों ने जोरदार स्वागत किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने आर्मी के कर्नल डीएस चौहान एवं आर्मी के जवानों को माला पहना कर एवं परिषद की पुस्तक ध्येय यात्रा भेंट की। जिसमें प्रमुख रूप से प्रांत सोशल मीडिया सह संयोजक सत्यम याज्ञिक, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य आदित्य हृदय, बजरंग दल नगर संयोजक मानवेंद्र सिंह परिहार, पूर्व प्रांत कार्यकारिणी सदस्य निखिल बाथम, हरिओम पटेल, अमन पटेल, अनूप दीक्षित आदि मौजूद रहे।

उधर, हदरूख में शहीद स्मारक पर बाइक रैली का स्वागत किया गया। जहां कर्नल देवेंद्र सिंह चौहान, दीपक भट्ट, कर्नल दुष्यंत सिंह चौहान कमांडेंट ऑफिसर एनसीसी बटालियन 58 उरई, कर्नल दीपक भट्ट स्टेशन ऑफिसर झांसी हेडक्वार्टर आदि ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वीर गाथा से अवगत कराया और कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले वीर योद्धाओं की शौर्य गाथाओं से परिचित कराया।

किसान की बाइक में रखी एक लाख की नकदी चोरी

जालौन, उरई। बैंक से रुपये निकालकर घर जा रहे किसान की बाइक में रखे लगभग एक लाख रुपये अज्ञात चोरों ने उड़ाए। पीड़ित किसान ने मामले की तहरीर कोतवाली में दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। रेंढ़र थाना क्षेत्र के ग्राम छिरिया खुर्द निवासी किसान राजकुंमार ने पुलिस को बताया कि 24 जुलाई को वह बाइक से जालौन आए थे। कुछ कामकाज निपटाकर उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से घर के जरूरी काम के लिए एक लाख रुपये निकाले और चार हजार रुपये उनके पास पहले से ही थे। रुपये निकालकर उन्होंने बाइक की डिग्गी में रख लिए। जिसके बाद वह वापस अपने गांव बाइक से जाने लगे। बंगरा रोड पर छहपुला के आगे उन्हें लघुशंका की आवश्कता महसूस हुई। उन्होंने सड़क किनारे बाइक खड़ी कर दी और लघुशंका करने लगे। इसी दौरान अज्ञात चोर ने उनकी बाइक की डिग्गी का ताला खोलकर उसमें रखे रुपये चोरी कर लिए। जब वह वापस आए तो डिग्गी खुली थी और रुपये गायब थे।

बड़े बकायदारों पर शिकंजा, शुरू हुआ कनेक्शन काटो अभियान

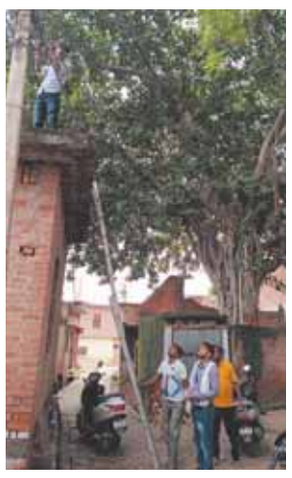

कालपी, जालौन। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के निर्देश के अनुरूप विद्युत विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की टीम राजस्व वसूली के लिये नगरीय क्षेत्र में उतर पड़ी। विभागीय टीम के द्वारा कामर्शियल तथा बड़े बकायेदार उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने वसूली करने का अभियान चलाया गया। उपखंड अधिकारी आदर्श राज, अवर अभियंता जितेंद्र कुमार, टीजीटू अभिषेक कुमार की टीम एकत्रित हो गई। टीम के द्वारा मिर्जा मंडी दमदमा, हरीगंज, भट्टीपुरा, जुलैहटी बाईपास रोड आदि मुहल्लों में प्रतिष्ठानों तथा घर घर जाकर बिजली चैकिंग की गई। एसडीओ ने बताया कि विद्युत देय राशि की वसूली करने के लिए विभाग गंभीर है। उन्होंने कहा कि पावर कारपोरेशन के निर्देश पर 5 हजार से ज्यादा के बड़े बकायदारों पर कार्यवाही की जा रही है।

उन्होंने बताया कि विभागीय टीमों ने चिन्हित बड़े बकायेदारों के आवासों तथा प्रतिष्ठानों में चेकिंग की तथा बकाया विद्युत देय राशि को जमा करने के लिए अभियान चलाया। उपखंड अधिकारी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि अपने-अपने विद्युत बिलों की धनराशि को समय से जमा करके अनावश्यक परेशानी से बचें।

हाइवे पर हुई पांच गौवंशों की मौत पर हिन्दू संगठनों में दिखा आक्रोश

कालपी, जालौन। शुक्रवार सुबह हाईवे पर गौवंशों की मौत पर हिन्दू संगठन आक्रोश में है। इसके लिए उन्होंने एसडीएम को पत्र सौंपा है जिसमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है अन्यथा की स्थित में आंदोलन की चेतावनी भी दी है। गौवंशों की सुरक्षा और संरक्षण शासन की प्राथमिकता में शामिल हैं जिसके लिए नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में गौशालाओं की व्यवस्था की गई है लेकिन इसके बाद भी गौवंश आवारा हालत में हाईवे के साथ खेतों तक देखे जा सकते हैं जबकि प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने प्रशासनिक जिम्मेदारों गौवंशों के सड़क पर मौजूद न रहने के निर्देश दिए हैं लेकिन इसके बाद भी व्यवस्था बदली नही है जबकि हाईवे से तहसील से लेकर लखनऊ तक के प्रशासनिक जिम्मेदार गुजरते है लेकिन किसी ने हाईवे पर आवारा गौवंशों की मौजूदगी का संज्ञान नही लिया है। इसी के चलते आये दिन गौवंशों की हादसों में दर्दनाक मौत हो जाती है और इसी कड़ी में शुक्रवार सुबह अज्ञात वाहन की टक्कर से जोल्हूपुर क्षेत्र स्थित हाईवे पर गौवंशों की मौत हो गई है। विश्व हिंदू परिषद के दीपक शर्मा कहते हैं कि दो दिनों में 5 गौवंशों की हादसों में मौत हुई है और इसी नाराज हिन्दू। संगठन के लोगों ने शुक्रवार को एसडीएम सुशील कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा है जिसमें कहा गया है कि पालिका परिषद द्वारा गौशाला संचालित किये जाने के बाद भी नगर सीमा स्थित हाईवे और नगर में भी बडी संख्या में आवारा गौवंश मौजूद रहते हैं इसलिये इनका सँरक्षण कराया जाए।

बेंजामिन नेतनयाहू
समर्थन पाने के प्रयास

बेंजामिन नेतनयाहू ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए गाजा युद्ध के लिए समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनयाहू ने कांग्रेस में भाषण देते हुए अमेरिका से एकजुटता का आह्वान किया है। हालांकि, उनकी अपने देश में लोकप्रियता घट रही है और विरोध बढ़ रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस को संबोधित करते हुए नेतनयाहू ने अमेरिकन विधि-निर्माताओं का आह्वान किया कि वे गाजा में जारी सैनिक कार्रवाइयों का समर्थन करें। बढ़ती हिंसा तथा हताहत सिविलियनों की संख्या बढ़ने की पृष्ठभूमि में दिया गया यह भाषण नेतनयाहू की प्रतिबद्धता रेखांकित करता है कि वे इसराइल के सर्वाधिक शक्तिशाली सहयोगी का अडिग समर्थन चाहते हैं। उन्होंने जोर दिया कि इसराइल को गाजा में सक्रिय चरमपंथी समूहों, खासकर हमास से अपने अस्तित्व पर खतरा है। प्रधानमंत्री नेतनयाहू ने सैनिक कार्रवाई को इसराइली समुदायों को प्रभावित करने वाले राकेट हमलों तथा वर्तमान समय में जारी आतंकी हमलों की आवश्यक प्रतिक्रिया बताया। लेकिन नेतनयाहू के भाषण में फिलिस्तीनी क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघनों पर बढ़ती अंतरराष्ट्रीय चिन्ताओं को संबोधित नहीं किया गया था। 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' तथा 'ह्यूमन राइट्स वाच' समेत अनेक मानवाधिकार संगठनों ने इन क्षेत्रों में अनेक मानवाधिकार उल्लंघन उजागर किए हैं।

गाजा में मानवीय संकट नाकेबंदी के कारण और गंभीर हुआ है जिससे लोगों और वस्तुओं का आवागमन अत्यधिक सीमित हो गया है। इससे भोजन, पानी और चिकित्सा देखभाल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कमी

हो गई है। गाजा में वर्तमान आक्रमण 250 दिन से अधिक समय से जारी है जिसमें बड़े पैमाने पर मौतें और विनाश हुआ है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इसराइली हमलों में 34,000 से अधिक लोग मारे गए हैं तथा 77,000 से अधिक घायल हुए हैं। मृतकों में लगभग 72 प्रतिशत महिलायें और बच्चे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने कहा है कि 'हर दस मिनट में' गाजा में कोई बच्चा मारा जाता है या घायल होता है। इसराइल की कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन तथा सामूहिक दंड है जिसमें निरपराध सिविलियन जनसंख्या को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इससे मानवीय संकट गहरा रहा है। इसराइल के मुख्य सहयोगी के रूप में अमेरिका इसराइल-फिलिस्तीन टकराव की दिशा तय करने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इस समर्थन से अमेरिका की आलोचना हो रही है क्योंकि वह शांति तथा मानवाधिकारों को बढ़ावा देने में अपने प्रभाव का प्रयोग कर सकता है। अमेरिका द्वारा उपलब्ध कराए हथियारों का प्रयोग इसराइल फिलिस्तीन में सिविलियनों के खिलाफ कर रहा है जो भयानक समय का सामना कर रहे हैं। अमेरिकी जनता तथा कांग्रेस के कुछ सदस्यों में ज्यादा संतुलित दृष्टिकोण की पैरोकारी की जा रही है। अमेरिका से अपील की जा रही है कि वह मानवाधिकार उल्लंघनों पर कठोर दृष्टिकोण अपनाते हुए टकराव का टिकाऊ व न्यायोचित समाधान निकालने के राजनयिक प्रयासों का समर्थन करे। दोनों पक्षों के वैध सरोकारों को संबोधित करने वाले समावेशी व समग्र दृष्टिकोण से ही टिकाऊ शांति संभव होगी। इस क्षेत्र में न्याय व मानवाधिकारों की पैरोकारी की अमेरिका की नैतिक एवं रणनीतिक जिम्मेदारी है। अमेरिका बेंजामिन नेतनयाहू से कह सकता है कि वे गाजा पर संयुक्त राष्ट्रसंघ के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सिविलियन ठिकानों पर बमबारी बंद करें ताकि हताहत सिविलियनों की संख्या न्यूनतम की जा सके। इस प्रकार अमेरिका इस क्षेत्र में स्थाई शांति की दिशा में केन्द्रीय भूमिका निभा सकता है।

दीर्घकालीन विकास को लक्षित बजट

केन्द्रीय बजट 2024-25 दीर्घकालीन विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि करता है। भारत तेज विकास के लिए अपनी असाधारण क्षमता का लाभ उठाने की स्थिति में है।

दीपक सूद
(लेखक, एसोचैम के महासचिव हैं)

केंद्रीय बजट 2024-25 दीर्घकालीन विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि करता है। भारत तेज विकास के लिए अपनी असाधारण क्षमता का लाभ उठाने की स्थिति में है। भारत की आर्थिक शक्ति मजबूत करने की दिशा में लक्षित 2024-25 वित्त वर्ष के केन्द्रीय बजट में प्रगतिशील सुधारों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस बजट में एमएसएमई, ई-कामर्स व स्टार्टअप की प्रगति के अनेक प्राविधान किए गए हैं। इससे 'विकसित भारत' की दिशा में देश के रोडमैप के लिए अतिरिक्त समर्थन जुटाया गया है। वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने गरीब, महिला, युवा और किसान को सशक्त बनाने के लिए अनेक प्राविधान इस बजट में किए हैं। बजट में उनके द्वारा की गई घोषणायें एकदम सही समय पर सामने आई हैं। इनसे भारतीय अर्थव्यवस्था को 'अमृत काल' में आगे बढ़ाने तथा नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की प्रतिबद्धता प्रकट की गई है। इन प्रयासों से भारत का कद उभरती विश्व व्यवस्था में और आगे बढ़ेगा। पिछले दस साल में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में दसवें नंबर की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने लगभग 60 बाद पहली बार लगातार मिले अपने तीसरे कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की प्रतिज्ञा की है। मोदी की तीसरी सरकार का पहला बजट इस दिशा में बढ़ने की प्रतिबद्धता प्रकट करता है।

इस बजट में एमएसएमई को और मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं। बजट में उचित ही औद्योगिक पिरामिड के सबसे निचले स्तर पर मौजूद एमएसएमई को आगे बढ़ाने के प्रयास शामिल हैं जिसमें उसे आसानी से मिलने वाले कर्जों की व्यवस्था की गई है। भातर में वर्तमान समय में 633.9 लाख एमएसएमई हैं। इनमें से 99 प्रतिशत सूक्ष्म उद्यमों की परिभाषा में आते हैं जिनकी संख्या 630.5 लाख है। 10 मिलियन रुपयों तक निवेश वाले सूक्ष्म उद्यमों को छोटे या मझोले उद्यम न बन पाने के पीछे एक प्रमुख कारण उनकी औपचारिक कर्ज तक पहुंच न होना था। 'मुद्रा लोन' की धनराशि दूनी करने तथा नई 'सिडबी' शाखायें स्थापित करने के माध्यम से ये संगठन अब आसानी से कर्ज तक पहुंच सकेंगे।

अन्य कदमों, जैसे 'मैनडेटरी ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्कांउटिंग सिस्टम' से तरलता को बढ़ावा मिला है, जबकि औद्योगिक पार्क एमएसएमई को बहु-प्रतीक्षित डिजिटल समर्थन प्रदान करेंगे जो आमतौर से उनकी पहुंच में नहीं था। इसके साथ ही एमएसएमई के लिएनई कर्ज गारंटी योजनाओं ने बिना बंधक या तीसरे पक्ष की गारंटी के कर्जों की उपलब्धता सहज की है। इससे छोटे बिजनेस मालिकों पर वित्तीय बोझ कम होगा तथा उद्यामिता को बढ़ावा मिलेगा। इस सकारात्मक समर्थन से इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति छोड़ने का विश्वास पैदा होगा और वह 2047 का लक्ष्य बना कर तेजी से आगे बढ़ेगा। इस बजट में सरकार ने कौशल संवर्धन तथा रोजगार सृजन को केन्द्र में रखा है। इस बजट के माध्यम से सरकार ने देश के नौजवानों में कौशल संवर्धन तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की आवश्यकता पर सकारात्मक प्रतिक्रिया की है। कौशल संवर्धन पर लगातार जोर देने से प्रशिक्षण संस्थानों तथा बड़े निगमों को पेशेवर रूप से प्रशिक्षित श्रमशक्ति तैयार करने के दृष्टिकोण से सहभागिता में सहायता मिलेगी। यह प्रशिक्षित श्रमशक्ति आसानी से बड़े एमएसएमई परिवेश में समाहित होगी, जबकि वर्तमान समय में इसे अक्सर प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए पैसे की कमी अनुभव होती है। लेकिन योजनाओं का समुचित क्रियान्वयन महत्वपूर्ण होगा ताकि रोजगार सृजन के प्रयास सही दिशा में आगे बढ़ सकें।

मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के इस बजट से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के उल्लेखनीय प्रयास किए हैं। हालांकि, भारत का पिछले वर्षों में तेजी से शहरीकरण हुआ है, पर इसके बावजूद देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था बड़ी संख्या में जनसंख्या की आजीविका का आधार बनी हुई है। मोदी सरकार पिछले दस साल से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के प्रयास कर रही है। इस प्रकार वर्तमान बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सरकार की ओर से मिलने वाले समर्थन का उद्देश्य इस क्षेत्र को मजबूत करना है जो देश की लगातार आर्थिक वृद्धि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। बजट 2024 में कुछ महत्वपूर्ण घोषणायें की गई हैं जिनका उद्देश्य अनाजों व तिलहनों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा इनका उत्पादन बढ़ाना है। बजट में उठाए गए कदमों से नए आर्थिक क्लस्टर बनाने में व्यापक रूप से सहायता मिलेगी जो अर्थव्यवस्था का निरंतर विकास सुनिश्चित करेंगे। बजट का उद्देश्य एक करोड़ किसानों को 'प्राकृतिक खेती' में प्रशिक्षण देना है। इसके साथ ही किसानों को मार्केटिंग, प्रमाणन व ब्रांडिंग, आर्गेनिक फार्मिंग, आदि क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण देने की योजना है। इन सबसे किसानों की अर्थव्यवस्था तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत गति मिलेगी। सरकार ने भोजन की उपलब्धता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को संबोधित करने का लक्ष्य बनाया है। इससे सरकार का ग्रामीण परिस्थितिकी में दीर्घकालीन व टिकाऊ विकास का दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। सरकार ने इस बजट के माध्यम से स्टार्टअप और ई-कामर्स को आगे बढ़ाने के लिए स्पष्ट कदम उठाए हैं।

बजट में 'एंजल टैक्स' समाप्त करने की घोषणा की गई है। इससे पूरे देश के स्टार्टअप सिस्टम में खुशी की लहर दौड़ गई है। 2012 में लागू किए गए 'एंजल टैक्स' को गैर पंजीकृत कंपनियों द्वारा भारतीय निवेशकों को जारी किए गए शेयरों से एकत्रित पूंजी पर लगाया जाता था, यदि शेयरों का मूल्य कंपनी की 'फेयर मार्केट वैल्यू'-एफएमवी से अधिक हो। इसी प्रकार ई-कामर्स का प्रयोग करने वाले व्यापारियों और कारीगरों को इस बजट में राहत दी गई है। इन पर टीडीएस न केवल घटाया गया है, बल्कि टीडीएस विलंब से जमा करने को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है। इससे वर्तमान समय में ई-कामर्स निर्यात जो 2 बिलियन डालर है, उसके 2030 तक 350 बिलियन डालर होने की उम्मीद है। कस्टम ड्यूटी में परिवर्तन से सरकार का इरादा उन कारीगरों और व्यापारियों को सहायता देना है जो अपनी चीजें वेबसाइटों से बेचते हैं।

यह कदम 'मेक इन इंडिया' रणनीति के अनुरूप है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के कारण भारत की ऊर्जा आवश्यकतायें तेजी से बढ़ रही हैं। छोटे नाभिकीय रिएक्टरों में निजी निवेश प्रोत्साहन तथा नाभिकीय ऊर्जा के नए रूपों में आरएंडडी को बढ़ावा देने के माध्यम से बजट भारत की 'ऊर्जा सुरक्षा' रणनीति सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। विभिन्न क्लस्टरों में नियमित 'ऊर्जा आडिट' के माध्यम से बड़े वाणिज्यिक थर्मल प्लांटों की स्थापना तथा भंडारण नीति को गति देकर बजट भारत को बढ़ती ऊर्जा मांग से निपटने का अवसर देता है। हालांकि, हमारे 'हरित ऊर्जा' लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी हैं और 'हरित ईंधनों' की दिशा में परिवर्तन के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है।

भूमि रिकार्डों का 'डिजिटलीकरण' बजट में प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रगति पर संभवत: सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। हमारी भूमि के विशाल हिस्से, खासकर ग्रामीण भारत में अक्सर समुचित दस्तावेजीकरण न होने के कारण विवादों को जन्म देते हैं। यह बड़ी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की बड़ी बाधा है। पूरे भारत में भूमि रिकार्डों के डिजिटलकरण से सरकार विधि व्यवस्था में अनेक मामलों में बिचौलियों को समाप्त करने में सफल होगी तथा भूमि विवादों की संख्या में कमी आएगी। इस प्रकार कुल मिला कर केन्द्रीय बजट 2024-25 दीर्घकालीन टिकाऊ वृद्धि के लिए सरकार की प्रतिबद्धता मजबूत करता है। रणनीतिक निवेशों तथा अग्रगामी नीतियों से भारत वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सफल होगा तथा अपना सामाजिक-आर्थिक विकास करेगा। 'विकसित भारत' का रास्ता अनेक चुनौतियों से भरा है, लेकिन टिकाऊ दृष्टिकोण व प्रगतिशील नीतिगत समर्थन से हम यह सपना पूरा कर सकते हैं।

बजट के द्वारा राजकोषीय व रोजगार संतुलन

बजट राजकोषीय अनुशासन के मार्ग पर चल रहा है, भले ही पीएम मोदी गठबंधन सरकार की अगुआई कर रहे हों।

कुमारदीप बनर्जी
(लेखिक नीति विश्लेषक हैं)

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ग्यारहवां पूर्ण-कालिक बजट राजकोषीय अनुशासन के मार्ग पर चल रहा है, भले ही वह गठबंधन सरकार की अगुआई कर रहे हों। 4 जून के आश्चर्यजनक नतीजों ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके करियर में शायद पहली बार गठबंधन सरकार दिलाई, लेकिन इसके बावजूद उनके बजट प्रस्तावों को रोका नहीं जा सका, जिसमें पृष्ठभूमि में ठोस अर्थशास्त्र के साथ-साथ राजनीतिक भी शामिल था।

बजट से पहले, कई लोगों ने उम्मीद की थी कि वित्त अधिनियम इस साल के अंत में होने वाले हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के राज्य चुनावों को ध्यान में रखते हुए लोकलुभावन होगा। हालांकि निर्मला सीतारमण की जेब से जो निकला, वह एक ऐसा दस्तावेज था, जिसने लोकलुभावन मांगों के आगे झुकने के बिना दीर्घकालिक विकास और सभ्य बुनियादी ढाँचे के खर्च के मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चुना। सरकार द्वारा उजागर किया गया मुख्य विषय रोजगार है। देश के युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के सृजन के लिए घोषित योजनाओं की व्यवहार्यता के बारे में बजट के बाद के विश्लेषण में सवाल उठाए गए हैं।

भारत की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों में प्रति वर्ष लाखों युवाओं को सरकारी वजीफा देने का वादा करने वाली प्रशिक्षु योजना तभी गेम चेंजर साबित हो सकती है, जब इन युवा प्रशिक्षुओं को ध्यानपूर्वक प्रशिक्षित किया जाए, ताकि उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें औपचारिक रूप से नौकरी मिल सके। अपेक्षाकृत अकुशल कार्यबल की प्रचुर उपलब्धता के बारे में गंभीर चिंताएँ हैं, जो बिना कोई सार्थक कौशल सीखे बड़े

कार्यालयों में काम करते रहते हैं।

ईपीएफओ से जुड़ी नई नौकरी प्रोत्साहन योजना के बारे में भी इसी तरह के सवाल उठाए गए हैं, जिसके कई पहलू हैं, जो संभवत: एक सुविचारित नीति को अंधेरे कोने में धकेल रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि नीतिगत धक्का मुख्य रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत अधिक युवाओं को औपचारिक मानक कार्यबल के भीतर लाना और उनमें शुरू से ही वित्तीय साक्षरता अनुशासन पैदा करना है।

हालांकि, यह वित्तीय साक्षरता तब धराशायी हो जाती है जब कोई सट्टा इक्विटी बाजार में निवेश करने वाले किसी भी निवेशक के लिए कर संरचनाओं में किए गए बदलावों को देखता है। पूंजीगत लाभ कर की बढ़ी हुई दर और नई आयकर व्यवस्था को बढ़ावा देना, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के विपरीत प्रतीत होता है, सरकार चाहती है कि युवा पहले महीने के वेतन सब्सिडी के रूप में 15,000 रुपये का पूरा लाभ उठाने का बीड़ा उठाएं। पहले की कर व्यवस्थाओं ने औपचारिक नौकरी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले किसी भी युवा के लिए वित्तीय जिम्मेदारी की भावना पैदा की, जिसमें कई लोगों ने भविष्य में कर छूट का दावा करने और बचत करने के साधन के रूप में कम से कम एक उत्पाद चुना। इसने उन्हें कामकाजी पेशेवरों के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान एक लंबे वित्तीय अनुशासन पथ पर आगे बढ़ाया, जो अब धीरे-धीरे आसान होता दिख रहा है। सरकार के पास प्रति-तर्क यह हो सकता है कि वे चाहते हैं कि उपभोक्ता अर्थव्यवस्था पहले बढ़े, जिसका नेतृत्व युवा करें, जो अपनी नई नौकरियों में मिलने वाले मासिक वेतन से खाद्य पदार्थों, मनोरंजन आदि पर खर्च करने के लिए अधिक इच्छुक हो सकते हैं। हालांकि, यह उन्हें बचत की आदत डालने से रोकता है, जो बारिश के दिनों या कोविड जैसे संकटों के दौरान उपयोगी होती है। हां, सरकार ने राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखने में अच्छा काम किया, उम्मीद से बेहतर जीडीपी वृद्धि और केंद्रीय बैंक से भारी लाभांश भुगतान से उत्साहित। खाद्य पदार्थों को छोड़कर कुल मुद्रास्फीति भी सहनीय स्तरों के भीतर है, जिससे सरकार को कल्याणकारी परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए एक सहारा मिल रहा है, जो उसे लगता है कि आवश्यक है। केंद्रीय बजट 24-25 असंतुष्ट मतदाताओं को वापस लुभाने का एक प्रयास है। 4 जून के नतीजों से भाजपा ने जो सबक लिया है, वह यह है कि युवा विशाल मंदिरों, कुछ स्मार्ट चमचमाती ट्रेनों और अपने मेड इन इंडिया फोन में सस्ते मोबाइल डेटा को लेकर उत्साहित हैं।

लेकिन वे तेजी से पैसा कमाने, एक आकर्षक व्यवसाय करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, जो उनकी महत्वाकांक्षी जीवन शैली को आगे बढ़ाए। फिर गठबंधन की राजनीति के दबाव और खींचतान है, जिसमें एनडीए के दो सहयोगी टीडीपी और जेडी(यू) अपने मुख्य निर्वाचन क्षेत्रों की सेवा करने के लिए अपनी इच्छा सूची रखते हैं। एक दीर्घकालिक पासा फेंका गया है, शायद एनडीए 3.0 ने इस बजट के साथ गोल्डीलॉक्स संतुलन हासिल कर लिया है।

आप की बात

कारगिल युद्ध की स्मृति

कारगिल युद्ध की 25वीं वर्षगांठ पर हम शहीदों को नमन कर रहे हैं। इस युद्ध ने भारत को कई सबक दिए हैं। पहले जहां सैनिकों के पांच पर्याप्त संसाधन, जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट और बर्फ में पहनने वाले जूते नहीं थे, वहीं वे आज सबको उपलब्ध हैं। 25 साल में सेना का कायापलट हो गया है और अब उसके पास अनेक आधुनिक संसाधन मौजूद हैं। फिर भी देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों के लिए निरंतर नई तकनीकों और मजबूत गुप्तचर तंत्र को अद्यतन बनाने की आवश्यकता है। सेना के भीतर घुसे विदेशी जासूसों या उनको गुप्त जानकारी देने वालों की पहचान कर कठोर दंड देने की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई तकनीक का उपयोग पूरे देश की सीमा पर ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि घुसपैठियों का स्वचालित ढंग से सफाया जा जाए। इस्राइल ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए तकनीक का व्यापक विकास कर अनेक ऐसी तकनीकें भारत को भी सौंपी हैं। इनसे उन दुर्गम इलाकों में भी सटीक निगरानी संभव होगी जहां सैनिकों को पहुंचने व गश्त करने में कठिनाई होती है। लेकिन इस्राइल पर हुए भयंकरतम आतंकी हमले से स्पष्ट है कि केवल तकनीक पर निर्भर रहना ठीक नहीं होगा। कारगिल शहीदों को सही श्रद्धांजलि सीमाओं की सुरक्षा को अभेद्य बनाना होगा।

– **विभूति बुपक्या,** खाचरोद

संघ की बढ़ती स्वीकार्यता

केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष शपथ पत्र देकर कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में केंद्रीय कर्मचारियों के शामिल होने पर अब केंद्र को कोई आपत्ति नहीं है। संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है एवं अन्य संगठनों की तरह इसकी गतिविधियों में याचिकाकर्ता को शामिल होने का पूरा अधिकार है। केंद्र सरकार ने वर्ष 1966 से संघ की गतिविधियों को राजनीतिक मानकर केंद्रीय कर्मचारियों को इसमें शामिल होने पर प्रतिबंध लगा रखा था। अब यह प्रतिबंध हटा लिया गया है। अपनी प्रखर व स्पष्ट राष्ट्रवादी विचारधारा के कारण आरएसएस कांग्रेस समेत अनेक ऐसे राजनीतिक दलों के निशाने पर रहा है जो मुस्लिम तुष्टीकरण को अपने वोटबैंक का माध्यम बना कर जनता को संघ के खिलाफ भड़काते रहे हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने भारत-चीन युद्ध के समय संघ की प्रशंसनीय भूमिका को देखते हुए उसे गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। संघ के स्वयंसेवक देश में अनेक आपदाओं के समय राहत कार्यों से अपनी पहचान बना चुके हैं। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को संघ के कार्यक्रमों में भाग लेने पर प्रतिबंध का कोई औचित्य नहीं था।

– **मनमोहन राजावत,** शाजापुर

परीक्षा व्यवस्था

सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा को निरस्त नहीं किया, हालांकि उसने परीक्षा में हुई गड़बड़ी को स्वीकार किया है। पेपर लीक के खिलाफ सख्त कानून अलग-अलग राज्य बना रहे हैं। इसके बजाय केंद्र को ही सभी बड़ी परीक्षाओं के लिए पूरे देश में एक कानून लागू करना चाहिए। पेपर लीक व किसी कोचिंग सेंटर के कई छात्रों का अत्यधिक नंबर लाने जैसी विसंगतियों के पुख्ता सबूत हैं। इन विकृतियों को देखते हुए पेपर सेट करने व उनको परीक्षा केन्द्रों तक पहुंचाने की एकदम नई व्यवस्था पर विचार होना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो एक ही विषय के लिए कई तरह के प्रश्न पत्र बनाएं और यह प्रश्न पत्र परीक्षा से एक घंटे पूर्व सभी परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन पहुंचाया जाए। इससे परीक्षा में मानवीय दखल पूरी तरह खत्म होने से कोई हेराफेरी संभव नहीं होगी। यदि परीक्षा परिणाम एक सप्ताह में जारी हो जाएं तो शिक्षा माफिया कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। इससे परीक्षाएं पूरी तरह पारदर्शी होगी। इसके साथ ही इंटरव्यू में भी पक्षपात समाप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए। परीक्षा व्यवस्था में परिवर्तन के सुझावों पर सभी पक्षों की राय लेकर केन्द्र व राज्यों के स्तर पर प्रभावशाली कदम उठने चाहिए।

सुभाष बुडावन वाला, रतलाम

बाढ़ की विभीषिका

बाढ़ की विभीषिका अनेक स्थानों पर दिख रही है। फिर चाहे वह मुंबई, पूना, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल, यूपी और बिहार हो, हर बाढ़ से मुसीबत आ रही है। पानी घरों में घुस रहा है, सड़कें डूब रही हैं, घरों में दरारें पड़ रही हैं तो कहीं पुल और पहाड़ दरक रहे हैं। यदि बरसाती पानी की संग्रहण व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाए तो कभी पानी की कमी नहीं होगी। लेकिन वर्षा जल के प्राकृतिक संरक्षक, वर्षा को बुलाने वाले तथा भूमिगत जल भंडारों के भरने में सहायक हरे-भरे जंगल कट रहे हैं और हरियाली उजड़ रही है। दूसरी ओर सीमेंट- कंक्रीट के नए-नए जंगल उभर रहे हैं जो पानी के प्राकृतिक बहाव में बाधा डालने के साथ ही बरसाती पानी को भूमिगत जल भंडारों तक पहुंचने से रोकते हैं। इससे सरकारों और जनता को पौधरोपण की याद आती है पर उनकी रखवाली भगवान् भरोसे छोड़ दी जाती है। शहरों में लगे पेड़ों की जड़ें चारों ओर पत्थरों, डामर या कंक्रीट से घिर जाती हैं और पेड़ों की अकाल मौत का कारण बनती हैं। नगर नियोजन, वृक्षारोपण व हरियाली की सुरक्षा में समन्वय बनाना जरूरी हो गया है।

– **शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

मंडलायुक्त ने की कानून, सुरक्षा व राजस्व की समीक्षा

संवाददाता। अयोध्या

मण्डलायुक्त गौरव दयाल की अध्यक्षता में शासन के महत्वपूर्ण प्राथमिकता कार्यक्रमों मुख्यमंत्री डैशबोर्ड मंडल अनुश्रवण (विकास कार्यो से सम्बंधित) की माह जून 2024 की प्रगति रिपोर्ट पर मंडलीय समीक्षा बैठक का आयोजन आयुक्त कार्यालय सभाकक्ष में आहूत की गयी। मण्डलायुक्त ने मण्डल के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने-अपने जनपदों के कार्यो का नियमित समीक्षा करते हुए समय-समय पर डाटा फीड कराएं और उसका अनुश्रवण करें, जिससे जिले की रैंकिंग के साथ साथ मण्डल की रैंकिंग में सुधार आ सकें।

उन्होंने ऊर्जा विभाग के खराब ट्रांसफार्मर की शिकायत, दैनिक विद्युत आपूर्ति घंटे ग्रामीण/शहरी, विद्युत बिलों में सुधार हेतु आवेदन बिन्दुओं का समीक्षा करते हुये जिलाधिकारी अमेठी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में विद्युत सम्बंधी उपकरण की आपूर्ति न होने के कारण समस्या बनी रहती है, जिस पर मंडलायुक्त ने मुख्य अभियन्ता पावर कार्पोरेशन को निर्देश दिये कि मण्डल को प्राप्त होने वाले विद्युत सम्बंधी उपकरणों को जिले की आवश्यकता अनुसार सीधे जिलों के स्टोर में भेजे। इसके साथ ही जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर व अमेठी द्वारा गलत विद्युत बिलों की समस्या से अवगत कराया गया जिस पर मण्डलायुक्त ने कहा कि एमडी पावर कार्पोरेशन से इस विषय पर पत्राचार कराते हुए शीघ्र गलत बिलों का निस्तारण सुनिश्चित करायें।

इसके साथ ही मुख्य अभियन्ता पावर कार्पोरेशन को निर्देश दिये कि मण्डल के सभी जिलों के अधिशाषी अभियन्ताओं को पंचायत व ब्लाक स्तर पर कैम्प का आयोजन कर गलत विद्युत बिल की शिकायतों पर तत्काल ठीक करवाने के निर्देश दिये। इसके साथ ही जिन मीटर रीडर द्वारा गलत बिल बनाये जा रहे है उन पर कार्यवाही करते हुये एफआईआर दर्ज करायें और इसका अनुश्रवण जिलाधिकारी अपने स्तर से सुनिश्चित करें।

मण्डलायुक्त ने कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए सभी जिलाधिकारियों से कहा कि फसल बीमाओं का जनपद स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार कराएं और भवन निर्माण के जो कार्य चल रहे है या पूर्ण हो चुके है उसके फिनीशिंग कार्य व गुणवत्ता का भौतिक निरीक्षण अवश्य करा लें।

उन्होंने समीक्षा के दौरान बताया कि चिकित्सा विभाग में एम्बुलेंस के फर्जी रिपोर्टिंग व बिल की शिकायत, सिंचाई व विद्युत विभाग में अनियमितता की शिकायत का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इसके साथ ही जिलाधिकारी गण व अपर निदेशक स्वास्थ्य को निर्देश देते हुए कहा कि जनपद में अभियान चलाकर चल रहे झोलाछाप डॉक्टरों व उनकी क्लीनिक पर कार्यवाही करें।

मण्डलायुक्त ने विकास कार्यो की समीक्षा के दौरान एकीकृत बागवानी विकास मिशन, पर ड्राप मोर क्राप-माईक्रोईरीगेशन, विद्युत बिलों के सुधार, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम कुसुम, बीज डीबीटी, डे0एन0आर0एल0एम0 बैंक क्रेडिट लिंकेज व बी0सी0 सखी, आवास योजना, मनरेगा, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, एम्बुलेंस 102/108, टेली रेडियोलॉजी, सिटी स्कैन सेवाएं, सहकारी दुग्ध समिति, दिव्यांग पेंशन, जलजीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, आपरेशन कायाकल्प, पशु टीकाकरण, शादी अनुदान योजना, मत्स्य उत्पादन आदि शासन की मुख्य बिन्दुओं पर समीक्षा की।

राजस्व की वसूली में तेजी लायें व लंबित वादों का निस्तारण करें अधिकारी: कमिश्नर

संवाददाता। गोंडा

विभागीय अधिकारी कर-करेत्तर, राजस्व की वसूली में तेजी लायें। जिला प्रशासन का सहयोग लेकर वसूली एवं प्रवर्तन कार्य करें, ताकि समय से वार्षिक लक्ष्य समय से पूरा किया जा सकें। उक्त निर्देश मण्डलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने विभागीय अधिकारियों को दिये है।

समीक्षा बैठक में आयुक्त ने कहा कि वसूली के लिए क्षेत्र में जाने पर संबंधित एसडीएम तथा पुलिस को अवश्य सूचित करें, ताकि मौके पर कानून व्यवस्था किसी प्रकार प्रभावित न हों। विद्युत विभाग गांव-गांव कैंप लगाकर बिजली बिल की वसूली करायें तथा उपभोक्ता का बिल गलत होने पर उसे सही करें। उन्होने निर्देश दिया कि किसी भी मामले में एक पक्षीय निर्णय न लें तथा दोनों पक्षों को समान रूप से सुनवाई का मौका दें। स्टाम्प वादों के निस्तारण में कानूनसम्मत आदेश पालन करने का निर्देश देते हुए उन्होने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आर्डर की जॉच अवश्य की जाय। आयुक्त ने कहा कि सभी अधिकारी प्रवर्तन कार्य में तेजी लाकर लक्ष्य के सापेक्ष वसूली करायें। शासन ने जो लक्ष्य दिया है उसके सापेक्ष प्रतिमाह वसूली करायें। इसमें कोई विभाग लापरवाही न बरते अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। बड़े-बड़े बकायेदारों से आरसी की वसूली तहसील प्रशासन के सहयोग से कराई जाए।

मण्डलायुक्त ने कहा कि पांच वर्ष से लंबित राजस्व वादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाए। अधिकारी न्यायालय में बैठकर सभी पक्षों को सुनकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करायें। इसके अलावा उन्होंने बाढ़ राहत कार्यों की मंडलीय समीक्षा। कमिश्नर ने सभी जिलों के डीएम से बाढ़ के संबंध में जानकारी ली। साथ ही सभी डीएम को अपनी पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिये।

प्रधानों ने जिलाधिकारी को मांग पत्र देकर बताई समस्याएं

संतकबीरनगर। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के बैनर तले जिलाध्यक्ष जगदीश चौधरी के नेतृत्व में ग्राम प्रधानों ने जिलाधिकारी को प्रधानों द्वारा गांव में किये जा रहे विकास कार्यों में हो रहे समस्याओं के सम्बन्ध में मांग पत्र दिया है। जिलाधिकारी को दिये गये मांग पत्र में प्रधान रामेश्वर, सुनीता सिंह, किरन, एकलाख अहमद, इनामुल्लाह कुरैशी, विनोद कुमार, उर्मिला देवी, उमैर अहमद, बिन्दु, आशा देवी सहित ग्राम प्रधानों ने कहा है कि बस्ती मण्डल के ग्राम पंचायतों में लगने वाले इण्टरलाकिंग ईटो का दर निर्धारण वित्तीय दर 22 रूपया निर्धारित था और वर्तमान में घटाकर 18 रू0 प्रति अदद कर दिया गया है। इण्टरलांकिग ईट में प्रयोग होने वाले सामग्रियों का दर बढ़ा नही है जबकि घटा दिया गया है। प्रधानों ने 22 रूपये ईट का निर्धारित किया जाय। इसी क्रम में ग्राम प्रधानों ने कहा है कि राज्य वित्त, 15वां वित्त के कार्यो से होने वाले कार्यो में प्रयोग होने वाले ईट, सीमेन्ट, छड़ आदि का वर्तमान बाजार के दर से कम है। बाजार दर में काफी अन्तर है। प्रधानों ने मांग किया है कि सर्वे कराकर सामग्रियों के क्रय हेतु अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करें।

व्यापारी की फर्म पर एसआईबी का छापा, मचा हड़कंप

●एक दर्जन अधिकारी व पुलिस फोर्स रही मौजूद

संवाददाता। शुकुल बाजार, अमेठी

स्थानीय कस्बे में वाणिज्यकर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआइबी) की टीम ने बड़े लोहा कारोबारी के यहां छापेमारी की। टीम के धमकते ही कस्बे के व्यापारियों में अफरा-तफरी मच गई। बाजार शुकुल कस्बा के एक दुकान में सर्च वारंट के साथ पहुंचे एसआईबी टीम को देखते ही अधिकांश दुकानदार अपने शटर गिराकर भागने लगे।

कटरा चौराहे दुकानें बंद दिखाई देने लगी। एसआईबी की विशेष टीम ने छापेमारी कर जांच शुरू कर दी। जांच टीम ने कारोबारी की गोदाम के स्टॉक आदि की जांच के साथ ही खरीद-फरोख्त के दस्तावेज भी तलब किए। कारोबारी के गैर मौजूदगी में उनके अधिवक्ता व सीए ने टीम को जांच के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराए। हालांकि जांच टीम का दावा है कि प्राथमिक जांच में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। दस्तावेजों की गहन जांच के बाद ही स्थिति साफ होगी।

बाजार शुकुल कटरा में करीब एक दर्जन दुकानों में एक ही परिवार दो फर्म के नाम से लोहे का बड़ा कारोबार करता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक बुधवार की दोपहर आयरन स्टोर पर अयोध्या की एसआईबी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने छापेमारी की। जिससे बाजार में हड़कंप मच गया। कई घंटे तक टीम जांच पड़ताल करती रही।

एसआईबी टीम के डिप्टी कमिश्नर अयोध्या प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि वाराणसी में एक ट्रक पकड़ी गई थी। जो झारखंड सरिया लेकर आ रही थी।माल जो लदा हुआ था उसके प्रपत्रों में कमी थी।एसआईबी बनारस की टीम ने उसे पकड़ा लिया। वो माल शुकुल बाजार आ रहा था । जिसको लेकर वहां के अधिकारियों ने पत्र लिखकर इसकी जांच करने का अनुरोध किया। उसी के तहत व्यापारी के सर्च वारंट के मद्देनजर दुकान के सभी अभिलेख पत्रावलियों की जांच की गई। सभी सामानों की मिलान कराई गई। जांच के बाद टीम वापस लौट गई।

दुकान में कोई बहुत अंतर नहीं मिला। लगभग सभी पत्रावली सही पाए गए। दुकानदार को एक सप्ताह के भीतर बिल, इनवायस, स्टाक रजिस्टर मिलान के लिए संबंधित कार्यालय के लिए निर्देशित किया गया। जांच के दौरान सचल दल असिस्टेंट कमिश्नर सारिका सिंह ,वाणिज्य अधिकारी जय लाल सहित एक दर्जन पुलिसकर्मी उपस्थित रहे।

वाणिज्यकर विभाग की विशेष अनुसंधान शाखा (एसआइबी) की टीम के मुताबिक बड़े लोहा कारोबारी के यहां छापेमारी की दोपहर दो बजे से रात्रि दस बजे तक कुल 10 घंटे तक छापेमारी कीजांच टीम ने कारोबारी की गोदाम के स्टॉक आदि की जांच के साथ ही खरीद-फरोख्त के दस्तावेज भी तलब किए।

जिला रोजगार कार्यालय द्वारा रोजगार मेले का आयोजन

अमेठी। शासन के निर्देशानुसार राजकीय आईटीआई गौरीगंज में श्री राम पिस्टन कंपनी द्वारा एक कैंपस ड्राइव जिला सेवायोजन कार्यालय के सौजन्य से शुक्रवार को आयोजित किया गया। जिला सेवायोजन अधिकारी अनुपमा रानी ने अभ्यर्थियों को संबोधित किया, रोजगार संगम पोर्टल पर बच्चों का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तथा करियर संबंधित जानकारी प्रदान की। मेले में कुल 78 बेरोजगार युवाओं ने प्रतिभाग किया। जिसमे से लिखित परीक्षा एवम साक्षात्कार के माध्यम से 26 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। रोजगार मेले में आईटीआई प्रधानाचार्य विवेक यादव एवम कार्यदेशक अजय कुमार सिंह द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। सेवायोजन कार्यालय के सुरेंद्र पांडे, अजय कुमार तथा आईटीआई के समस्त कर्मचारियों ने रोजगार मेले में प्रतिभाग किया।

न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल में मनाया गया कारगिल विजय दिवस

रायबरेली। न्यू स्टैण्डर्ड पब्लिक स्कूल त्रिपुला के शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी शिक्षण संस्थान एवम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित शिक्षण संस्थान न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल के प्रबन्धक षषिकांत षर्मा ने शहीद जवानों के लिए दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की । साथ ही साथ विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं व बच्चों ने भी शहीदों को पुष्प अर्पित कर नमन किया।

प्रधानाचार्या एस.एल. प्रजापति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस का 25वाँ वर्ष है, जितना खुशी हमें जीत की है उससे कहीं ज्यादा दु:ख भी है । इस युद्ध में हमारे देश के वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों की बाजी लगा कर देश की रक्षा की, हिमांचल प्रदेश के राइफ्लमैन संजय कुमार के साथ कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध के दौरान देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहूति दे दी थी और साथ ही साथ लगभग 527 जवानों ने भी अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया था। उनका यह योगदान संपूर्ण राष्ट्र कभी नहीं भुला सकता। अतुल्य शौर्य, साहस और पराक्रम का परिचय देने वाले सेना के सभी जवानो को शत शत नमन। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विद्यालय के बच्चों द्वारा सेना की वेशभूषा में दिया गया परिचय सराहनीय रहा।

सैनिक स्कूल में कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को किया नमन

संवाददाता। अमेठी

1999 में आज के ही दिन 26 जुलाई को भारत कारगिल युद्ध के दौरान अपने सशस्त्र बलों की वीरता का सम्मान करने के लिए एक मार्मिक अवसर पर कारगिल दिवस मनाता है। यह दिन भारतीय इतिहास में गहरा महत्व रखता है, जो विपरीत परिस्थितियों में देश के लचीलेपन, बहादुरी और एकता का प्रतीक है। इस वर्ष कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ या रजत जयंती है। सैनिक स्कूल अमेठी ने कारगिल विजय दिवस को उत्साह और चिंतन के साथ मनाने के लिए मोटिवेशनल हॉल के दौरे और एक वृत्तचित्र की स्क्रीनिंग सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। लेफ्टिनेंट कर्नल गीता महाडीक, प्रिंसिपल, लेफ्टिनेंट कमांडर सिद्धार्थ नेहरा, प्रशासनिक अधिकारी के साथ, कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया। कैडेट शौर्य सिंह कैडेट प्रशांत यादव , और कैडेट अर्नव त्रिपाठी ने अपने भाषणों में हमारे योद्धाओं के प्रेरणादायक साहसी कार्यों को याद किया। एनसीसी प्रशिक्षक, एएनओ और सभी एनसीसी कैडेट इस दिवस को मनाने और भारतीय सशस्त्र बलों के उन योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए मोटिवेशनल हॉल में एकत्र हुए, जिन्होंने कारगिल युद्ध में देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।

जमीनी विवाद में कांस्टेबल पर मारपीट का मुकदमा दर्ज

जगदीशपुर, अमेठी। थाना क्षेत्र के अन्तर्गत जमीनी विवाद को लेकर पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर कांस्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अन्तर्गत जगधरपुर मजरे हारीमऊ का है गांव निवासी कमलेश पत्नी राजबक्श सरोज का काशीराम से मकान बनाने को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया था कि रास्ते में पुलिस विभाग में खीरी लखीमपुर कोतवाली गोला में कांस्टेबल के पद पर आन ड्यूटी पर तैनात काशीराम ने परिजनों के साथ कोतवाली जगदीशपुर जा रही महिला कमलेश सरोज व उनके बेटे को जमकर मारपीट कर गंदी गंदी गालियां भी दिया जिसका वीडियो को संज्ञान में लेने के बाद पुलिस ने कांस्टेबल काशीराम के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।

शिक्षामित्र पर लगाया छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप

ऊंचाहार। कोतवाली क्षेत्र में शिक्षा के मंदिर को शर्मसार करने का मामला सामने आया है, विद्यालय में तैनात शिक्षमित्र पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रोहनियां ब्लाक क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 11 वर्षीय बालिका गांव स्थित कम्पोजिट विद्यालय में कक्षा 5 की छात्रा है।घटना 19 जुलाई की है, जब छात्रा विद्यालय गई हुई थी। तभी आरोप है कि गांव के ही रहने वाले शिक्षमित्र ने उसे अपने पास बुलाया और उसके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी।छात्रा के विरोध करने पर शिक्षमित्र ने उसे पैसे देने का लालच दिया। घर पहुंचने पर छात्रा ने परिजनों को आपबीती बताई।तो परिजन आगबबूला हो गये।जिसके बाद ये जानकारी जब विभागीय शिक्षकों को हुई तो आरोप है कि सब एकजुट होकर आरोपी शिक्षमित्र के बचाव में छात्रा के घर गये और उसके परिजनों को समझा बुझाकर 6 दिनों तक मामले को दबाये रखा।

डीएम ने राजस्व विवाद रहित गांव चिन्हित करने का दिया निर्देश

संतकबीरनगर। जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर द्वारा जनपद के तीनों उप जिलाधिकारियों एवं तहसीलदारों को राजस्व विवाद रहित ग्राम की परिकल्पना के संबंध में राजस्व विवादरहित ग्रामों को चिहिन्त कर सूची बनाने के निर्देश दिये गये थे। जिसका आशय यह था कि जनता दर्शन आदि के दौरान भूमि विवाद एवं अन्य छोटी-छोटी शिकायते प्राप्त होती हैं जिनका निस्तारण लेखपाल/राजस्व निरीक्षक आदि के स्तर से किया जा सकता है। ऐसे राजस्व ग्राम जिसमें जनसुनवाई/जनता दर्शन में अधिक शिकायती प्रार्थना प्राप्त होते हैं और उस ग्राम में भूमि विवाद से संबंधित वाद विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन पाये गये हैं। ऐसे ग्रामों में अभियान चलाकर प्रकरण के निस्तारण हेतु ग्रामवार टीम गठित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देश के कम में उप जिलाधिकारी धनघटा रमेश चन्द्र ने बताया है कि जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में राजस्व ग्रामवार टीम का गठन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि राजस्व टीम को निर्देशित किया गया है कि राजस्व विवाद रहित ग्राम बनाने के लिए संबंधित ग्राम में उपस्थित होकर समस्याओं/शिकायतों को सूचीबद्ध कर, क्रमिक निस्तारण कराते हुए निस्तारण आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा किया गया माक एक्सरसाइज कार्यक्रम का आयोजन

डलमऊ, रायबरेली। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन विभाग लखनऊ द्वारा गुरुवार को गंगा तट डलमऊ के किनारे बाढ़ आपदा के समय डूबने आदि जैसी आपदा से बचाव के लिए माक एक्सरसाइज कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें क्षेत्रीय विभागों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया जिसमें सभी विभागों द्वारा अपने-अपने आपदा के समय दी जाने वाली सुविधाओं की एक्सरसाइज की गई।

गुरुवार को गंगा तट डलमऊ के रानी शिवाला घाट पर उप जिलाधिकारी डलमऊ मनोज कुमार सिंह की अगवाई में मांक एक्सरसाइज कार्यक्रम का आयोजन किया गया उप जिलाधिकारी डलमऊ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि विश्व बचाओ दिवस के क्रम में मॉक एक्सरसाइज का कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन लखनऊ द्वारा क्षेत्रीय विभागों के अधिकारियों और कर्मियों के साथ बाढ़ आपदा के पहले और आपदा के दौरान तथा आपदा के बाद होने वाली समस्याओं से निजात दिलाने के लिए एक्सरसाइज की गई बाढ़ के समय डूबे हुए को बचाने के लिए एसडीआरएफ टीम के कर्मचारियों के साथ क्षेत्रीय गोताखोर द्वारा बचाव की मांक एक्सरसाइज की गई।

कार्यक्रम में पुलिस विभाग स्वास्थ्य विभाग राजस्व विभाग विकासखंड विभाग खाद्य पूर्ति विभाग एवं एसडीआरएफ के कर्मचारियों द्वारा अपने-अपने कार्यों का अभ्यास किया गया कार्यक्रम पूर्वन 8:00 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक आयोजित किया गया जिसकी ट्रेनिंग के निर्देश आपदा प्रबंधन नई दिल्ली के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी गई इस मौके पर तहसीलदार डलमऊ उमेश चंद्र नायब तहसीलदार डलमऊ शिवम सिंह राठौर क्षेत्राधिकार अरुण सिंह कोतवाली प्रभारी पवन कुमार सोनकर डॉ विनीत सिंह आदि के साथ अन्य विभाग के अधिकारी व क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे।

जिलाधिकारी ने गांव में चौपाल लगाकर सुनीं ग्रामीणों की शिकायतें

संवाददाता। गोंडा

जन चौपाल कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने हलधरमऊ ब्लाक की पांच ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों के साथ चौपाल लगाकर गांव में हो रहे विकास कार्यों की जमीनी हकीकत को जाना। डीएम ने गांव में विकास कार्यों का सत्यापन भी कराया तथा जहां खामियां मिली, उन्हें तुरंत दुरूस्त कराए जाने के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने डीएम के समक्ष विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याएं रखीं।

जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया तथा समस्या का निस्तारण करने के कड़े निर्देश दिए। इस मौके पर डीएम की अध्यक्षता में ग्राम बालपुर हजारी, हरसिंहपुर, चौरी, गुरसड़ा तथा कोंचा कासिमपुर में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। इन सभी चौपालों में ग्राम वासियों द्वारा राशन वितरण, आवास, किसान सम्मान निधि, राजस्व, पेंशन आदि से संबंधित समस्या को रखा गया।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यदि किसी कर्मचारी या किसी अधिकारी द्वारा जनता की समस्याओं के समाधान में जरा सी भी लापरवाही बरती गई तो लापरवाह कर्मचारी अथवा अधिकारी के खिलाफकड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी एम.अरून्मोली, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा, उपजिलाधिकारी करनैलगंज भारत भार्गव, तहसीलदार करनैलगंज मनीष कुमार, नायब तहसीलदार हलधरमऊ संतोष कुमार यादव, जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दूबे, परियोजना निदेशक डीआरडीए चन्द्र शेखर, डीएसओ कृष्ण गोपाल पाण्डेय सहित सभी संबंधित विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

वंदन योजना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने की बैठक

श्रावस्ती। शासन के निर्देशानुसार जनपद के नगरीय क्षेत्रों में सांस्कृतिक पौराणिक धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर अवस्थापना तथा अन्य सुविधाओं के विकास हेतु वंदन योजना से सम्बन्धित प्रस्ताव/आगणन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कक्ष में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि योजनान्तर्गत 2 स्थानों का चिन्हांकन कर प्रस्ताव/आगणन तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। जिससे जनपद की सांस्कृतिक पौराणिक एवं धार्मिक स्थलों पर सुविधाओं का विकास किया जा सके। उन्होने यह भी निर्देशित किया कि चयनित स्थल से सम्बन्धित नगरीय निकाय द्वारा नियमानुसार डीपीआर तैयार कराकर प्रस्तुत किया जाए। उन्होने कहा कि इसका उद्देश्य जनपद के नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित सांस्कृतिक धार्मिक पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं आगन्तुकों को मूलभूत अवस्थापना सुविधायें उपलब्ध कराया जा सके। इस अवसर पर एडीएम अमरेन्द्र कुमार वर्मा, ईओ नगर पालिका परिषद भिनगा डा अनीता शुक्ला अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग केपी मिश्रा सहायक पर्यटन अधिकारी मनीष श्रीवास्तव उपस्थित रहे।

आरक्षण अधिकार दिवस विषयक गोष्ठी का किया गया आयोजन

संवाददाता। रायबरेली

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी कार्यालय में संविधान-मान स्तम्भ की स्थापना की गयी। 26 जुलाई 1902 को छत्रपति शाहू जी महराज ने ज्योतिबा राव फूले की प्रेरणा से अपने राज्य में पहली बार 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की थी। इस अवसर पर आरक्षण अधिकार दिवस विषयक गोष्ठी का आयोजन किया गया।

गोष्ठी को सम्बोधित करते हुए जिलाध्यक्ष इं0 वीरेन्द्र यादव ने कहा कि सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े, पी0डी0ए0 के लोगों को सम्मान देने की जो परिकल्पना ज्योतिबा राव फूले, छत्रपति शाहू जी महराज, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डा0 राम मनोहर लोहिया, मुलायम सिंह यादव ने की थी और संविधान में व्यवस्था दी थी उसी संविधान एवं संविधान के तहत मिलने वाले आरक्षण को सरकार समाप्त कर देना चाहती है।

बछरावां विधायक श्याम सुंदर भारती ने कहा कि बाबा साहब ने 26 नवम्बर 1946 को संविधान की रचना की एवं 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र में लागू किया गया। सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ओ0पी0 यादव ने कहा कि मोदी सरकार सरकारी विभागों का निजीकरण कर आरक्षण समाप्त कर देना चाहती है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शशिकांत शर्मा ने कहा कि आरक्षण निजी कम्पनियों एवं शिक्षण संस्थानों में लागू किया जाय। प्रान्तीय नेता शिव मूर्ति सिंह राना ने कहा कि आरक्षण भीख नहीं पी0डी0ए0 का अधिकार है। शिक्षा विद रमेश चौरसिया नें कहा कि आरक्षण के बल पर ही हम अपना भविष्य बना सकते है। इसके लिए संघर्ष करने की आवश्यकता है। गोष्ठी का संचालन जिला महासचिव मो0 अरशद खान ने किया। गोष्ठी को उमाशंकर चौधरी, चौधरी सुरेश निर्मल, हसीन अहमद, शिव नारायण सोनकर, राजेन्द्र यादव, मुशीर अहमद, राजेश मौर्या, अरूण यादव, आदि मौजूद रहे।

मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी में संविदा कर्मी, काला फीता बांध किया काम

लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ की लखीमपुर इकाई द्वारा प्रदेश कार्यकारिणी के आवाहन पर अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर शुक्रवार से आंदोलन में सहभागिता शुरू कर दी गई है। इसके क्रम में शुक्रवार को जिले के समस्त एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर कार्य किया और अपना विरोध दर्ज कराया। जिला अध्यक्ष विकास श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश भर में एनएचएम के अंतर्गत तैनात कर्मचारी की प्रमुख मांगों को लेकर लगातार शासन व प्रशासन से वार्तालाप किया जा रहा था परंतु काफी समय बीत जाने के बाद भी जब निष्कर्ष नहीं निकला तब प्रदेश कार्यकारिणी के आवाहन पर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जिलेभर में तैनात एनएचएम संविदा कर्मियों ने शुक्रवार को काला फीता बांधकर कार्य किया और अपना विरोध दर्ज कराया है।

जिला पुरुष चिकित्सालय में डॉ शिखर बाजपेई और डॉ शिशिर पांडे के नेतृत्व में संविदा कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन महंत सिंह व फार्मासिस्ट सहदेव सचान सहित संविदा कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं टीबी क्लिनिक में तैनात संविदा कर्मचारियों ने भी कला फीता बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया इस दौरान राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से फार्मासिस्ट परमानंद वर्माए संजय राय आधिकारिक कर्मचारियों ने भाग लिया इसी तरह सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केदो पर तैनात संविदा कर्मचारियों ने कला फीता बांधकर पहले दिन अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है।

कक्षा 9 व 11 में पंजीकरण पांच अगस्त तक हो सकेंगे

फतेहपुर। यूपी बोर्ड के स्कूलों में प्रवेश लेने वालों के लिए अभी भी मौका है। बोर्ड की ओर से कक्षा 9 और 11 में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं के पंजीकरण के लिए 5 अगस्त अंतिम तिथि तय की है। ऐसे में कक्षा 9 और 11 में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को पांच अगस्त तक का मौका मिल सकेगा। छात्र-छात्राओं के पंजीकरण कराने में हेराफेरी करने वाले विद्यालयों पर विशेष रूप से नजर रखी जाएगी। अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रधानाचार्य के खिलाफ कार्रवाई होगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से कक्षा 9 और 11 में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं के पंजीकरण के लिए समय सारणी जारी कर दी गई है।

26 अगस्त तक जमा होगा चालान: माध्यमिक शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कक्षा 9 और 11 में प्रवेश लेने वाले सभी छात्र-छात्राओं का शुल्क चालान के माध्यम से कालेज के प्रधानाचार्य को 26 अगस्त तक जमा कराना होगा और 26 अगस्त तक सभी छात्र-छात्राओं का विवरण भी माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराना आवश्यक होगा। 26 अगस्त से 5 सितंबर के बीच संस्था के प्रधानाचार्य वेबसाइट पर छात्र-छात्राओं के विवरण फोटो आदि की जांच कर सकेंगे। इस दौरान किसी भी विवरण में अपडेशन नहीं कराया जा सकेगा। जांच के बाद कमी पाए जाने पर 5 सितंबर से 20 सितंबर तक परीक्षार्थियों के विवरण में संशोधन कराया जा सकेगा लेकिन इस दौरान कोई नवीन छात्र का विवरण अपलोड नहीं कराया जा सकेगा। 20 सितंबर को कक्षा 9 और 11 के छात्र छात्राओं के विवरण को अंतिम रूप देने के बाद उसकी एक प्रति माध्यमिक शिक्षा परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को 30 सितंबर तक प्रधानाचार्य के माध्यम से भेजी जाएगी।

कारगिल दिवस पर युवाओं ने दिया देशभक्ति का संदेश

फतेहपुर। कारगिल विजय दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से दो दिवसीय कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को प्रेक्षागृह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ सभा का आयोजन कर वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सैनिक कैप्टन राजकुमार राठौर ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश कार्यसमिति सदस्य जिला प्रवासी रुद्र मिश्रा रहे।

भाषण, गीत प्रतियोगिता, ताइक्वांडो प्रदर्शन समेत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिसमें 10 विद्यालयों ने प्रतिभाग किया। मुख्य अतिथि ने युवाओं में उत्साह भरते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई ने अदम्य साहस दिखाते हुए 60 दिनों में भारतीय विजय पताखा फहराने का काम किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नीचता पूर्ण घटना का पूरे दमखम के साथ धूल चटाने वाले अटल बिहारी वाजपेई हम सबके लिए प्रेरणादायक हैं। प्रदेश कार्य समिति सदस्य रुद्र मिश्रा ने युवाओं में उत्साह भरा।

जिलाध्यक्ष मधुराज विश्वकर्मा ने सभी भाषण प्रतिभागियों, पूर्व सैनिकों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रतिभागियों की सराहना की। संचालन जिला महामंत्री प्रसून तिवारी ने किया। इस अवसर पर ऐश्वर्या सिंह चंदेल, गौरव अग्रहरि, विमलेश पांडेय, सावन गुप्ता, उदय प्रताप सिंह, कुलदीप मौर्य, सुयश अंबेडकर, मंडल अध्यक्ष किशन शुक्ला, गौरव अग्रहरि, हिमांशु त्रिपाठी, आलोक सिंह, अनुभव शुक्ला, सचिन पांडे समेत निलेश मिश्रा, घनश्याम राजपूत, दुर्गेश लोधी, नीरज निषाद आदि तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे।

पूर्व राज्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को सौंपी आर्थिक सहायता

मृतक बच्चों के परिजनों को आर्थिक सहायता देतीं पूर्व राज्यमंत्री।

गुरसहायगंज (कन्नौज)। विगत दिनों पूर्व समधन के मोहल्ला गर्दाबाद में तालाब में नहानें गये एक ही मोहल्ले के चार बच्चों की गहरे पानी में डूबकर मृत्यु हो गई थी। जिसमें शासन द्वारा भेजी गई आर्थिक सहायता को पूर्व राज्यमत्री अर्चना पाण्डेय नें मृतक बच्चों के परिजनों को सौंपकर संवेदना व्यक्त कीं।

बीतीशाम क्षेत्र के कस्वा समधन के मोहल्ला गर्दाबाद में समर्थकों के साथ पहुंची पूर्व राज्यमंत्री अर्चना पाण्डेय नें छिबरामऊ उपजिलाधिकारी उमाकान्त, चेयरमैन आसमा बेगम व उनके प्रतिनिधि अखलाख हुसैन सिददीकी के साथ चार मृतक बच्चों के परिजनों को चार-चार लाख रुपयों की आर्थिक सहायता प्रदान करनें के उपरान्त मृतक बच्चों के प्रति गहरा दुख व्यक्त करते हुये हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होनें कहा कि भाजपा सरकार समस्त प्रदेश वासियों के सुख दुख में सदैव साथ रही है।

भारी बारिश से सरकारी कार्यालय जलमग्न

मौदहा, हमीरपुर। शुक्रवार को हुई जोरदार बारिश में सरकारी दावों की पोल खुल गई और कस्बे का जल संस्थान में पानी से भर गया, वहीं बिल जमा करने गए उपभोक्ता और कार्यालय में बैठे कर्मचारी असहाय नजर आए। वहीं बिल जमा करने कार्यालय आए उपभोक्ताओं में से एक उपभोक्ता ने वीडियो वायरल कर विभाग की पोल खोल दी। शुक्रवार दोपहर हुई लगभग घंटे की जोरदार बारिश ने कस्बे के सरकारी दावों की पोल खोल दी। दोपहर बाद एक वीडियो जमकर सोशल मीडिया में वायरल हुआए जिसमें कार्यालय में कुर्सी पर बैठे कर्मचारी असहाय दिखाई दिएए जबकि पूरे कार्यालय में करीब चार से पांच इंच पानी से भरा हुआ दिखाई दिया। जिससे विभाग में रखीं फाइलें भी प्रभावित हुईं। हालांकि समाचार पत्र वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता हैए लेकिन वायरल वीडियो मौदहा के जल संस्थान का बताया जा रहा है। जिसमें लोगों द्वारा तरह तरह के कमेंट्स किए जा रहे है।

बरसात के चलते डीएम द्वारा गठित टीम मौके पर नहीं पहुची

हमीरपुर। लघु सिचाई द्वारा निर्मित किये गये चेकडैमों की जांच के लिये डीएम द्वारा बनायी गयी कई टीमे भारी बरसात होने के कारण मैके पर नही जा सकी। हालाकि इसके लिये टीम में शामिल अधिकारी ठेकेदारों को लेकर चंडौत बस स्टेशन में जाकर ग्रामीणों के बुलाकर उनसे मान मनौब्बल करते रहे। जमकर विवाद हुआ। उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया है। जानकारी के मुताबिक विभाग द्वारा वाटर रिचार्जिंग सिचाई के लिये बनाये गये चेकडैम समय से पहले ही नष्ट हो गये है बंधौली व चंडौत में अभी हाल ही में बनाये गये थे मगर वह चटक गये है जब कि विभाग के अधिशासी अभियंता एसबी सिंह का कहना है कि चेकडैम पांच साल पहले बनाये गये थे वह नष्ट हुये है एक्शियन ने उच्चाधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास किया है। इधर आज जांच के लिये गयी जांच टीम के अधिकारी बरसात के कारण जब मौके पर नही जा पाये तो ग्रामीणों को मनाने का प्रयास किया जिससे जांच अधिकारियों में काफी देर तक झड़प होती रही। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में कोई चेकडैम नही है जिससे एक बूद से खेत की सिचाई हुई हो उधर ठेकेदारों द्वारा ग्रामीणों पर जांच टीम दबाव पाने का प्रयास किया मगर ग्रामीणों ने ठेकेदारो को भी खरी खोटीसुनायी है। जिससे मौके पर भीड एकत्र हो गयी। उधर महेंद्र सिंह राजपूत ने चेकडैम के बारे में पांच साल के बनाये गये चेकडैमों की आरटीआई से सूचना मांगी है। ताकि विभागीय अभियंताओं की असलियत शासन के सामने लायी जा सके। हालाकि बिभागीय अभियंता नेताओं की चौखट में हाजिरी देना शुरु कर दिया है वही उच्चाधिकारियों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे है।भाजपा नेताओ का कहना है कि यदि अधिशासी अभियंता ने किसानों के साथ धोखा किया तो आन्दोलन किया जायेगा। मामला शासन स्तर पर पहुच गया है।

आबकारी विभाग ने 118 लीटर कच्ची शराब की बरामद

फर्रूखाबाद। आबकारी आयुक्त, के आदेश एवं डीएम के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी के पर्यवेक्षण में विशेष प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत जनपद के आबकारी निरीक्षक क्षेत्र.1 कुमार गौरव सिंह एवं क्षेत्र .2 राजेश कुमार चौबे मय स्टाफद्वारा बाग लकूला एवं कायमगंज क्षेत्र में दबिश दी गई। लगभग 180 किग्रा लहन नष्ट किया व लगभग 118 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर 3 अभियोग पंजीकृत किये गए। आबकारी दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। स्टाक रजिस्टर, आनलाइन पेमेंट एसी सी टी वी कैमरा का परीक्षण किया गया। अवैध मदिरा के निर्माण बिक्री परिवहन की रोकथाम हेतु प्रवर्तन कार्य निरंतर जारी रहेगा।

क्विक न्यूज

25 लाख से अधिक के कीमती 101 मोबाइल बरामद

फर्रूखाबाद। पुलिस ने आज 25 लाख रुपए से अधिक के कीमती 101 मोबाइल बरामद किये। यह जानकारी आज शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि देश, प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं थानों के पिछले कई महीनो से गायब हुए एवं चोरी गए फोन धारको की सूचना के उपरांत सर्विलांस पुलिस टीम प्रभारी विशेष कुमार के दलबल द्वारा आज शुक्रवार को 25 लाख रुपए से अधिक की कीमत वाले 101 मोबाइलों को बरामद किया। उन्होंने बताया कि जिले की पुलिस सर्विलांस टीम द्वारा बरामद किए गएए सभी मोबाइलों को आज फतेहगढ़ पुलिस लाइन के सभागार में आयोजित किए गए गए। एक कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार प्रियदर्शी ने फोन धारक उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया। जिसके फलस्वरूप सभी फोन धारकों में खुशी की लहर की दौड़ गई।

हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर युवक की मौत

फतेहपुर। सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के कस्बे के समीप जंगल गया युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। जिससे उसकी मौत हो गई घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई कर रही है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी राम प्रकाश सिंह का 24 वर्षीय पुत्र महेंद्र प्रताप सिंह गांव के समीप जंगल गया था। तभी 11 हजार लाइन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की जानकारी परिजनों को हुई तो घर में कोहराम मच गया। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

संदिग्ध अवस्था में युवक की मौत

फतेहपुर। सदर कोतवाली क्षेत्र के कांशीराम कॉलोनी में युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। जिसकी सूचना पुलिस को हुई तो मौके पर पहुंची पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर घटना की जांच पड़ताल कर रही है। जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी निवासी स्वर्गीय जयपाल के 28 वर्षीय पुत्र छोटू कश्यप की घर पर संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। जिसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटना की जांच पड़ताल कर रही है।

बेतवा नदी का जल स्तर बढा

हमीरपुर। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ व छतरपुर जिलों में हुई बारी बरसात के कारण धसान नदी में पानी बढ़ गया है। इसलिये वेतवा नदी में लगभग ढाई मीटर तक पानी बढने की संभावना है। दोनो नदियां खतरे के निशान से बहुत दूर है। हालाकि प्रशासन ने नदियों के किनारे रहने वाले लोगो से बाढ़ से सतर्क रहने का एलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन का मानना है कि फिलहाल जिले में बाढ़ जैसे कोई हालात नही है।

तीन लोगों पर की गई गुंडा एक्ट की कार्रवाई

गुरसहायगंज (कन्नौज)। गुरुवार को स्थानीय कोतवाली कार्यालय में प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र के कस्बा समधन के मोहल्ला गोरी नवादा निवासी वसीम पुत्र वकील तथा ग्राम अनीभोज निवासी रिजवान पुत्र यूनुस एवं ग्राम खाडेदेवर निवासी राजीव कुमार पुत्र सुरेश चंद्र कटेरिया आदि गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं इनका जनता में डर व आतंक व्याप्त है। उनके भय की वजह से जनता का कोई भी व्यक्ति गवाही देने को तैयार नहीं है। बताया कि वसीम व रिजवान अपने घर आते जाते रहते हैं। जबकि राजीव अपने घर पर मौजूद है। आरोपियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट कार्रवाई की गई है।

ज्वेलर्स की दुकान से युवक का मोबाइल हुआ चोरी

गुरसहायगंज (कन्नौज)। ज्वेलर्स की दुकान पर जेवरात खरीदने आए युवक का एक अज्ञात महिला ने मोबाइल फोन चोरी कर लिया। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। क्षेत्र के ग्राम सिंहपुर निवासी राम पाल बाथम पुत्र नंदराम द्वारा कोतवाली में दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा गया है कि शुक्रवार की दोपहर नगर के चकोर रोड स्थित मां आभूषण केंद्र पर जेवरात खरीदने आया था। ग्राम मझपुरवा निवासी अज्ञात महिला ने उसका मोबाइल फोन चोरी कर लिया। पीड़ित की तहरीर पर कोतवाली पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है।

पंचायत सचिवों, पंचायत मित्रों तथा प्रधानों के लिए मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम बना मजाक

मौदहा हमीरपुर। मनरेगा के कार्यों में होने वाले मोबाइल मानीटरिंग सिस्टम में एक ही फोटो को अलग.अलग मस्टररोल में दर्शाया जा रहा है लेकिन जिम्मेदार आंख मिचौली का खेल खेलकर कार्य प्रभारी एवं पंचायत मित्रों की क्रिया कलापों पर मूकदर्शक बने बैठे हैं हालांकि सीडीओ समय-समय पर विकास कार्यों की निगरानी हेतु कार्य स्थल पर पहुंच वहां की जमीनी हकीकत देखते हुए भी अंजान बन रहे हैं।मौदहा विकासखंड का हमेशा विवादों से गहरा रिश्ता बना रहा है फिर चाहे यहां आवास घोटाला का मामला हो या मुर्दों से मनरेगा के विभिन्न काम करवाने का लेकिन मौजूदा समय में मनरेगा के हो रहे विकास कार्यों में सरकार द्वारा मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से प्रतिदिन मनरेगा मजदूरों की हाजिरी का प्रावधान रखा गया है, उक्त पद्धति से मनरेगा में पारदर्शिता स्थापित होगी लेकिन विकासखंड कार्यालय में तैनात तमाम सचिवों प्रधानों एवं पंचायत मित्रों ने सरकार की मंशा को धता बता दिया है।

प्रशिक्षण व रोजगार गुणवत्ता की जांच समिति बनाकर करें: जिलाधिकारी

फतेहपुर। कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के अनुश्रवण की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी सी. इंदुमती की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा गांधी सभागार में सम्पन्न हुई। उन्होंने केंद्र प्रोषित योजनाएं पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, राज्य पोषित योजना स्टेट स्किल डेवलपमेंट, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, प्रोजेक्ट प्रवीन, जिला कारागार प्रशिक्षण से सबद्ध सस्थाओं की बिंदुवार प्रगति समीक्षा की। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित पाए जाने वाली संस्था पोषिष्ट स्किल अग्रनाइजेशन, जीरो. टू0स्पा सैलून प्राइवेट लिमिटेड से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश संबंधितों को दिये। उन्होंने कहा कि संस्थाएं संचालित कोर्सो में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार युवक व युवतियों का नामांकन कराते हुए गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण निर्धारित समय से पूर्ण कराते हुए रोजगार दिलाएं। उन्होंने कहा कि संस्थाओं में संचालित कोर्सो में दिये जा रहे प्रशिक्षण व रोजगार की गुणवत्ता की जाँच समिति बनाकर करें और सूचना रिपोर्ट से भी अवगत कराएं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कर रहे युवक व युवतियों के नाम, मोबाइल नंबर, पता सहित सूची भी उपलब्ध कराएं। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत स्किल प्राप्त युवकों को औधोगिक अधिष्ठानों में अप्रेंटिसशिप दिलाएं। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण लेने वाले को समयबद्धता के साथ प्रशिक्षण दें। प्रशिक्षण के दौरान फोटोग्राफी कराकर उपलब्ध करायी जाये। इस अवसर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी, जिला अर्थ संख्याधिकारी, डीसीएनआरएलएम, प्रधानाचार्य आईटीआई, प्रधानाचार्य पॉलिटेक्निक, जिला पंचायत राज अधिकारी, उपायुक्त उद्योग सहित संस्था के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

प्रशासन व पुलिस ने आरटीओ कार्यालय के बाहर मारा छापा

पुलिस हिरासत में मौजूद चौदह आरोपी।

● लाईसेंस के नाम पर अबैध बसूली करनें वाले चौदह लोगों को पकडा

कन्नौज। शक्रवार को अपर जिलाधिकारी आशीष सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. संसार सिंह के नेतृत्व में सदर क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश शर्मा द्वारा दलबल के साथ आरटीओ कार्यालय कर छापा मार कार्यवाही की गयी जिसमें करीब चौदह लोगों को हिरासत में लेकर विधिक कार्यवाही की गई है। स्थानीय कोतवाली में अपर जिलाधिकारी आशीष सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. संसार सिंह नें जानकारी देते हुये बताया कि विगत कुछ समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि आरटीओ कन्नौज के बाहर कुछ लोगों ने अपनी दुकाने एवं झोपडिया खोली हुई हैं। आरटीओ कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेन्स एवं ड्राइविंग लाइसेन्स रिन्यूवल आदि काम करवाने हेतु लोग जाते है उन लोगों से यह कहकर कि तुम्हारा काम हमारे माध्यम से हो सकता है एवं काम कराने के बदले में अवैध वसूली करते हैं। एवं ये लोग काम करवाने हेतु आने वाले लोगों को यह कहकर धमकाते है कि यदि तुम लोग हमारे माध्यम से काम नहीं करवाओगें तो तुम्हारा काम नही होने देगे। एडीएम आशीष सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. संसार सिंह, सदर क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार, प्रशिक्षु सीओ/थाना प्रभारी तालग्राम कपूर कुमार, प्रभारी निरीक्षक जय प्रकाश शर्मा, उपनिरीक्षक सुभाष चन्द्र ने दल बल के साथ छापेमारी कर श्रीराम, विकास, अभिषेक, ऋषभ, अवनेश कुमार, विपिन कुमार, देवेन्द्र, मुलाब, अजय कुमार, मो0 शमील, अमर कुमार शर्मा, सुमित, शिवाकान्त, हरिओम को हिरासत में लेकर कार्रवाई की गई है।

सैकड़ों बीघा पशुचर, ग्राम समाज परती एंव सरकारी भूमि पर दबंगों ने किए कब्ज़े

रोपी गयी धान की फ़सल

संडीला (हरदोई)। क्षेत्र में सक्रिय पैसे और पहुंच वाले दबंग भूमाफ़िया के आगे प्रशासन कितना बेबस और बौना है इसका उद्हारण ग्राम ककराली और उसका मजरा सेमराखेड़ा तथा ग्राम सभा आलमपुर हैए जहां पशुचर, परती और खाद्य के गड्ढों आदि के लिए रिज़र्व भूमि पर दबंग भूमाफ़िया ने कब्ज़ा कर उन्हें खेतों पर परिवर्तित कर बाकायदा धान की फ़सल भी रोक दी। ग्रामसभा ककराली का मजरा सेमराखेड़ा में जानकारी के अनुसार लगभग 200 बीघा पशुचरए परती तथा वन क्षेत्र हेतु आरक्षित भूमि है। इस भूमि पर वर्तमान तथा पूर्व प्रधानों की सहमति और राजस्वकर्मियों के संलिप्त होने के कारण इनपर भूमाफ़िया ने अपने लोगों के कब्ज़े करा दिए। धीरे.धीरे इन लोगों ने इन जमीनों को खेतों में परिवर्तित कर दिया। इस क्षेत्र में बाकायदा जेसीबी चलाकर ज़मीनों की हदबंदी कराकर कब्ज़े किए गए और यह सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर जो कुछ पशुचर भूमि बची भी थी उसपर भी बाकायदा जुताई करके धान की पौध रोप दी गयी है। कई स्थानों पर मिट्टी माफ़िया ने अंधाधुंध खुदाई करके वहां बड़े.बड़े तालाब भी बना डाले हैं। हद तो यह है कि इन दबंग लोगों ने वन विभाग के लिए संरक्षित भूमि तक पर कब्ज़े कर लिए। वर्तमान स्थिति यह है कि ग्राम सेमराखेड़ा में द 10 बीघा भी पशुचर और परती भूमि नहीं बची है। अब आवारा पशु वनविभाग के द्वारा स्थापित वन उपवन में ही चराई कर अपना किसी प्रकार पेट भर रहे हैं।

इसके अलावा विधानसभा ककराली के आसपास जो भी पशुचर और परती भूमि थीए उसपर भी कब्ज़ा करके उन्हें खेतों में परिवर्तित कर दिया गया है। ग्रामसभा आलमपुर के बाहर जो भी खाद्य के गड्ढे, परती और पशुचर भूमि थी उस पर भी अवैध कब्ज़े हो गए हैं और इनमें से अधिकांश में धान की पौध रोक दी गयी है। सरकारी भूमि की इस प्रकार की गयी लूट के संबंध में तमाम शिकायतें करने के बाद भी कोई कार्रवाई होती नहीं दिखी।

संचारी अभियान को मुंह चिढ़ा रही शहर में फैली गंदगी

फतेहपुर। बारिश के मौसम में वेक्टर जनित बीमारियों के नियंत्रण को लेकर चलाया जा रहा विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान विफल होता नजर आ रहा है। शहर में जगह-जगह फैली गंदगी इस बात की गवाही दे रही हैं कि अभियान के तहत जो निरोधात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए वह नहीं हो रही हैं।

शासन के निर्देश पर एक से 31 जुलाई तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान समापन की ओर है। बावजूद इसके नगर पालिका के क्षेत्र में रानी कालोनी में गंदगी का अंबार लगा है। यहां पर सड़क किनारे नालियां गंदगी से अटी हैं। नालियां ओवरफ्लो होने के बाद गंदगी आधी सड़क पर फैली हुई है। यहां के लोगों का कहना कि यहां पर नगर पालिका की ओर से सफाई नहीं कराई गई है। यहां पर लोग सड़क किनारे ही गोबर व कूड़ा डालने का काम करते हैं। कई-कई दिन बाद कूड़े को उठाकर डंपिंग ग्राउंड में डाला जाता है। नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा कई दिन तक कूड़ा इकट्ठा करने के बाद उठाया जाता है। जिस कारण नाली में पानी की निकासी बंद हो जाती है। गंदगी से नाली भरने के बाद सड़क पर गंदगी फैल जाती है।

सफाई के नाम पर झाड़ू तक ही सीमित: अभियान के सभी वार्डो के मोहल्लों में साफ सफाई के साथ एंटी लार्वा का छिड़काव, फागिंग समेत घास-झाड़ियों की कटाई आदि किया जाना चाहिए लेकिन तांबेश्वर मंदिर चौराहे से जिला कारागार जाने वाले मार्ग में मंदिर के ठीक पीछे झाड़ियों का अंबार है। झाड़ियां इतनी बड़ी हैं कि आधा मार्ग तक बंद हो चुका है लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। खासकर साउथ सिटी के अधिकांश मोहल्लों में गंदगी का अंबार लगा है जिसकी सफाई अभी तक नहीं हो सकी है। मच्छर बीमारी बांटने को तैयार: बारिश के मौसम में मच्छरों का आंतक बढ़ चुका है।

जरा याद करो कुर्बानी! कारगिल के शहीदों को शत् शत् नमन, डीएम ने दी श्रद्धांजलि

● डीएम ने खीरी के पांच पराक्रमी कारगिल सैनिकों को किया सम्मानित

लखीमपुर खीरी। जिलेभर में शुक्रवार को 25 वॉ कारगिल शौर्य दिवस को शौर्य दिवस मनाते हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं कलेक्ट्रेट स्थित जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय स्थित शहीद स्मारक में प्रभारी डीएम ने देश की सुरक्षा की खातिर शहीद हुए कारगिल शहीदों को पुष्प चढ़ाकर नमन किया गया। प्रभारी डीएम/सीडीओ अभिषेक कुमार ने एडीएम संजय कुमार सिंह संग जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय स्थित कारगिल शहीद स्मारक पर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती पर कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम हुआ, प्रभारी डीएम अभिषेक कुमार ने कारगिल युद्ध में शामिल पराक्रमी 05 पूर्व सैनिकों (ऑनरी कैप्टन अकरम खान, ऑनरी लेफ्टीनेंट प्रेम कुमार, सुबेदार लखविंदर सिंह, नायक संदीप कुमार और नायक खगेश्वर प्रसाद) को शील्ड एवं शाल भेंट कर सम्मानित किया।

प्रभारी डीएम अभिषेक कुमार ने कहा कि आज का दिन सिर्फ जीत को याद करने का नहीं है, बल्कि सेना के उन जवानों की वीरता, शौर्य और अदम्य साहस को याद करने का दिन है जिनके सजदे में देशवासियों का सिर हमेशा से झुकता आया है। आज पूरी देश करगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सपूतो को याद कर रहा है। डीएम ने कारगिल दिवस की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कारगिल युद्ध में जवानों की योगदान को रेखांकित किया। एनसीसी कैडेट्स सेना के शौर्य को जानने के लिए उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी पढ़ें। पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों को कोई असुविधा न हो इसका पूरी अफसर की टीम की ओर से हर संभव प्रयास करेंगे। एडीएम ने कहा कि कारगिल जैसा कठिन युद्ध होने के बाद भी देश के सैनिकों ने बहादुरी को परिचय देते हुए देश की सरहदों को दुश्मनों से मुक्त करवाया।

पुरानी पेंशन व्यवस्था अब मुमकिन नहीं: वित्त सचिव सोमनाथन

नई दिल्ली। वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था अब वित्तीय रूप से मुमकिन नहीं है और इसे लाना देश के उन नागरिकों के लिए नुकसानदेह होगा, जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं। एनपीएस (नई पेंशन प्रणाली) को लेकर कर्मचारी संगठनों और राज्य सरकारों से कुछ सार्थक बातचीत हुई है। सोमनाथन ने कहा कि सरकार देश में युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने के मकसद से उन्हें कंपनियों में प्रशिक्षण देने की सुविधा के अलावा 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) को आधुनिक रूप भी देगी।

सोमनाथन ने पीटीआई-भाषा से विशेष बातचीत में कहा, एनपीएस पर बनी समिति का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। हमने इस बारे में कर्मचारी संगठनों और राज्य सरकारों से बातचीत की है। इसमें कुछ प्रगति हुई है। उन्होंने कहा, कर्मचारियों की कुछ चिंताएं हैं। पहला, उनका कहना है कि यह नई योजना है। एनपीएस शेयर बाजार से जुड़ा है, हमें उतार-चढ़ाव नहीं चाहिए। उनका कहना है कि यह स्पष्ट हो कि कितनी पेंशन मिलेगी। दूसरा, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद जो भी पेंशन मिले उसमें महंगाई से निपटने का भी कुछ प्रावधान यानी डीए (महंगाई भत्ता) जैसी कोई व्यवस्था चाहिए। ऐसा नहीं होने पर पेंशन का वास्तविक मूल्य घटता जाएगा। तीसरा, अगर किसी ने पूरी नौकरी यानी 30 साल तक काम नहीं किया है, उसके लिए कुछ न्यूनतम पेंशन तय की जाए। ए ऐसे मामले हैं, जिस पर हमें निर्णय लेना है। उन्होंने कहा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था वित्तीय रूप से मुमकिन नहीं है। पुरानी पेंशन लाना देश के उन नागरिकों के लिए नुकसानदेह होगा, जो सरकारी नौकरी में नहीं हैं।

वित्त मंत्रालय ने पिछले साल सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना की समीक्षा करने और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जरूरत के हिसाब से बदलाव का सुझाव देने के लिए वित्त सचिव की अगुवाई में एक समिति का गठन किया था।

एक सवाल के जवाब में सोमनाथन ने कहा, बजट में महत्वपूर्ण रोजगार पर जोर देना है। एक तरफ जहां वित्तीय सहायता के जरिए रोजगार सृजन पर जोर है वहीं दूसरी तरफ रोजगार गहन क्षेत्र एमएसएमई और कौशल विकास के लिए कदम उठाए गए हैं। कौशल विकास के तहत हम देश में युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने के मकसद से उन्हें कंपनियों में प्रशिक्षण देने की सुविधा के अलावा1,000 आईटीआई को आधुनिक बनाएंगे। कौशल विकास के तहत केंद्र, राज्य और उद्योग के सहयोग से आईटीआई को आधुनिक रूप दिया जाएगा। उद्योग में जो आधुनिक मशीनरी, कामकाज का तरीका है उसे आईटीआई में शामिल किया जाएगा। अच्छे प्रशिक्षकों को भी जोड़ा जाएगा। इसका मकसद बेहतर प्रशिक्षण देना है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सप्ताह मंगलवार को पेश बजट में संगठित क्षेत्र में आने वाले नए कामगारों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के जरिए तीन योजनाओं की घोषणा की। रोजगार को बढ़ावा देने के मकसद से लाई गई इन योजनाओं के लिए कुल 1.07 लाख करोड़ रुपए का निर्धारण किया गया है। इससे अगले पांच साल में 2.90 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। एक करोड़ युवाओं को कंपनियों में प्रशिक्षण और 20 लाख को आईआईटी में प्रशिक्षण देने की भी घोषणा की गई है।

बजट में नई पीढ़ी के सुधारों और राज्यों के सहयोग से जुड़े सवाल के जवाब में वित्त सचिव ने कहा, सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए, राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा। राजकोषीय उपायों के जरिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। आर्थिक समीक्षा में खाद्य महंगाई को मौद्रिक नीति से अलग करने के बारे में पूछे जाने पर सोमनाथन ने कहा, यह सोचने वाली बात है। अर्थशास्त्रियों की अलग-अलग राय हैं। इस पर चर्चा की जा सकती है। इसी सप्ताह पेश आर्थिक समीक्षा में कहा गया कि खाद्य पदार्थों को छोड़कर, महंगाई का लक्ष्य तय करने पर विचार किया जाना चाहिए। प्राय: खाद्य वस्तुओं की ऊंची कीमतें मांग के बजाय आपूर्ति की समस्या के कारण होती हैं। आरबीआई मौद्रिक नीति पर विचार करते समय मुख्य रूप से खुदरा मुद्रास्फीति पर विचार करता है। खाद्य महंगाई ऊंची होने से नीतिगत दर में पिछले साल अप्रैल से कोई बदलाव नहीं किया गया है। एक अन्य सवाल के जवाब में सोमनाथन ने कहा, बजट में सभी का ध्यान रखा गया है। मुझे नहीं लगता बहुत लोग इससे नाराज हैं। कुछ हो सकते हैं। हर बजट में कुछ प्राथमिकताएं होती हैं, इसमें भी वही हैं। इसमें सभी का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि बजट में विकसित भारत के लिए, रोजगार सृजन के साथ-साथ पूंजीगत निवेश और राजकोषीय सूझ-बूझ के साथ नवोन्मेष, अनुसंधान एवं विकास तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए कदम उठाए गए हैं।

धनखड़ ने कार्यस्थगन प्रस्ताव को लेकर सत्ता पक्ष के सदस्यों को लिया आड़े हाथ

भाषा। नई दिल्ली

राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा कर्नाटक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा कराए जाने पर जोर दिए जाने के कारण उन्हें आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सभापति द्वारा इस बारे में स्पष्ट व्यवस्था दिए जाने के बावजूद आसन पर दबाव बनाना ठीक नहीं है। उच्च सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद शून्यकाल में सभापति धनखड़ ने कहा कि उन्हें आज भाजपा सदस्य ईरण्ण कडाडी, सुधांशु त्रिवेदी, नरेश बंसल और बृजलाल के नियम 267 के तहत चार नोटिस मिले हैं। यह नोटिस कर्नाटक में महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति कार्पोरेशन में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मिले हैं।

उन्होंने कहा कि यह सभी नोटिस नियम 267 के बारे में उनके द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों की स्पष्ट अनदेखी है। सभापति ने कहा कि उन्होंने इस बारे में सदन में स्पष्ट व्यवस्था दी थी और उसके बाद पिछले दो दिन कार्य स्थगन प्रस्ताव के कोई नोटिस नहीं आए।

धनखड़ ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के सदस्य कडाडी ने एक ऐसे मुद्दे पर नियम 267 के तहत नोटिस दिया जिसे वह शून्यकाल में पहले ही उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोई मुद्दा सदस्यों के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है, फौरी महत्व का हो सकता है किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि इसे इसे नियम 267 के तहत सदन में उठाए। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के कई सदस्यों द्वारा शोरशराबा करने के बीच सभापति ने संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू को बोलने का अवसर दिया। रीजीजू ने कहा कि यद्यपि सभापति ने नियम 267 के नोटिसों के बारे में स्पष्ट व्यवस्था दी है किंतु यह एक अत्यंत महत्व का विषय जिससे कुछ सदस्य आंदोलित हैं और इसीलिए उन्होंने यह नोटिस दिया।

सभापति ने रीजीजू को टोकते हुए कहा कि वह नोटिस पर न बोलें क्योंकि ठीक इसी तरह उन्होंने पूर्व में सदन में नेता प्रतिपक्ष को भी इसी कारण नहीं बोलने दिया था। इसके उपरांत सत्ता पक्ष के सदस्य शांत होकर बैठ गए तथा विभिन्न सदस्यों ने आसन की अनुमति से शून्यकाल में लोक महत्व के विषय उठाने शुरू कर दिए। सभापति ने बाद में शून्यकाल के दौरान कडाडी को कर्नाटक में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया। विपक्ष, खासकर कांग्रेस के सदस्यों ने इसका जोरदार विरोध किया। विरोध और हंगामे के बीच कडाडी ने कन्नड में अपनी बात रखी।

भाजपा नेता प्रभात झा का गुरुग्राम के मेदांता मेडिसिटी अस्पताल में निधन

गुरुग्राम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा का शुक्रवार की सुबह 5 बजे यहां मेदांता मेडिसिटी में निधन हो गया। वे 67 वर्ष के थे और कई दिन से बीमार चल रहे थे। उनकी तबियत में कुछ खास सुधार नहीं हो पाया। बिहार के दरभंगा जिला के गांव हरिहरपुर में प्रभात झा का जन्म 4 जून 1957 को हुआ था। बाद में वे वे परिवार के साथ मध्य प्रदेश के गवालियर में आकर रहने लगे थे। वे भाजपा के मुखपत्र कमल संदेश के संपादक भी रहे। कई पुस्तकों की उन्होंने रचना की। रंजना झा से उनका विवाह हुआ था। उनके दो बेटे तुष्मुल झा व अयत्न झा हैं। प्रभात झा भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे थे। बाद में पार्टी ने राज्यसभा सांसद भी बनाया। प्रभात झा पेशे से एक पत्रकार थे। पत्रकारिता के बाद उन्होंने राजनीति में किस्मत आजमाई।

पिछले कई दिनों से वे बीमार चल रहे थे। परिजनों की ओर से जानकारी दी गई कि पहले उनका भोपाल के बंसल अस्पताल में इलाज करवाया था। वहां दो दिन रखा गया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। दो दिन बार एयरलिफ्ट करके उन्हें गुरुग्राम मेदांता मेडिसिटी में लाया गया। उनके बेटे अयत्न ने निधन की जानकारी सांझा की। साथ ही कहा कि अंतिम संस्कार ग्वालियर या पैतृक गांव कोरियाही, सीतामढ़ी (बिहार) में होगा। उनके निधन पर राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

मानसून सत्र के अंतिम दिन आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष का सदन से बहिर्गमन

भाषा। पटना

बिहार विधानसभा में शुक्रवार को राज्य के संशोधित आरक्षण कानूनों को लेकर पेश एक निजी विधेयक पर मतदान कराने की मांग अस्वीकार किए जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को निजी विधेयक के जरिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी- मार्क्सवादी-लेनिनवादी (भाकपा-माले) के विधायक अजीत कुमार सिंह ने आरक्षण में संशोधन को लेकर पारित दो कानूनों को संविधान की नौवीं अनुसूची में डाले की मांग की। इन दोनों संशोधित कानूनों में वंचित वर्गों के लिए कोटा बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का प्रावधान किया गया था।

बिहार विधानसभा परिसर में बाद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राष्ट्रीय जनता दल (राजद) विधायक भाई वीरेंद्र ने निजी विधेयक पर सरकार के जवाब से असंतुष्ट होने की स्थिति में मतदान का प्रावधान होने का दावा करते हुए आरोप लगाया कि मत विभाजन की विपक्ष की मांग को अध्यक्ष ने सरकार के इशारे पर खारिज कर दिया।

राजद विधायक ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन में साझेदार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), दलितों के आरक्षण का विरोध करती रही है। विधानसभा के मौजूदा अध्यक्ष नंद किशोर यादव भाजपा से आते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में बने रहने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनकी गोदी में बैठकर किलकारी भर रहे हैं।

नीतीश कुमार के नेतृत्व वाल पिछली महागठबंधन सरकार ने जाति आधारित गणना कराया था जिसके मुताबिक राज्य में पिछड़े वर्ग, दलित और आदिवासियों की कुल आबादी में हिस्सेदारी करीब दो तिहाई है। इसके बाद तत्कालीन महागठबंधन सरकार ने इन वर्गों का आरक्षण बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया था।

इन आरक्षण कानूनों को नौवीं अनुसूची में रखे जाने से ए न्यायिक समीक्षा से मुक्त हो जाएंगे और राज्य सरकार की ओर से इसके लिए अनुरोध केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के समक्ष लंबित है। इस बीच, पटना उच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण में की बढ़ोतरी को खारिज कर दिए जाने के बाद राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को दिन भर की कार्यवाही समाप्त होने पर दोनों सदनों को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।

बिहार विधानसभा का सत्र स्थगित किए जाने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा, विपक्ष उस व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रहा है जो स्टेशन पर देर से पहुंचता है और ट्रेन छूटने के बाद ट्रेन के पीछे भागता है।

उन्होंने आरोप लगाया, वे हताश हैं कि जाति सर्वेक्षण और आरक्षण में बढ़ोतरी का श्रेय मुख्यमंत्री को मिल रहा है। वे कुछ सुर्खियां बटोरना चाहते थे। जब केंद्र से इन्हें नौवीं अनुसूची में डाले जाने के लिए पहले ही अनुरोध किया जा चुका है, तो इस मुद्दे को फिर से उठाना बेतुका है। चौधरी ने बताया कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद संशोधित आरक्षण कानून प्रभावी नहीं रह गए हैं। पुराने कानून जिसके तहत आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत निर्धारित की गई है, लागू रहेंगे। यह एक तकनीकी बात है जिसे विपक्ष को समझना चाहिए। बिहार विधानमंडल के पांच दिवसीय मानसून सत्र के दौरान कुल मिलाकर सात विधेयक पारित किए गए जिनमें से दो का उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्रों के लीक और अन्य गड़बड़ियों को रोकना है।

घोटालों और धन की हेराफेरी कर कर्नाटक को दिवालियापन की ओर धकेल रही कांग्रेस: भाजपा

भाषा। नई दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए घोटालों और धन की हेराफेरी कर राज्य को दिवालियापन की ओर धकेल रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की राज्य में दो कथित घोटालों में संलिप्तता का दावा करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इन मामलों में शामिल कुछ लोगों को बचाने के लिए भाजपा सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा में मुद्दा नहीं उठाने दिया। राज्यसभा में शुक्रवार को शून्यकाल के दौरान उस समय हंगामा हुआ जब सभापति जगदीप धनखड़ ने कर्नाटक में भ्रष्टाचार से संबंधित एक मुद्दे पर चर्चा के लिए सदन के सूचीबद्ध कामकाज को निलंबित करने के भाजपा सदस्यों के नोटिस को खारिज कर दिया। धनखड़ ने हालांकि भाजपा के एक सदस्य को शून्यकाल के दौरान सदन में मामला उठाने की अनुमति दी। लोकसभा में झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने संबंधी टिप्पणी और कर्नाटक सरकार के एक मंत्री से जुड़े कथित घोटालों को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के बीच कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी।

संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत में जोशी ने कहा, कर्नाटक एक प्रगतिशील राज्य है लेकिन अस्पतालों में दवाएं नहीं हैं, वहां उचित सड़कें नहीं हैं। इस बार भारी बारिश के कारण कई मकान ढह गए और पानी लोगों के घरों में प्रवेश कर गया, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं दी। धारवाड़ के सांसद ने दावा किया कि राज्य परिवहन की बसें इसलिए खड़ी हैं कि उन्हें चलाने के लिए डीजल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। जोशी ने कहा, कांग्रेस के शासन में कर्नाटक में दो-तीन घोटाले हुए और मुख्यमंत्री इनमें से दो घोटालों में सीधे तौर पर संलिप्त हैं।

केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि प्रगतिशील और फलते-फूलते राज्य कर्नाटक को कांग्रेस सरकार दिवालिया होने की ओर धकेल रही है और राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए आवंटित धन का इस्तेमाल गारंटी (कांग्रेस के चुनावी वादे) को लागू करने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सदस्यों ने भाजपा सांसदों को शुक्रवार को संसद में मुद्दे नहीं उठाने दिए क्योंकि कर्नाटक की मौजूदा स्थिति के लिए पार्टी आलाकमान जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भ्रष्ट है। यही कारण है कि उन्होंने भाजपा सदस्यों को राज्यसभा में यह मुद्दा नहीं उठाने दिया। लोकसभा में उन्होंने हंगामा किया। इसका मतलब है कि कांग्रेस आलाकमान की भी इसमें (घोटालों में) हिस्सेदारी थी।

भाजपा ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुडा) और कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम से जुड़े कथित घोटालों में सिद्धारमैया की संलिप्तता का दावा करते हुए कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। विवादास्पद योजना में लेआउट बनाने के लिए अधिग्रहित अविकसित भूमि के बदले में भूमि खोने वाले को 50 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित करने की परिकल्पना की गई है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा के राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासन में कर्नाटक में भ्रष्टाचार और अराजकता चरम पर है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजाति से जुड़े कोष का तथाकथित गारंटी के लिए इस्तेमाल किया। भ्रष्टाचार के माध्यम से राजनीतिक और व्यक्तिगत हितों के लिए सबसे वंचित वर्ग के उत्थान से जुड़ी निधियों का उपयोग एक बहुत ही गंभीर, संवेदनशील और दर्दनाक मुद्दा है। हम इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा करने का आरोप लगाया।

यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी सूरज रेवन्ना ने कहा, सच्चाई 15-20 दिन में सामने आ जाएगी

मैसुरु (भाषा)। कुछ पुरुषों के यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे और जमानत पर बाहर आए जनता दल (सेक्युलर) के विधान पार्षद सूरज रेवन्ना ने शुक्रवार को कहा कि 15 से 20 दिन में उन सभी लोगों का पर्दाफाश हो जाएगा जो उनके और उनके परिवार के खिलाफ साजिश का हिस्सा थे। रेवन्ना ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और सच्चाई जल्द सामने आ जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के पोते सूरज रेवन्ना ने मैसुरु में देवी चामुंडेश्वरी की पूजा करने के बाद संवाददाताओं से कहा, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। इसलिए हम सभी इतने आश्वस्त हैं। सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। समय इसका जवाब देगा। सूरज ने कहा, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि सच्चाई लंबे समय तक छिप नहीं सकती। इस साजिश में शामिल सभी लोग बेनकाब होंगे। बस 15 से 20 दिन इंतजार कीजिए। चामुंडी हिल्स की अपनी यात्रा के बारे में जद (एस) विधान पार्षद ने कहा कि यह एक पारिवारिक परंपरा है कि हर साल वह अपने माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ देवी की पूजा करने के लिए चामुंडेश्वरी मंदिर जाते हैं। सूरज रेवन्ना को यौन उत्पीड़न मामले में दो दिन पहले ही जमानत पर रिहा किया गया था। सूरज को जद (एस) कार्यकर्ता की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि उन्होंने उसका यौन उत्पीड़न किया। सूरज के छोटे भाई प्रज्वल रेवन्ना पर भी कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है और वह जेल में हैं।

स्वर्ण उद्योग की मांग एक राष्ट्र, एक दर, पूर्वी भारत से होगी शुरुआत

भाषा। कोलकाता

स्वर्ण आभूषण उद्योग एक राष्ट्र, एक दर नीति की वकालत कर रहा है, जिसकी शुरुआत अगस्त से पूर्वी भारत के लिए समान दर लागू करने के साथ की जाएगी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। स्वर्ण शिल्प बचाओ समिति के अध्यक्ष समर कुमार डे ने कहा कि सभी हितधारकों ने देश भर में एक समान सोने की दर के विचार में रुचि दिखाई है।

डे ने कहा, हम अगस्त से बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एकल दर की शुरुआत करेंगे। इस पहल में हमने सर्राफा विक्रेताओं को भी शामिल कर लिया है। अखिल भारतीय रत्न एवं आभूषण घरेलू परिषद (जीजेसी) के चेयरमैन संयम मेहरा ने कहा, इसका मकसद सभी हितधारकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना और मूल्यह्रास को रोकना है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में सोने और चांदी पर आयात शुल्क 15 प्रतिशत से घटाकर छह प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा था। उद्योग जगत के लोगों ने कहा कि शुल्क में भारी कटौती से अवैध आयात को खत्म करने में मदद मिलेगी।

हीरा आयातक सनी ढोलकिया ने कहा, कुल 950 टन आयात में से 100 टन सोने की तस्करी किए जाने का अनुमान है। हालांकि, उद्योग सूत्रों ने बताया कि इस बात को लेकर चिंता है कि क्या सरकार के पास सोने से संबंधित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में कोई अन्य योजना है। जीजेसी ने जीएसटी परिषद से आभूषणों पर कर की दर मौजूदा तीन प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने की अपील की है।

पांच वर्ष से कम आयु के 36 प्रतिशत बच्चे बौने: महिला एवं बाल विकास मंत्री

भाषा। नई दिल्ली

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि 0-5 वर्ष आयुवर्ग के लगभग 17 प्रतिशत बच्चे कम वजन वाले हैं, जबकि 36 प्रतिशत बच्चे बौने और छह प्रतिशत कमजोर (शक्तिक्षीण) हैं। शून्य से पांच वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में बौनापन, शक्तिक्षीणता और कम वजन कुपोषण के मुख्य संकेतक हैं। बौनापन से तात्पर्य उन बच्चों से है जो अपनी उम्र के हिसाब से बहुत छोटे होते हैं। ऐसा आमतौर पर दीर्घकालिक कुपोषण के कारण होता है।

शक्तिक्षीण बच्चों का तात्पर्य उन बच्चों से है, जो अपनी लंबाई के हिसाब से बहुत पतले हैं, जो गंभीर रूप से कम वजन के कारण तीव्र कुपोषण का संकेत देते हैं। ऐसे बच्चों का वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम होता है, जिसमें बौनापन और शक्तिक्षीणता दोनों शामिल हैं और यह दीर्घकालिक या तीव्र कुपोषण या दोनों को दर्शाता है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि जून 2024 के पोषण ट्रैकर के आंकड़ों के अनुसार, छह वर्ष से कम उम्र के लगभग 8.57 करोड़ बच्चों की लंबाई मापी गई, जिनमें से 35 प्रतिशत बौने पाए गए वहीं 17 प्रतिशत कम वजन वाले और पांच वर्ष से कम उम्र के छह प्रतिशत बच्चे शक्तिक्षीण पाए गए।

उन्होंने राज्यवार आंकड़े भी साझा किए, जिसके अनुसार बौनेपन की सर्वाधिक 46.36 प्रतिशत दर उत्तर प्रदेश में है, जिसके बाद लक्षद्वीप में यह दर 46.31 प्रतिशत है। आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बौनेपन की दरें क्रमश: 44.59 प्रतिशत और 41.61 प्रतिशत दर्ज की गई हैं। बिहार और गुजरात में बच्चों में शक्तिक्षीणता की दर क्रमश: 9.81 प्रतिशत और 9.16 प्रतिशत है। कम वजन वाले बच्चों के मामले में, मध्य प्रदेश 26.21 प्रतिशत के साथ सबसे आगे है, इसके बाद दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव 26.41 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

पेज 1 का शेष

पाकिस्तान ने...

पूर्व सैनिकों को 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक दिए गए। उन्होंने आगे पिछली सरकारों की उपेक्षा की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के 7 दशक बाद भी शहीदों के लिए युद्ध स्मारक नहीं बनाया, सीमा पर तैनात हमारे सैनिकों को पर्याप्त बुलेटप्रूफ जैकेट उपलब्ध नहीं कराई और अपने पास रखा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ लद्दाख के उपराज्यपाल, ब्रिगेडियर (डॉ.) बी डी शर्मा, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री, संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल अनिल चौहान और तीनों सशस्त्र बलों के सेना प्रमुख उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने गौरव गाथा सुनी-एनसीओ द्वारा कारगिल युद्ध पर ब्रीफिंग और अमर संस्मरण- हट ऑफ रिमेंबरेंस का दौरा किया। उन्होंने वीरभूमि का भी दौरा किया।

कांवड़ मार्ग...

कहा कि उन्होंने अपना जवाब दाखिल कर दिया है और उनका कहना है कि संबंधित निर्देश कानून के तहत अनिवार्य हैं। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि इस मामले पर अगले सोमवार को सुनवाई की जाए, अन्यथा यह मुद्दा निरर्थक हो जाएगा। सोमवार को शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ होती है, खासकर श्रावण के महीने में। उन्होंने कहा, हमें एकपक्षीय आदेश का सामना करना पड़ा और बिना सुनवाई के आदेश पर रोक लगा दी गई। उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेश केंद्रीय कानून के अनुरूप नहीं है। पीठ ने कहा कि यदि भोजनालयों और दुकानों को नियंत्रित करने वाला कोई कानून है तो राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में इसे लागू करना चाहिए। न्यायमूर्ति रॉय ने रोहतगी से कहा, कानून को पूरे राज्य में लागू किया जाए, न कि केवल कुछ क्षेत्रों में। कृपया एक हलफनामा दाखिल करें जिसमें दिखाया जाए कि कानून को पूरे राज्य में लागू किया गया है। तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि यदि नाम और अन्य विवरण प्रदर्शित करने संबंधी यह कानून पिछले 60 वर्षों से लागू नहीं किया गया है, तो इस मुद्दे को समय आने पर उठाया जा सकता है और निर्देश लागू किए बिना यात्रा जारी रहने दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार का जवाब उन्हें कल (बृहस्पतिवार) रात साढ़े दस बजे दिया गया और उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। उत्तराखंड के उप महाधिवक्ता जतिंदर कुमार सेठी ने कहा कि राज्य ने कांवड़ यात्रा के संबंध में कोई विशेष आदेश जारी नहीं किया है और सरकार केवल उस कानून को लागू कर रही है, जिसके तहत सभी त्योहारों के दौरान भोजनालयों के नाम का खुलासा करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा एक वार्षिक तीर्थयात्रा है जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं और किसी भी शरारत से बचने के लिए राज्य को कानून लागू करने की जरूरत है। सेठी ने पीठ से आग्रह किया कि राज्य को दो कानूनों को लागू करने के लिए कार्वाई की अनुमति दी जाए, जिसके तहत दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अपने पंजीकरण प्रमाण पत्र और पहचान पत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत का अंतरिम आदेश उन कानूनों को लागू करने में बाधा बन रहा है। उन्होंने जिन दो कानूनों का उल्लेख किया वे हैं: खाद्य सुरक्षा और मानक (पंजीकरण और लाइसेंसिंग) विनियम, 2011 (एक केंद्रीय कानून) और उत्तराखंड पंचायती राज उपनियम। सेठी ने कहा, अगर कानून को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया तो हमें कानून-व्यवस्था की समस्या की आशंका है।

सुप्रीम कोर्ट...

लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार ने मार्च में शीर्ष अदालत का रुख किया था और आरोप लगाया था कि विधानसभा द्वारा पारित कुछ विधेयकों को राज्यपाल ने राष्ट्रपति के पास भेज दिया था और ये अब भी मंजूरी के लिए लंबित हैं। पश्चिम बंगाल ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि राज्यपाल आठ विधेयकों पर मंजूरी नहीं दे रहे हैं। केरल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता के के वेणुगोपाल ने कहा , यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पीठ ने कहा, हम दोनों मामलों में राज्यपालों के सचिव और केंद्र को नोटिस जारी कर रहे हैं। वेणुगोपाल ने कहा, यह विधेयक पिछले आठ महीनों से लंबित हैं। मैं राष्ट्रपति को (विधेयक) भेजे जाने को ही चुनौती दे रहा हूं... राज्यपालों के बीच भ्रम की स्थिति है। वे विधेयकों को लंबित रखते हैं। यह संविधान के खिलाफ है।

क्रिकेट...

डालते हुए 10 रन देकर तीन विकेट चटकाए। उन्होंने बांग्लादेश के शीर्ष क्रम को झकझोरा तो वहीं राधा ने मध्यक्रम के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी पर नचाया। बांग्लादेश के लिए कप्तान निगार सुल्ताना ने 51 गेंद में 32 जबकि शोर्ना अख्तर ने नाबाद 19 रन का योगदान दिया। दोनों ने सातवें विकेट के लिए 36 रन की साझेदारी कर टीम को मुश्किल स्थिति से बाहर निकाला। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया लेकिन रेणुका ने पहले ओवर में ही छक्का खाने के बाद दिलारा अख्तर (06) को चलता किया। दिलारा के एक और बड़ा शॉट खेला लेकिन यह डीप मिडविकेट पर खड़ी उमा छेत्री को पार करने के लिए काफी नहीं था। उन्होंने अपने अगले दो ओवरों में इश्मा तंजीम (08) और मुर्शिदा खातून (04) को चलता किया जिससे पावरप्ले में बांग्लादेश की टीम तीन विकेट पर 25 रन ही बना सकी। कप्तान सुल्ताना ने एक छोर से पारी को संभालने की कोशिश की। भारतीय गेंदबाजों ने सातवें से 10वें ओवर के बीच सात रन खर्च किए और इस दौरान राधा ने रूमाना अहमद (01) को आउट कर शिकंजा और कस दिया। भारतीय स्पिनरों की सटीक लाइन लेंथ का बांग्लादेश के बल्लेबाजों के पास कोई जवाब नहीं था। गत चैम्पियन भारत का क्षेत्ररक्षण में काफी सुधार दिखा। शेफाली ने पूजा वस्त्राकर की गेंद पर राबिया खान (01) का डाइव लगाकर शानदार कैच लपका। दीप्ति की गेंद पर रितु मोनी (05) को विकेटकीपर रिचा घोष ने स्टंप किया।सुल्ताना को इसके बाद शोर्ना के रूप में अच्छा साथ मिला और दोनों ने 35 गेंद में 36 रन की साझेदारी कर टीम को कुछ हद तक संघर्ष करने लायक स्कोर तक पहुंचाया। राधा ने दीप्ति के हाथों कैच कराकर सुल्ताना को पवेलियन की राह दिखाई।

असम...

लेकिन केवल 30 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और असम राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित हैं। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग के सलाहकार और पर्यटक गाइड ट्रेनर रंजन के बरुआ ने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में चराइदेव मोइदम्स को शामिल किए जाने की सराहना करते हुए इसे असम और उससे आगे के लोगों के लिए बेहद गर्व का क्षण बताया। उन्होंने टिप्पणी की, ये उल्लेखनीय स्थल अहोम राजवंश की विरासत की भव्यता का प्रतीक हैं और मिस्र के पिरामिडों के समान एक वास्तुशिल्प चमत्कार के रूप में खड़े हैं। बरुआ ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या इसी तरह के संस्थानों द्वारा आगे की खोज से अहोम राजवंश की समृद्ध विरासत में अतिरिक्त अंतर्दृष्टि का पता चल सकता है, जिससे इस ऐतिहासिक खजाने के बारे में हमारी समझ समृद्ध होगी।ताई-अहोम 13वीं शताब्दी में वर्तमान असम में चले गए और उन्होंने चराइदेव को अपनी पहली राजधानी और शाही क़ब्रिस्तान के लिए स्थान के रूप में चुना। उन्होंने पूर्वी भारत में पटकाई पहाड़ियों पर पहली राजधानी स्थापित की और इसका नाम चराइदेव रखा, जिसका उनकी भाषा में अर्थ है पहाड़ के ऊपर एक चमकदार शहर। भले ही कबीले शहरों में चले गए, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए दफन स्थल को राजघरानों की दिवंगत आत्माओं के लिए सबसे पवित्र स्थान के रूप में देखा जाता था।यूनेस्को की वेबसाइट के अनुसार, इस स्थल पर इन गुंबददार टीलों की कब्रगाहों की सबसे बड़ी सघनता है और यह आसपास की पहाड़ियों के मूर्तिकला परिदृश्य को दर्शाता है। मोइदाम की विशेषता गुंबददार कक्ष हैं, जो अक्सर दो मंजिला होते हैं, जिनमें धनुषाकार मार्गों से पहुंचा जा सकता है। कक्षों में केंद्रीय रूप से ऊंचे मंच थे जहां मृतकों को उनके शाही प्रतीक चिन्ह, हथियारों और व्यक्तिगत सामानों के साथ दफनाया जाता था। इन टीलों के निर्माण में ईंटों, मिट्टी और वनस्पति की परतें शामिल थीं, जिससे परिदृश्य दिव्य पर्वतों की याद दिलाने वाली लहरदार पहाड़ियों में बदल गया। मृतक द्वारा अपने जीवन के दौरान उपयोग की जाने वाली कई वस्तुएं, जैसे शाही प्रतीक चिन्ह, लकड़ी, हाथीदांत या लोहे से बनी वस्तुएं, सोने के पेंडेंट, चीनी मिट्टी के बर्तन, हथियार, इंसानों की हद तक कपड़े (केवल लुक-खा-खुन कबीले से)) वेबसाइट के अनुसार, उन्हें उनके राजा के साथ दफनाया गया था। पूर्वोत्तर राज्य में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान क्रमश: प्राकृतिक और मिश्रित विरासत श्रेणियों में आते हैं।

मध्य प्रदेश सरकार पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर कोटा लागू करेगी:मुख्यमंत्री

भाषा। भोपाल

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को घोषणा की कि उनकी सरकार पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करेगी। उन्होंने यह घोषणा करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की 25वीं वर्षगांठ पर की।अग्निवीर, अग्निपथ योजना के तहत सेना के तीनों अंगों में चार साल के लिए सैनिकों की तैनाती की जाती है। यादव ने संवाददाताओं से कहा, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इच्छा के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस और सशस्त्र बलों में अग्निवीरों को आरक्षण देने का फैसला किया है। अग्निवीर योजना वास्तव में न केवल सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने और सक्षम जवानों की भर्ती करने का प्रयास है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर युवा बनाने का भी प्रयास है'' उन्होंने कहा, ''हम इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की भावनाओं के साथ चलेंगे'' इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अग्निपथ योजना सेना द्वारा किए गए आवश्यक सुधारों का एक उदाहरण है और विपक्ष पर सशस्त्र बलों में औसत आयु को युवा बनाए रखने के उद्देश्य से भर्ती प्रक्रिया पर राजनीति करने का आरोप लगाया ।करगिल युद्ध में विजय की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए द्रास में कारगिल विजय दिवस पर अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि कुछ लोग राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने इस दावे को खारिज कर दिया कि पेंशन राशि बचाने के लिए अग्निपथ योजना शुरू की गई है।उन्होंने कहा, योजना शुरू की गई है।उन्होंने कहा, अग्निपथ का उद्देश्य सेनाओं को युवा बनाना है...अग्निपथ का उद्देश्य सेनाओं को लगातार युद्ध के लिए फिट रखना है।

छत्तीसगढ़ सरकार पुलिस और वनरक्षक भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण देगी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को घोषणा की कि उनकी सरकार पुलिस आरक्षक, वन रक्षक और अन्य पदों की भर्ती में राज्य के अग्निवीरों को आरक्षण देगी। विधानसभा परिसर में संवाददताओं से बात करते हुए साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के अग्निवीर जब भारतीय सेना में अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तब छत्तीसगढ़ सरकार इन नौजवानों को पुलिस सेवा में आरक्षक, वन सेवा में वन रक्षक और जेल प्रहरी इत्यादि पदों में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी। साय ने कहा, अग्निवीरों को इसके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश हमारी सरकार शीघ्र ही जारी करने जा रही है।

आईटीबीपी के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे अग्निवीर: महानिदेशक

नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की रक्षा के लिए तैनात आईटीबीपी के लिए अग्निवीर बहुत उपयोगी साबित होंगे। यह बात केंद्रीय बल के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को कही। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक (डीजी) राहुल रसगोत्रा ने गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में कहा कि इन ''अच्छी तरह प्रशिक्षित और अनुशासितै सैनिकों की भर्ती के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं, जो सेना से सीमा सुरक्षा पुलिस बल में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि जैसा कि ज्ञात है, आईटीबीपी और सेना के जवान भारत-चीन सीमा की रक्षा करते हैं और इसलिए ''ए अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुशासित अग्निवीर, सीमा सुरक्षा पुलिस बल के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। आईटीबीपी महानिदेशक ने कहा कि सीमा सुरक्षा पुलिस बल ''का मानना है कि अग्निवीरों के शामिल होने से आईटीबीपी को एक नई ऊर्जा मिलेगी और उसे उनसे लाभ होगा। रसगोत्रा ने कहा कि अग्निवीरों को शामिल करने के लिए आईटीबीपी के भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है और वे आयु और शारीरिक दक्षता परीक्षण में छूट के लिए पात्र होंगे। यह बयान ऐसे समय में आया है, जब सेना, नौसेना और वायुसेना में कर्मियों की अल्पकालिक भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना पर नए सिरे से चर्चा हो रही है। सरकार ने सेना के तीनों अंगों में औसत आयु वर्ग को युवा रखने के उद्देश्य से 2022 में अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी। इस योजना में साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को चार साल की अवधि के लिए अग्निवीर के रूप में भर्ती करने का प्रावधान है, जिसमें से 25 प्रतिशत को अगले 15 वर्षों तक बनाए रखने का प्रावधान है। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इस योजना को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि चार साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद शेष 75 प्रतिशत अग्निवीरों का क्या होगा। लगभग 90,000 कर्मियों वाली आईटीबीपी को मुख्य रूप से चीन के साथ लगती 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) की रखवाली करने के अलावा कई तरह की आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी भी निभानी होती है।

उच्चतम न्यायालय ने असम के निरुद्ध केंद्र में सुविधाओ की कमी को लेकर चिंता जताई

नई दिल्ली। (भाषा) असम में विदेशी घोषित किए गए लोगों के लिए बनाए गए एक निरुद्ध केंद्र की दयनीय स्थिति पर चिंता जताते हुए उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वहां पर्याप्त जल आपूर्ति, उचित स्वच्छता और पर्याप्त शौचालय सुविधाओं जैसी आवश्यक सेवाओं की कमी है। न्यायालय ने कहा कि उसने असम के मटिया स्थित निरुद्ध (डिटेंशन) केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति के बारे में असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया है। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा, हमने पाया है कि सुविधाओं का अभाव हैं, यहां पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं है, उचित साफ-सफाई नहीं है, पर्याप्त शौचालय सुविधाएं नहीं हैं। पीठ विदेशी घोषित किए गए लोगों के निर्वासन और असम में निरुद्ध केंद्रों में प्रदान की गई सुविधाओं से संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि रिपोर्ट में भोजन और चिकित्सा सहायता की उपलब्धता के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। न्यायालय ने असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्देश दिया कि वह केन्द्र में आपूर्ति किए जाने वाले भोजन की मात्रा और गुणवत्ता, रसोईघर में साफ-सफाई, तथा चिकित्सा एवं अन्य सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक बार और वहां का दौरा करें।

आयकर विभाग ने अचल संपत्ति पर एलटीसीजी गणना को लेकर जारी किया स्पष्टीकरण

नई दिल्ली। (भाषा) आयकर विभाग ने कहा है कि दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर की गणना के उद्देश्य से वर्ष 2001 से पहले खरीदी गई अचल संपत्तियों के अधिग्रहण की लागत एक अप्रैल 2001 तक उचित बाजार मूल्य (एफएमवी, स्टांप ड्यूटी मूल्य से अधिक नहीं) या भूमि या भवन की वास्तविक लागत होगी।

सरकार ने मंगलवार को आम बजट में अचल संपत्तियों पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (एलटीसीजी) कर को 20 प्रतिशत से घटाकर 12.5 प्रतिशत करने के साथ ही अप्रैल, 2001 के बाद खरीदी गई संपत्तियों के मुद्रास्फीति समायोजन (इंडेक्सेशन) से जुड़े लाभ को हटाने का प्रस्ताव रखा। वर्ष 2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों के मामले में, उचित बाजार मूल्यांकन (स्टांप ड्यूटी मूल्य से अधिक नहीं) को मुद्रास्फीति समायोजन मूल्य निर्धारित करने के लिए आधार बनाया जा सकता है। मुद्रास्फीति समायोजन के बाद मूल्य को एलटीसीजी की गणना के लिए बिक्री मूल्य से घटा दिया जाएगा और फिर 20 प्रतिशत कर लगाया जाएगा।

आयकर विभाग ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि वर्ष 2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों के लिए एक अप्रैल 2001 तक अधिग्रहण की लागत के बारे में मुद्दा उठाया गया है। विभाग ने कहा है कि एक अप्रैल 2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों (भूमि या भवन या दोनों) के लिए एक अप्रैल 2001 के मूल्य के हिसाब से खरीद लागत, या एक अप्रैल 2001 को ऐसी परिसंपत्ति का उचित बाजार मूल्य (जहां भी उपलब्ध हो, स्टांप शुल्क मूल्य से अधिक नहीं) उस परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत होगी। विभाग ने बृहस्पतिवार रात को जारी सूचना में कहा, करदाता दोनों में से एक विकल्प चुन सकते हैं। आयकर विभाग ने एक उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश है कि 2001 से पहले खरीदी गई संपत्तियों के मामले में पूंजीगत लाभ कर की गणना किस तरह की जाएगी। उसने एक संपत्ति का उदाहरण दिया, जिसकी 1990 में अधिग्रहण की लागत पांच लाख रुपए थी और एक अप्रैल 2001 को इसका स्टांप शुल्क मूल्य 10 लाख रुपए और एफएमवी 12 लाख रुपए था। यदि इसे 23 जुलाई 2024 को या उसके बाद एक करोड़ रुपए में बेचा जाता है, तो एक अप्रैल 2001 तक अधिग्रहण की लागत 10 लाख रुपए (स्टाम्प ड्यूटी या एफएमवी में से जो भी कम हो) होगी। वित्त वर्ष 2024-25 में इस अधिग्रहण की मुद्रास्फीति समायोजन लागत 36.3 लाख रुपए (10 लाख रुपए गुणा 363।100) है। 363 वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लागत मुद्रास्फीति सूचकांक है। इस सूचकांक को आयकर विभाग अधिसूचित करता है। इस मामले में एलटीसीजी 63.7 लाख रुपए (एक करोड़ रुपए में से 36.3 लाख रुपए घटाकर) बैठता है। इस तरह 20 प्रतिशत की दर पर, ऐसी संपत्तियों के लिए एलटीसीजी कर 12.74 लाख रुपए बनेगा। वहीं नई व्यवस्था में एलटीसीजी 90 लाख रुपए (एक करोड़ में से लागत 10 लाख रुपए घटाने) आंका जाएगा और इस पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर 12.5 प्रतिशत हिसाब से 11.25 लाख करोड़ रुपए बैठेगा।

भारत ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण संगठन एडीपीसी की अध्यक्षता संभाली

नई दिल्ली। भारत ने वर्ष 2024-25 के लिए स्वायत्त अंतरराष्ट्रीय संगठन एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर (एडीपीसी) की अध्यक्षता संभाल ली है। यह संगठन एशिया और प्रशांत क्षेत्र में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्रियान्वयन और जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहयोग के लिए है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के सदस्य और विभागाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने थाइलैंड के बैंकॉक में बृहस्पतिवार को वर्ष 2024-25 के लिए चीन से एडीपीसी की अध्यक्षता संभाली ।बयान के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) के क्षेत्र में भारत वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभा रहा है। भारत ने इस दिशा में कई वैश्विक पहल की हैं, जिनमें आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) की स्थापना जैसी पहल प्रमुख हैं। बयान के मुताबिक, भारत और आठ पड़ोसी देश बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपीन, श्रीलंका और थाईलैंड, एडीपीसी के संस्थापक सदस्य हैं।

राजस्थान : सलूंबर में शिक्षक की तलवार से वार कर हत्या, आरोपी की तलाश जारी

जयपुर। राजस्थान के सलूंबर जिले में बृहस्पतिवार रात 40 साल के एक शिक्षक की तलवार से वार कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने बचाव करने आए शिक्षक के पिता को भी तलवार से घायल कर दिया। पुलिस के अनुसार सलूंबर के अदवास गांव की मेघवाल बस्ती में सिगरेट खरीदने के बहाने दुकान पर आए आरोपी फतेह सिंह ने दुकान के पास खड़े शिक्षक शंकरलाल मेघवाल पर अचानक तलवार से हमला कर दिया। उसने अध्यापक की गर्दन पर वार किया जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक जब शंकरलाल के पिता डाल चंद (60) उसे बचाने आए, तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर घायल कर दिया। उनका अस्पताल में उपचार जारी है। सलूम्बर के पुलिस अधीक्षक अरशद अली ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी मानसिक रूप से परेशान था और उसे संदेह था कि कोविड महामारी के दौरान शिक्षक द्वारा उसे फूल भेंट करने के बाद से उसका व्यवसाय नहीं चल रहा। आरोपी अहमदाबाद में फोटोकॉपी की दुकान चलाता है। उन्होंने बताया कि मृतक शिक्षक के परिजन और स्थानीय ग्रामीणों द्वारा मुआवजे की मांग के चलते शव का पोस्टमार्टम अभी तक हुआ है। उन्होंने बताया कि मामले में चार पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए लोगों में आरोपी को तलवार देने वाले भी शामिल हैं। शिक्षक की पत्नी ललिता ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, मेरे पति की गर्दन पर वार करके हत्या कर दी गई। जब तक मैं पहुंची, तब तक वे जमीन पर पड़े थे। मेरे ससुर पर भी हमला किया गया। अब मैं क्या करूं? शंकरलाल के छोटे भाई प्रकाश ने कहा, मेरे पिता दुकान पर थे। तभी एक व्यक्ति सिगरेट खरीदने के बहाने आया। सिगरेट जलाने के तुरंत बाद उसने मेरे भाई पर पीछे से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उसने बीच बचाव करने आए मेरे पिता पर भी हमला किया। उनका हाथ कट गया और शरीर पर कई चोटें आईं। पुलिस ने बताया कि आरोपी रात में गांव के पास के जंगल में फरार हो गया। पुलिस टीम ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक एक पुलिस दल को आरोपी की तलाश के लिए अहमदाबाद भेजा गया है। इस बीच, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया और राज्य सरकार से इस पर जवाब देने की मांग की।

राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़ राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त

जयपुर (भाषा)। राजस्थान में विधानसभा की पांच सीटों पर उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य मदन राठौड़ को नया प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है। वे इस पद पर सांसद सीपी जोशी की जगह लेंगे। इसके साथ ही पार्टी ने अरुण सिंह की जगह सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल को प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। दो दिन पहले सांसद सीपी जोशी ने पार्टी आलाकमान से मुलाकात कर प्रदेशाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की पेशकश की थी। प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त होने के बाद राठौड़ ने एक्स पर लिखा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सब मिलकर भाजपा राजस्थान को नई बुलंदियों पर ले जाएंगे और डबल इंजन की सरकार में विकास की नई गाथा लिखेंगे। उन्होंने लिखा कि भाजपा राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष की नई जिम्मेदारी मिलने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी जी से शिष्टाचार मुलाकात की। राठौड़ पांच महीने पहले राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। अब पार्टी ने ओबीसी के अपने वोट बैंक को और मजबूत करने के लिए उन्हें प्रदेश भाजपा की नई जिम्मेदारी सौंपी है। मदन राठौड़ पाली की सुमेरपुर विधानसभा सीट से दो बार विधायक रह चुके हैं। वह 2013 से 2018 तक सरकार के उप मुख्य सचेतक भी रहे हैं। उनके पास लंबा संगठनात्मक अनुभव है। उन्होंने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भी टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। कुछ महीने बाद ही उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया। अब प्रदेश भाजपा की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मदन राठौड़ को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को भाजपा राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा, नि:संदेह, आपके ऊर्जावान नेतृत्व व कुशल मार्गदर्शन में भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ प्रदेश में सफलता के नवीन मानक स्थापित करेगी।

भाजपा ने राधामोहन दास अग्रवाल को राजस्थान, हरीश द्विवेदी को असम का प्रभारी बनाया

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य और राष्ट्रीय महासचिव राधामोहन दास अग्रवाल को राजस्थान के लिए पार्टी का प्रभारी नियुक्त किया। पूर्व लोकसभा सदस्य हरीश द्विवेदी को असम के लिए पार्टी का प्रभारी बनाया गया। पार्टी ने एक बयान में कहा कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा ने राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन और पूर्व सांसद राजदीप रॉय को क्रमश: तमिलनाडु और त्रिपुरा का प्रभारी नियुक्त किया है। मेनन को फिर से यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष विजया रहाटकर राजस्थान में और सुधाकर रेड्डी तमिलनाडु में संगठनात्मक मामलों के सह-प्रभारी होंगे। इसके साथ ही पार्टी ने बिहार और राजस्थान में भी नए अध्यक्षों की नियुक्ति की है। बिहार सरकार में मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल को उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की जगह नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

भाजपा को महाराष्ट्र विधानसभा की सभी 288 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए : नारायण राणे

मुंबई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी को इस साल के अंत में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में सभी 288 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। भाजपा राज्य में महायुति सरकार का हिस्सा है। गठबंधन में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) शामिल है।राणे ने एक सवाल के जवाब में कहा, मुझे लगता है कि भाजपा को (विधानसभा की) सभी 288 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री राणे ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी बृहस्पतिवार को राज्य में चुनाव की तैयारियों पर भाजपा नेताओं के साथ बैठक की थी। शिवसेना सांसद और पार्टी प्रवक्ता नरेश म्हास्के ने राणे की टिप्पणी पर तुरंत प्रतिक्रिया दी।

हरिद्वार में कांवड़ मार्ग पर मस्जिद, मजारों के आगे लगाए गए पर्दे हटाने का कार्य शुरू

हरिद्वार (भाषा)। कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली मस्जिदों और मजारों को पर्दों से ढके जाने से शुरू हुए विवाद के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन ने कुछ घंटों के बाद ही उन्हें उतारना शुरू कर दिया। हालांकि, यात्रा मार्ग पर शराब की दुकानों के आगे लगाए गए पर्दों को नहीं हटाया गया है। शराब की दुकानों के बाहर भी इस बार पहली बार पर्दे लगाए गए हैं।

हिंदुओं की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा की इस वर्ष शुरुआत विवादों के साथ हुई जहां उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकारों ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर होटल और ढाबा संचालकों को अपने नाम और पते वाले साइनबोर्ड लगाने का आदेश दिया। इस पर विवाद के बीच मामला उच्चतम न्यायालय पहुंचा जहां इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई। अभी यह विवाद ठंडा भी नहीं पड़ा था कि हरिद्वार जिला प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली मस्जिदों और मजारों को पर्दों से ढक दिया। प्रदेश के पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने इस संबंध में पूछे जाने पर कहा कि कांवड़ यात्रा को व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए मस्जिद और मजारों को ढका गया। उन्होंने कहा, कोई समस्या न हो, इसे देखते हुए ही कुछ बातो पर रोक लगाई जाती है। कांवड़ मार्ग पर किसी प्रकार की उत्तेजना न हो, इसलिए मस्जिद और मजारों को ढका गया है। ज्वालापुर में आर्यनगर के पास इस्लामनगर की मस्जिद और उंचे पुल पर बनी मजार और मस्जिद को पर्दे से ढक दिया गया। लेकिन इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया आने के बाद प्रशासन ने कुछ ही घंटों में उन्हें उतारने का कार्य शुरू कर दिया। प्रशासन के निर्देश पर मस्जिदों और मजारों के आगे लगे पर्दे हटाने पंहुचे कांवड़ मेले के एसपीओ (पुलिस की सहायता के लिए तैनात स्वयंसेवक) दानिश अली ने बताया कि पुलिस चौकी से उन्हें पर्दे हटाने का आदेश मिला है और इसलिए वह उन्हें हटाने आए हैं। इससे पहले, कांवड़ यात्रा के दौरान मस्जिदों और मजारों को कभी नहीं ढका नहीं जाता था। ज्वालापुर स्थित मजार के प्रबंधक शकील अहमद ने कहा कि इस संबंध में उनसे कोई बात नहीं की गई।

पश्चिम बंगाल : भाजपा विधायक ने नया केंद्र शासित प्रदेश गठित करने की मांग की

कोलकाता। पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे की मांग से सहमति जताते हुए भाजपा के एक विधायक ने शुक्रवार को दावा किया कि उन्होंने पहले भी यह मुद्दा उठाया था। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के विधायक गौरी शंकर घोष ने विधानसभा परिसर में संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने दो अगस्त 2022 को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को पत्र भेजकर नया केंद्र शासित प्रदेश गठित करने की मांग की थी। घोष ने कहा, मैंने केंद्र को मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों के माध्यम से अवैध रूप से देश में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी लोगों के बारे में सूचित किया था, जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। घोष ने उम्मीद जताई कि लोकसभा में भाजपा के एक सांसद द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने के बाद गृह मंत्रालय अब इस मामले को गंभीरता से लेगा। उन्होंने कहा, अब मेरी पार्टी के एक सांसद ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया है। मुझे उम्मीद है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय अब इस पर गंभीरता से विचार करेगा। वहीं, तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने भाजपा पर चुनावी असफलताओं के बाद लोगों को धार्मिक आधार पर बांटने और पश्चिम बंगाल के विभाजन के प्रयास करने का आरोप लगाया। दुबे ने बृहस्पतिवार को मांग की कि झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जाए, ताकि क्षेत्र में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ से उत्पन्न चुनौती से निपटा जा सके।

कर्नाटक सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ करने का फैसला किया

बेंगलुरु। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ करने का फैसला किया। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने कहा, हमने रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ करने का निर्णय लिया है...यह वहां के लोगों की मांग पर किया गया है। राजस्व विभाग इस प्रक्रिया को शुरू करेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए पाटिल ने कहा, केवल जिले का नाम बदलेगा, शेष सभी नाम (तालुकाओं के) वही रहेंगे। उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से कहा, सिर्फ जिले का नाम बदलेगा, बाकी सब वही रहेगा। राजधानी बेंगलुरु से लगभग 50 किलोमीटर दूर स्थित रामनगर कस्बा बेंगलुरु साउथ जिले का मुख्यालय बना रहेगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, रामनगर के लोग ब्रांड बेंगलुरु के अंतर्गत आना चाहते हैं। जिले के लोगों और कुछ प्रमुख हस्तियों की राय है कि वे ब्रांड बेंगलुरु चाहते हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या यह निर्णय चुनाव को ध्यान में रखकर लिया गया है, पाटिल ने कहा, यह चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं लिया गया, यह वहां के लोगों और जनप्रतिनिधियों की मांग पर आधारित है। रामनगर उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार का गृह जिला है। वह जिले के कनकपुरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने पिछले साल अक्टूबर में पहली बार यह प्रस्ताव रखा था।अगस्त 2007 में जब रामनगर जिला बनाया गया था तब केंद्रीय मंत्री और जनता दल-सेक्युलर (जद-एस) के नेता एच डी कुमारस्वामी जद-एस-भाजपा गठबंधन के मुख्यमंत्री थे।प्रस्ताव पर कटाक्ष करते हुए कुमारस्वामी ने हाल ही में कहा था कि यदि वह दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं तो इस योजना के लागू होने पर वह इसे पलट देंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने आरोप लगाया था कि इस प्रस्ताव के पीछे का उद्देश्य वहां रियल एस्टेट के अवसरों का दोहन करने का है।रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ करने का प्रस्ताव हाल में तब जोर पकड़ गया जब उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और इस मुद्दे को उठाने के लिए एक ज्ञापन सौंपा।

भाजपा के साथ गठबंधन फेविकोल से चिपका हुआ है

नई दिल्ली (भाषा)। जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने केंद्रीय बजट को विपक्ष द्वारा सरकार बचाओ बजट बताए जाने पर शुक्रवार को पलटवार किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ उनकी पार्टी का चुनाव-पूर्व गठबंधन है जो फेविकोल से चिपका हुआ है। उन्होंने लोकसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस बजट के माध्यम से ऐसी गुगली फेंकी है कि कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष क्लीन बोल्ड हो गया है। उन्होंने कहा, यह आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में मोदी जी के संकल्प को दर्शाने वाला बजट है। सिंह ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि सदन में बजट पर नहीं, बल्कि नरेन्द्र मोदी जी की आलोचना पर भाषण चल रहा है। उनका कहना था, पूरे विपक्ष की शैली यह दर्शाती है कि इन लोगों को मोदी जी का चेहरा पसंद नहीं है और वो प्रधानमंत्री से नफरत करते हैं। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, देश की जनता ने उनके चेहरे को पसंद किया है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री के मुताबिक, प्रधानमंत्री मोदी की यह उपलब्धि है कि 60 साल बाद किसी को तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला है।उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, हमारा यह एक परामर्श है कि आप लोग (विपक्ष) सच्चाई को स्वीकार कर लीजिए। ललन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, हम इनके साथ थे, ए गठबंधन के अंदर लॉबी चलाते हैं। इस कारण हम लोगों ने इन्हें प्रणाम किया और इधर (भाजपा के साथ) चले आए। उन्होंने कांग्रेस पर लोकसभा में उसकी 99 सीट को लेकर कटाक्ष किया और सांप-सीढ़ी के खेल का जिक्र करते हुए कहा कि इस खेल में 99 पर पहुंचते ही सांप काट लेता है और फिर सीधे शून्य पर पहुंच जाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने बजट को सरकार बचाओ बजट करार दिए जाने को लेकर विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा, चाहे हमारे साथ हो या तेलुगु देसम पार्टी के साथ हो, यह चुनाव-पूर्व गठबंधन है। हमारा यह गठबंधन फेविकोल से चिपका हुआ है। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी के सदन में दिए गए भाषण और सरकार की आलोचना को लेकर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, वो उन्हें नहीं दिखाई देता। केंद्रीय मंत्री का कहना था, यह देश का बजट है और प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश का विकास करना चाहते हैं इसलिए विपक्षी सदस्य केवल एक-एक राज्य की बात नहीं करें बल्कि पूरे देश की बात करें।

जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री व अन्य समकक्षों से भेंट की

भाषा। वियनतियाने (लाओस)

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को रूस के अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव और ब्रुनेई, न्यूजीलैंड और लाओस के अन्य नेताओं से मुलाकात की और शिक्षा तथा कृषि प्रौद्योगिकी समेत द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। जयशंकर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) की बैठकों में शामिल होने के लिए लाओस पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की राजधानी में हैं। उन्होंने बैठक के दौरान रूस के विदेश मंत्री लावरोव से मुलाकात की।

रूसी विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने आसियान कार्यक्रम के इतर मुलाकात की। जयशंकर ने ब्रुनेई और न्यूजीलैंड के अपने समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें कीं और शिक्षा तथा कृषि प्रौद्योगिकी सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की।

उन्होंने न्यूजीलैंड के अपने समकक्ष और देश के उप प्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स के साथ द्विपक्षीय बैठक की। जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स से मिलकर मुझे हमेशा खुशी होती है। शिक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, प्रशांत द्वीप समूह और क्रिकेट पर चर्चा हुई।

जयशंकर ने ब्रुनेई के अपने समकक्ष दातो हाजी एरीवान के साथ भी बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों के 40 वर्ष पूरे होने के मौके पर लोगो जारी किया। जयशंकर ने कहा, मुझे विश्वास है कि हमारे मधुर एवं मैत्रीपूर्ण संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। उन्होंने लाओस के गृह मंत्री विलायवो एनजी बौड्डखम, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री मलाइथोंग कोमासिथ, विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष सन्या प्रसुथ और विशेष दूत अलौंकियो किट्टीखौन से भी मुलाकात की।

जयशंकर ने कहा, हमारी मेजबानी के लिए राजदूत प्रशांत अग्रवाल को धन्यवाद। जयशंकर आसियान-भारत, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईएएस) और आसियान क्षेत्रीय मंच (एआरएफ) के प्रारूप में आसियान ढांचे के तहत विदेश मंत्रियों की बैठकों में शामिल होने के लिए लाओस की राजधानी में हैं, ताकि इस समूह के साथ भारत के संबंधों को और गहरा किया जा सके। उनकी यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक दशक पूरा हो रहा है।

डोभाल ने आतंकवाद समेत अन्य मुद्दों से निपटने के लिए बिम्सटेक सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया

नेपीता। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शुक्रवार को बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) देशों से आतंकवाद, मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी तथा संगठित अपराध से निपटने में मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डोभाल ने म्यांमा की राजधानी में बिम्सटेक देशों के सुरक्षा प्रमुखों की चौथी वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया। म्यांमा स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, एनएसए ने बिम्सटेक बैठक में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया। उन्होंने आतंकवाद , मादक पदार्थों की तस्करी और हथियारों की तस्करी तथा संगठित अपराध से निपटने में सहयोग मजबूत करने, बिम्सटेक कनेक्टिविटी, दूसरे बंदरगाह सम्मेलन के आयोजन और हिमालई नदी प्रणालियों की जल सुरक्षा पर बात की।

यह बैठक सदस्य देशों के समक्ष आने वाली सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए महत्वपूर्ण पहलों की रणनीति बनाने और समन्वय स्थापित करने के लिए आयोजित की गई है। इससे पहले डोभाल ने बृहस्पतिवार को म्यांमा के अपने समकक्ष एडमिरल मोए आंग से मुलाकात की। इसके अलावा वह अन्य बिम्सटेक सुरक्षा प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री सीनियर जनरल मिन आंग ह्लाइंग से भी मिले।

डोभाल बृहस्पतिवार को हनोई से यहां पहुंचे थे। हनोई में उन्होंने वियतनाम की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव गुएन फू ट्रोंग के राजकीय सम्मान के साथ हुए अंतिम संस्कार में भी हिस्सा लिया था। गुएन फू ट्रोंग का 19 जुलाई को निधन हो गया था। बिम्सटेक एक क्षेत्रीय संगठन है, जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों को आर्थिक विकास, व्यापार और परिवहन, ऊर्जा और आतंकवाद-निरोध जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए जोड़ता है। उद्देश्य सदस्य देशों- बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमा, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के बीच संबंधों को मजबूत करना और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।

डोभाल ने एडमिरल मोए आंग को वहां की हिंसा और अस्थिरता के कारण म्यांमा की भारत के साथ लगती सीमा पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर नई दिल्ली की चिंता से अवगत कराया। सेना द्वारा एक फरवरी 2021 को तख्तापलट कर सत्ता पर कब्जा किए जाने के बाद से म्यांमा में लोकतंत्र की बहाली की मांग को लेकर व्यापक स्तर पर हिंसक विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं। म्यांमा के कई हिस्सों में सेना और प्रतिरोधी बलों के बीच भीषण युद्ध जारी है। प्रतिरोधी बलों ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। म्यांमा उग्रवाद प्रभावित नगालैंड और मणिपुर सहित भारत के कुछ पूर्वोत्तर राज्यों के साथ 1,640 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है।

इमरान खान की पीटीआई पार्टी ने की देशव्यापी आंदोलन की घोषणा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जेल में बंद अपने सभी नेताओं की रिहाई के लिए देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। प्रशासन ने इस घोषणा के बाद पीटीआई समर्थकों के साथ संभावित टकराव से निपटने को लेकर तैयारी की है। दक्षिणपंथी जमात-ए-इस्लामी ने भी बिजली और अन्य वस्तुओं की ऊंची कीमतों के खिलाफ इस्लामाबाद में प्रदर्शन की घोषणा की है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक इमरान खान (71) और अन्य नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की रिहाई के लिए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। खान को पिछले साल पांच अगस्त को पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग द्वारा दायर तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। तब से वह विभिन्न मामलों में जेल में बंद हैं। क्रिकेट से राजनीति में आए खान को जमानत मिल गई है या फिर उनकी दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें रिहा नहीं किया गया।

वह राजधानी में नेशनल प्रेस क्लब के सामने प्रदर्शन करेगी, जबकि जमात-ए-इस्लामी ने संसद भवन के सामने स्थित प्रसिद्ध एफ-चौक पर धरना देने की योजना बनाई है। इस बीच, इस्लामाबाद में पुलिस ने धारा 144 लागू करते हुए संघीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन सहित सभी प्रकार की सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही रेड जोन को सील करते हुए प्रवेश निषिद्ध कर दिया है। इस जोन में प्रमुख सरकारी कार्यालय और दूतावास हैं। पुलिस ने फैजाबाद इंटरचेंज पर इस्लामाबाद राजमार्ग को भी आंशिक रूप से बंद कर दिया है, यह रावलपिंडी से इस्लामाबाद के मुख्य प्रवेश बिंदु पर स्थित है। इसके अलावा पंजाब गृह मंत्रालय ने सभी विरोध प्रदर्शनों और सभाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रांत में धारा 144 लागू कर दी। पीटीआई ने दावा किया है कि देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों से पहले उसके पार्टी नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। उसने कहा कि पंजाब पुलिस ने रावलपिंडी में पीटीआई नेता राजा बशारत के घर पर छापा मारा। उसने कहा कि कानूनविद जावेद इकबाल समेत दर्जनों लोगों को रहीम यार खान शहर में गिरफ्तार किया गयाहै। पुलिस ने लाहौर में पीटीआई नेता मेहर नईमुल्ला के कैंप कार्यालय पर छापा मारा और उनके पांच मित्रों को गिरफ्तार किया।

नेतन्याहू संबंधों में आई दरार को पाटने के लिए ट्रंप से मुलाकात करेंगे

वाशिंगटन। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू संबंधों में आई दरार को पाटने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से शुक्रवार को मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की ओर से इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की प्रमुख इच्छाओं को पूरा करने में अपने पूर्ववर्तियों से कहीं अधिक कदम उठाए थे। जब 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में नेतन्याहू ने चुनाव में जीत दर्ज करने वाले डेमोक्रेट जो. बाइडन को बधाई दी तो ट्रंप और नेतन्याहू के संबंधों में दरार आ गई थी। शुक्रवार को, दोनों नेता लगभग चार साल में पहली बार आमने-सामने की मुलाकात करेंगे और इस संभावना पर विमर्श करेंगे कि क्या रिश्ते को सुधारा जा सकता है। दोनों की अपने मतभेदों को दूर करने में रूचि है।

ट्रंप 2017 से 2021 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। वह इस साल नवंबर में होने वाले चुनाव में एक बार फिर रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात को लेकर कई तरह की अटकलें हैं। ट्रंप ने 2021 की शुरुआत में नेतन्याहू से नाता तोड़ लिया था। ऐसा तब हुआ जब इजराइली प्रधानमंत्री ट्रंप के झूठे दावे की अनदेखी करते हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए बाइडन को बधाई देने वाले पहले विश्व नेताओं में से एक बन गए। उस समय एक इज़राइली अखबार को दिए साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा था, नेतन्याहू चुप रह सकते थे। उन्होंने एक भयानक गलती की। नेतन्याहू के साथ अपने अलगाव के बाद ट्रंप ने सार्वजनिक बयानों में खुद को राष्ट्रपति के रूप में इज़राइल के लिए कड़ी मेहनत करने वाले के रूप में चित्रित किया और नेतन्याहू पर वफादारी न निभाने का आरोप लगाया। ट्रंप ने अन्य मुद्दों पर भी नेतन्याहू की आलोचना की है। ऐसे ही एक उदाहरण में उन्होंने कहा कि सात अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमलों से निपटने के लिए नेतन्याहू की तैयारी नहीं थी।

नेतन्याहू ने बुधवार को अमेरिकी संसद में अपने भाषण में बाइडन की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर विरोध के बावजूद गाजा में इजराइल की कार्वाई के लिए सैन्य और राजनयिक समर्थन जारी रखा है। उन्होंने ट्रंप की भी काफी प्रशंसा की और उनके द्वारा किए गए क्षेत्रीय समझौतों को ऐतिहासिक बताया। ट्रंप को इजराइल के लिए किए गए सभी कार्यों के लिए धन्यवाद दिया।

ब्रिटेन ने नेतन्याहू के खिलाफ आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट अनुरोध को चुनौती देने की योजना छोड़ी

लंदन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टॉर्मर के कार्यालय ने शुक्रवार को कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के लिए अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत (आईसीसी) के अनुरोध में ब्रिटेन हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस निर्णय से स्टॉर्मर की सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की योजना में अंतर आ गया है। सुनक ने वारंट को चुनौती देने की योजना बनाई थी। आईसीसी ने सरकार को चुनौती दायर करने के लिए शुक्रवार तक की समय सीमा तय की थी।

ओलंपिक से चंद घंटे पहले फ्रांस में रेलवे लाइन नेटवर्क पर हमला

पीटीआई। पेरिस

ओलंपिक खेलों के भव्य उद्घाटन समारोह से कुछ घंटे पहले फ्रांस के हाई-स्पीड रेल नेटवर्क को निशाना बनाकर की गई तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं से देश तथा यूरोप के विभिन्न हिस्सों से राजधानी पेरिस तक संचालित की जाने वाली ट्रेन सेवा शुक्रवार को प्रभावित हुई। अधिकारियों ने इन हमलों को आपराधिक कृत्य करार दिया। फ्रांस के प्रधानमंत्री गेब्रियल अट्टल ने कहा कि ओलंपिक की पूर्व संध्या पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं ने देश के मुख्य हिस्सों में फैले हाई स्पीड रेल नेटवर्क को बुरी तरह प्रभावित किया है और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क को बाधित करना था। उन्होंने कहा कि ओलंपिक के उद्घघाटन समारोह से महज कुछ घंटों पहले पेरिस की ओर जाने वाले उत्तर, पूर्व और पश्चिम के मुख्य मार्गों को चरणबद्ध तरीके से निशाना बनाया गया। अट्टल ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इन घटनाओं के गंभीर परिणाम होंगे क्योंकि हजारों लोग ओलंपिक या छुट्टियों के लिए पेरिस जाने की कोशिश करते समय बीच रास्ते में ही फंस जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक, ओलंपिक खेलों के मद्देनजर पूरी दुनिया की नजरें पेरिस पर थीं, ऐसे में इन हमलों से अकेले शुक्रवार को ढाई लाख यात्रियों के प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि रेल लाइनों पर तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं से ट्रेन परिचालन सप्ताहांत और इससे अधिक समय तक प्रभावित रहने की आशंका है। फ्रांस के परिवहन मंत्री पैट्रिस वर्गीते ने बताया कि जिन जगहों पर आगजनी की घटनाएं हुईं, वहां से लोगों को भागते देखा गया और इन स्थानों पर आग लगाने के लिए इस्तेमाल चीजें भी बरामद की गईं। वर्गीते ने कहा, हर चीज इंगित करती है कि ये आपराधिक घटनाएं हैं। उन्होंने बताया कि इन घटनाओं के कारण पेरिस को फ्रांस के अन्य हिस्सों और पड़ोसी देशों से जोड़ने वाली हाई-स्पीड ट्रेन का परिचालन ठप पड़ गया।

बीएफएम टेलीविजन से बातचीत में उन्होंने कहा कि ओलंपिक उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पेरिस की यात्रा की योजना बना रहे थे। उन्होंने कहा कि इसके अलावा छुट्टियां मनाने निकले कई पर्यटकों की भी पेरिस और अन्य जगहों की यात्रा करने की योजना थी। पेरिस में अधिकारी कड़ी सुरक्षा के बीच सीन नदी और इसके किनारे एक शानदार परेड निकालने की तैयारियों में जुटे थे कि तभी अटलांटिक, नॉर्ड और एस्ट में हाई-स्पीड लाइनों पर पटरियों के पास गोलीबारी की सूचना मिली। गोलीबारी की इन घटनाओं से पेरिस के प्रमुख मॉन्टपर्नासे स्टेशन पर ट्रेन परिचालन खासतौर पर प्रभावित हुआ। सोशल मीडीया पर साझा किए गए वीडियो में मॉन्टपर्नासे स्टेशन का हॉल यात्रियों से खचाखच भरा हुआ देखा जा सकता है। पेरिस के पुलिस के प्रमुख लॉरेंट नुनेज ने फ्रांस इन्फो टेलीविजन को बताया कि टीजीवी हाई-स्पीड नेटवर्क पर ट्रेन परिचालन ठप करने के लिए बड़े पैमाने पर किए गए हमलों के बाद पेरिस पुलिस ने अपने कर्मियों को पेरिस के रेलवे स्टेशनों की ओर भेज दिया। यूरोप के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से एक गारे डु नॉर्ड पर कई यात्री शुक्रवार सुबह से ही डिस्प्ले बोर्ड पर नजर टिकाए हुए थे, क्योंकि उत्तरी फ्रांस, बेल्जियम और ब्रिटेन को जाने वाली अधिकतर ट्रेन देरी से चल रही थीं। लंदन की ट्रेन का इंतजार कर रही सारा मोसले नाम की यात्री ने कहा, यह ओलंपिक की मेजबानी की बहुत घटिया शुरुआत है। कोरी ग्रेंगर नाम के एक यात्री ने कहा, उनके पास यात्रियों के लिए और अधिक जानकारी होनी चाहिए, खासकर तब, जब यह एक दुर्भावनापूर्ण हमला है। फ्रांस की राष्ट्रीय रेल कंपनी एसएनसीएफ ने इन घटनाओं को सुनियोजित हमला करार दिया। इसने कहा कि हमलों के कारण इंग्लिश चैनल के रास्ते लंदन, बेल्जियम और पश्चिमी, उत्तरी व पूर्वी फ्रांस तक संचालित की जाने वाली कई ट्रेन का परिचालन ठप पड़ गया। सरकारी अधिकारियों ने पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह से कुछ घंटे पहले हुई इन घटनाओं की निंदा की। हालांकि, इनका ओलंपिक खेलों से संबंध होने के तत्काल कोई संकेत नहीं मिले हैं। राष्ट्रीय पुलिस ने कहा कि अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं कि रेल लाइनों पर परिचालन क्यों प्रभावित हुआ। इस बीच, फ्रांसीसी मीडिया ने व्यस्त पश्चिमी मार्ग के एक स्टेशन पर भीषण आगजनी की खबर दी है।

नेपाल विमान दुर्घटना में जीवित बचे कैप्टन शाक्य को सामान्य वार्ड में स्थानांतरित किया

भाषा। काठमांडू

नेपाल में एक घातक विमान हादसे में जीवित बचे एकमात्र व्यक्ति कैप्टन मनीष राज शाक्य को स्वास्थ्य में सुधार के बाद गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) से सामान्य वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया। शुक्रवार को एक खबर में यह जानकारी सामने आई। इस विमान हादसे में 18 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। सौर्य एयरलाइंस के बॉम्बार्डियर सीआरजे-200 विमान में बुधवार को त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (टीआईए) से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद आग लग गई। इसमें चालक दल के दो सदस्य, एयरलाइन के तकनीकी कर्मचारी और एक बच्चा और उसकी मां सहित 19 लोग सवार थे। अधिकारियों ने बताया कि 15 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन ने उपचार के दौरान दम तोड़ा।

कैप्टन शाक्य (37) को दुर्घटनास्थल से बचा लिया गया। विमान के बाकी हिस्से में आग लगने से कुछ सेकंड पहले ही विमान का कॉकपिट एक मालवाहक कंटेनर से टकराकर अलग हो गया था, जिसके बाद उन्हें बचा लिया गया। द काठमांडू पोस्ट समाचार पत्र की खबर के मुताबिक, कैप्टन शाक्य का काठमांडू मेडिकल कॉलेज (केएमसी) अस्पताल के आईसीयू में इलाज किया जा रहा था। अस्पताल ने कहा कि शाक्य की हालत अब स्थिर है और उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है।

केएमसी की निदेशक प्रोफेसर डॉ. मीना थापा के हवाले से खबर में बताया गया कि उनकी (शाक्य) स्वास्थ्य स्थिति में सुधार के बाद उन्हें अब सामान्य वार्ड में स्थानांतरित किया गया है। थापा ने बताया कि न्यूरोलॉजी और ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ शाक्य की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया, उनके (शाक्य के) चेहरे, आंखों, नाक और सिर पर चोटें आईं हैं। इसके अलावा, उनके मेरु दंड (रीढ़ की हड्डी) की एक हड्डी और बाईं ओर की तीन पसलियां टूट गई हैं। खबर में थापा के हवाले से बताया गया, शाक्य की सर्जरी की जाए या नहीं अब तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। केएमसी सूत्रों के अनुसार, आग में नहीं झुलसने के बावजूद कैप्टन शाक्य को कई अंदरूनी चोटें आईं हैं।

चीन में सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की योजना से लोगों में नाराजगी

भाषा। बीजिंग

चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा तेजी से बढ़ती उम्रदराज आबादी से निपटने के लिए कामकाजी आबादी की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की योजना ने जनता में नाराजगी पैदा कर दी है। वर्तमान ढांचे के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में पुरुष कामगारों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है, जबकि महिला कामगारों के लिए यह उनके व्यवसाय के आधार पर 50 या 55 वर्ष है। हाल में संपन्न चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) के तीसरे पूर्ण अधिवेशन में अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाने के लिए व्यापक सुधारों की घोषणा की गई है जो कि गहराते जनसांख्यिकीय संकट, धीमी वृद्धि और बढ़ते स्थानीय सरकारी ऋण से प्रभावित है। अधिवेशन में सेवानिवृत्ति की आयु को स्वैच्छिक और लचीले तरीके से बढ़ाने की योजना पर भी चर्चा की गई।

ग्यारह जुलाई को जारी विश्व जनसंख्या संभावना 2024 रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की जनसंख्या, जो वर्तमान में 2024 में 1.41 अरब है, 2054 में घटकर 1.21 अरब हो जाएगी और 2100 तक और घटकर 63.3 करोड़ हो जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया, यह अनुमान लगाया गया है कि चीन, जो वर्तमान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, 2024 और 2054 के बीच जनसंख्या में सबसे बड़ी कमी (20.4 करोड़) का सामना करेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि चीन के लिए लंबी अवधि के जनसंख्या अनुमान अधिक अनिश्चित हैं।

चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2023 के अंत तक जनसंख्या और उसकी संरचना के अनुसार, 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 21.1 प्रतिशत (29.69 करोड़) थी, जिसमें से 65 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या 15.4 प्रतिशत (21.67 करोड़) है। कामकाजी आयु वर्ग, यानी 16 से 60 वर्ष तक की आयु की जनसंख्या 61.3 प्रतिशत (86.48 करोड़) है। पिछले सप्ताह आयोजित पूर्ण अधिवेशन द्वारा अनुमोदित आधिकारिक दस्तावेज में 2029 तक पूरे किए जाने वाले व्यापक सुधारों के तहत 300 से अधिक नीतिगत उपायों को सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि, सीपीसी ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की योजना को लागू करने के लिए आधिकारिक तौर पर कोई कार्यक्रम घोषित नहीं किया है। दस्तावेज के अनुसार, सरकार व्यवस्थित और क्रमिक तरीके से सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की दिशा में कदम उठाएगी और उम्रदराज लोगों के लिए विविध नौकरियों का सृजन करने को लेकर सिल्वर इकोनॉमी विकसित करने का प्रयास करेगी।

सिल्वर इकोनॉमी का आशय वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत की ऐसी प्रणाली से है जिसका उद्देश्य उम्रदराज लोगों की क्रय क्षमता का उपयोग करना और उनके उपभोग, जीवन और स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करना है। इस योजना को लेकर चीनी सोशल मीडिया में तीखी प्रतिक्रिया हुई है, जहां लोगों ने उनकी पेंशन मिलने में देरी की आशंका के चलते असंतोष व्यक्त किया है, युवा कर्मचारियों का कहना है कि यदि उम्रदराज कर्मचारी बने रहेंगे तो सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ने से उनके पास कम नौकरियां बचेंगी। लोगों ने सरकार संचालित चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज द्वारा 2019 में जताए गए एक पूर्वानुमान को भी साझा किया, जिसमें कहा गया था कि बढ़ती चिंताओं के बीच घटते श्रमबल के कारण चीन का सरकारी पेंशन कोष 2035 तक समाप्त हो जाएगा।

कमला ने नेतन्याहू से गाजा में युद्ध समाप्त करने का आग्रह किया

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हमास के साथ जल्द युद्धविराम समझौता करने और गाजा में विनाशकारी युद्ध स्थाई रूप से समाप्त करने का आग्रह किया है। फलस्तीनी क्षेत्र में हताहतों की संख्या बढ़ने और मानवीय संकट गहराने के बीच हैरिस ने इजराइल के प्रधानमंत्री से यह आग्रह किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस परिसर में हैरिस और नेतन्याहू की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उपराष्ट्रपति ने संवाददाताओं से कहा, इजराइल को अपना बचाव करने का अधिकार है और वह ऐसा किस तरीके से करता है, यह मायने रखता है। पिछले नौ महीनों में गाजा में जो कुछ हुआ है वह विनाशकारी है।

अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर देखी जा रहीं हैरिस ने कहा, कई मामलों में दूसरी, तीसरी या चौथी बार विस्थापित होने के बाद सुरक्षा के लिए भाग रहे हताश, भूखे लोगों और मृत बच्चों की तस्वीरें हैं। हम इन त्रासदियों के सामने आंखें नहीं मूंद सकते। मैं चुप नहीं रहूंगी।

हैरिस ने द्वि-राष्ट्र समाधान की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इससे पहले बृहस्पतिवार को नेतन्याहू ने राष्ट्रपति जो. बाइडन से मुलाकात की। व्हाइट हाउस में नेतन्याहू ने मुलाकात से एक दिन पहले कांग्रेस (अमेरिकी संसद) को संबोधित करते हुए हमास के खिलाफ पूर्ण जीत का संकल्प जताया। इस दौरान, हजारों फलस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया। युद्ध के नौवें महीने में पहुंचने के साथ नेतन्याहू पर इजराइल-गाजा युद्ध को समाप्त करने के लिए लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। हैरिस ने कहा, मैंने यह कई बार कहा है, लेकिन इसे दोहराना जरूरी है। इजराइल को अपना बचाव करने का अधिकार है और वह ऐसा किस तरीके से करता है, यह मायने रखता है। हमास एक क्रूर आतंकवादी संगठन है। हमास ने सात अक्टूबर को 44 अमेरिकियों सहित 1,200 निर्दोष लोगों की हत्या कर इस युद्ध की शुरुआत की। उन्होंने कहा, हमास ने यौन हिंसा के भयानक कृत्य किए हैं और 250 लोगों को बंधक बनाया। ऐसे अमेरिकी नागरिक हैं जो गाजा में बंदी बने हुए हैं।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने नेतन्याहू के साथ अपनी बैठक के दौरान गाजा में बड़ी संख्या में निर्दोष आम नागरिकों की मौत होने समेत मानवीय पीड़ा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, मैंने वहां की भयावह मानवीय स्थिति के बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की है। वहां 20 लाख से अधिक लोग खाद्य असुरक्षा और पांच लाख लोग गंभीर स्तर की खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। पिछले नौ महीने में गाजा में जो कुछ हुआ है, वह विनाशकारी है। हैरिस ने कहा कि युद्धविराम और बंधकों की रिहाई के समझौते को लेकर वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि समझौते के पहले चरण में पूर्ण युद्धविराम होगा, जिसके तहत गाजा के आबादी वाले केंद्रों से इजराइली सेना की वापसी होगी और दूसरे चरण में इजराइली सेना गाजा से पूरी तरह से पीछे हट जाएगी तथा इससे शत्रुता का स्थाई अंत होगा।

उन्होंने कहा, इस युद्ध को समाप्त करने का समय आ गया है और यह इस तरह से समाप्त होना चाहिए कि इजराइल सुरक्षित हो, सभी बंधकों को रिहा किया जाए, गाजा में फलस्तीनियों की पीड़ा समाप्त हो और फलस्तीनी स्वतंत्रता, गरिमा एवं आत्मनिर्णय के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। इस समझौते को लेकर वार्ता में आशाजनक प्रगति हुई है। हैरिस ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा कि इस समझौते को करने का समय आ गया है। जो लोग युद्धविराम और शांति चाहते हैं, मैं उन्हें देख रही हूं और सुन रही हूं। आइए, हम यह समझौता करें ताकि हम युद्ध समाप्त कर सकें, बंधकों को घर वापस लाया जा सके और फलस्तीनियों को अत्यावश्यक राहत प्रदान की जा सके।

साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है मालदीव के साथ विशेष संबंध : भारतीय उच्चायोग

माले। मालदीव के साथ भारत के विशेष संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। भारतीय उच्चायोग ने यहां मालदीव के साथ संसदीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में विश्वास जताया। मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर ने बृहस्पतिवार को संसद के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला से शिष्टाचार भेंट की। मालदीव की संसद के अकाउंट से एक्स पर किए गए एक पोस्ट में कहा गया, मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त मुनु महावर ने पीपुल्स मजलिस के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला से शिष्टाचार भेंट की। भारतीय उच्चायोग ने पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कहा, मालदीव के साथ भारत के विशेष संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हैं। हम अपने संसदीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए तत्पर हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से मुलाकात कर दोनों देशों के बीच निरंतर घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए अटूट प्रतिबद्धता दोहराई थी।

श्रीलंका में 21 सितंबर को होगा राष्ट्रपति पद का चुनाव

कोलंबो। श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव आगामी 21 सितंबर को होंगे। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को यह घोषणा की। इसी के साथ देश में महीनों से जारी इन अटकलों पर विराम लग गया कि निर्वतमान राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे का कार्यकाल बढ़ाने के लिए चुनाव की तारीख आगे खिसका दी जाएगी। सरकारी गजट संख्या 2394/51 शुक्रवार को जारी की गई, जिसमें कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद-31 (3) के तहत मतदान 21 सितंबर को होगा, जबकि 15 अगस्त को नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। चुनाव की घोषणा से पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का शेष कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, जिन्हें आर्थिक संकट से निपटने में नाकाम रहने पर 2022 के मध्य में इस्तीफा देना पड़ा था। नवंबर 2019 में जब पिछला राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, तब राजपक्षे ने लगभग सात लाख मतों से जीत दर्ज की थी।

दरअसल, वर्ष 1948 के बाद से सबसे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में 2022 की शुरुआत में लाखों लोग तत्कालीन राष्ट्रपति राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए थे। राजपक्षे को नौ जुलाई 2022 को देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था, जिसके बाद संसद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे को उनका उत्तराधिकारी चुना था। विक्रमसिंघे ने श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से बेलआउट पैकेज हासिल करने में सफलता पाई। भारत ने भी 2022 की पहली तिमाही में श्रीलंका को चार अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की, जिससे आर्थिक संकट के बीच भोजन और आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए भुगतान किया गया। विक्रमसिंघे सुधारों को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं। उन्होंने श्रीलंका को दिवालियापन से बाहर निकालने का संकल्प लिया है। माना जा रहा है कि वह राष्ट्रपति पद पर बने रहने के लिए चुनाव मैदान में उतरेंगे।

विक्रमसिंघे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे

कोलंबो। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने सितंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरने की शुक्रवार को घोषणा की। इससे पहले दिन में, निर्वाचन आयोग ने देश में राष्ट्रपति चुनाव आगामी 21 सितंबर को होने की घोषणा की। इसी के साथ देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर महीनों से जारी अटकलों पर विराम लग गया। श्रीलंका 2022 से अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। संकट के इस दौर के बाद श्रीलंका में यह पहला चुनाव होगा। डेली न्यूज अखबार की खबर के अनुसार, राष्ट्रपति के वकील रोनाल्ड परेरा ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 75 वर्षीय विक्रमसिंघे की ओर से नकद राशि जमा कराई। इसके बाद परेरा ने संवाददाताओं से कहा कि विक्रमसिंघे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति चुनाव लड़ेंगे।

सूर्यकुमार और गंभीर के नए युग में दबदबा बरकरार रखने के लिए उतरेगी भारतीय टीम

भाषा। पालेकल (श्रीलंका)

भारतः सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, रियान पराग, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, खलील अहमद, मोहम्मद सिराज।
श्रीलंकाः दिनेश चांदीमल, अविष्का फर्नांडो, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पथुम निसांका, कुसल परेरा, चरिथ असलांका (कप्तान), वानिंदु हसरंगा, कामिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, चामिंदु विक्रमसिंघे, बिनुरा फर्नांडो, असिथा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका, मथीशा पथिराना, महेश थीक्षाना, डुनिथ वेलालगे।

गौतम गंभीर और सूर्यकुमार यादव की नवनियुक्त कोच और कप्तान की जोड़ी के साथ भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ शनिवार से यहां शुरू होने वाली तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला में अपनी विशेष छाप छोड़ने की कोशिश करेगी। दो बार के विश्व कप विजेता गंभीर मुख्य कोच के रूप में जबकि टी20 के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक सूर्यकुमार खेल के इस छोटे प्रारूप में कप्तान के रूप में अपनी नई पारी शुरू करेंगे। गंभीर आईपीएल में कप्तान और मेंटर (मार्गदर्शक) के रूप में काफी सफल रहे हैं। वह राहुल द्रविड़ की जगह लेंगे जिनके कोच रहते हुए भारत ने अच्छी सफलताएं हासिल की थी। द्रविड़ के मुख्य कोच रहते हुए भारत ने आईसीसी प्रतियोगिताओं में तीनों प्रारूप के फाइनल में जगह बनाई तथा गंभीर को अब इन सफलताओं को नए मुकाम पर पहुंचाना होगा।

सूर्यकुमार को कप्तान बनाना थोड़ा हैरानी भरा फैसला रहा क्योंकि रोहित शर्मा के टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद हार्दिक पंड्या को इस पद का प्रमुख दावेदार माना जा रहा था। चयन समिति ने सूर्यकुमार के कप्तान के रूप में कम अनुभव को नजरअंदाज करके उन्हें टीम की कमान सौंपी है।

अगला टी20 विश्व कप 2026 में भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में खेला जाएगा तथा चयनकर्ताओं के पास उसके लिए टीम तैयार करने के लिए अभी काफी समय है। भारतीय टीम में यह बदलाव पिछले महीने विश्व कप जीतने तथा रोहित, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद आया है। भारतीय टीम जब परिवर्तन के दौर से गुजर रही है तब सीमित ओवरों की टीम के उप कप्तान शुभमन गिल इसे अपनी जगह पक्की करने के अवसर के रूप में देख रहे होंगे। केवल वही नहीं यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह और यहां तक कि रियान पराग जैसे अन्य खिलाड़ी भी ऐसा करना चाहेंगे

अक्षर पटेल टीम में जडेजा की जगह लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनके अलावा भारत के पास हार्दिक, शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर के रूप में अच्छे ऑलराउंडर भी मौजूद हैं। जसप्रीत बुमराह को इस दौरे से विश्राम दिया गया है तथा उनकी अनुपस्थिति में अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज यहां की तेज गेंदबाजों के अनुकूल परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाकर टीम में अपनी जगह मजबूत करना चाहेंगे। जहां तक श्रीलंका की बात है तो वह तेज गेंदबाजी विभाग में कमजोर नजर आता है क्योंकि उसके दो अनुभवी गेंदबाज दुष्मंथा चमीरा (ब्रोंकाइटिस और श्वसन संक्रमण) और नुवान तुषारा (उंगली में फ्रैक्चर) श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह असिथा फर्नांडो और दिलशान मदुशंका को टीम में लिया गया है।

श्रीलंका के टी20 विश्व कप में जल्दी बाहर होने के बाद कप्तान वानिंदु हसरंगा, कोच क्रिस सिल्वरवुड और सलाहकार कोच महेला जयवर्धने ने अपना पद छोड़ दिया था। श्रीलंका ने सनथ जयसूर्या को अंतरिम कोच नियुक्त किया है जिन्होंने अपनी टीम को भारत के स्टार खिलाड़ियों की अनुपस्थिति का पूरा फायदा उठाने के लिए कहा है लेकिन वह अपनी टीम की कमजोरी से भी अच्छी तरह वाकिफ हैं।

भारत की तरह श्रीलंका भी नए दौर की शुरुआत करेगा। उसने कप्तानी की जिम्मेदारी अनुभवी बल्लेबाज चरिथ असलांका को सौंपी है। श्रीलंका घरेलू परिस्थितियों का लाभ उठाकर जीत हासिल करना चाहेगा। उसके पास कई अनुभवी खिलाड़ी है जिनमें पूर्व कप्तान दासुन शनाका, कुसल परेरा, कुसल मेंडिस और दिनेश चांदीमल शामिल हैं।

मुझे नेतृत्व करना अच्छा लगता है, मैंने अलग-अलग कप्तानों से काफी कुछ सीखा है: सूर्यकुमार

पालेकल (श्रीलंका)। भारतीय टी20 टीम के नवनियुक्त कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा कि उन्होंने मैदान पर नेतृत्व करने का पूरा लुत्फ उठाया है तथा पिछले कई वर्षों में अलग-अलग कप्तानों की अगुवाई में खेलते हुए उन्होंने काफी कुछ सीखा है। भारतीय टीम के विश्व चैंपियन बनने के बाद रोहित शर्मा ने सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास ले लिया था। इसके बाद उनकी जगह सूर्यकुमार को कप्तान ने किया गया। उन्हे हार्दिक पंड्या पर प्राथमिकता दी गई जिन्हे पहले टी20 टीम की कप्तानी का दावेदार माना जा रहा था।सूर्यकुमार कप्तान के रूप में अपनी शुरुआत श्रीलंका के खिलाफ शनिवार से यहां शुरू होने वाली तीन मैच की टी20 श्रृंखला से करेंगे।मध्यक्रम के इस बल्लेबाज ने बीसीसीआई टीवी से कहा, भले ही मै कप्तान नही था लेकिन मैंने हमेशा मैदान पर नेतृत्वकर्ता की भूमिका का लुत्फ उठाया है। मैंने हमेशा अलग-अलग कप्तानो से काफी कुछ सीखा है। यह अच्छा एहसास और बड़ी जिम्मेदारी है। नए कप्तान सूर्यकुमार और नए मुख्य कोच गौतम गंभीर की मौजूदगी मे भारतीय टी20 टीम नए दौर की शुरुआत करेगी। सूर्यकुमार कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) की तरफ से 2014 मे गंभीर की अगुवाई मे इंडियन प्रीमियर लीग मे खेल चुके है और इन दोनो के आपस मे काफी अच्छे संबंध है। सूर्यकुमार ने कहा, यह रिश्ता काफी खास है क्योकि मै 2014 मे केकेआर की तरफ से उनके नेतृत्व मे खेल चुका हू। यह विशेष था क्योकि वही से मुझे मौके मिले थे। हमारा रिश्ता अब भी मजबूत है। उन्होने कहा, वह (गंभीर) जानते है कि मै कैसे काम करता हू और जब मै अभ्यास सत्र मे आता हू तो मेरी मानसिकता क्या होती है। मै यह भी जानता हू कि वह कोच के रूप मे कैसे काम करने की कोशिश करते है। यह सब हमारे बीच के प्यारे रिश्ते से जुड़ा है और मै यह देखने के लिए बेहद उत्साहित हू कि यह कैसे आगे बढ़ता है। सूर्यकुमार ने कहा कि एक कप्तान के रूप मे वह विनम्र बने रहना चाहते है क्योकि वह क्रिकेट को सिर्फ एक खेल के रूप मे देखते है, न कि जीवन के रूप मे।

गंभीर टीम में नए विचार लाएंगे

दुबई। (भाषा) भारत के पूर्व कप्तान रवि शास्त्री ने राष्ट्रीय टीम के नए कोच गौतम गंभीर के सफल होने की उम्मीद जताते हुए कहा कि वह एक समकालीन कोच हैं जिन्होंने अपेक्षाकृत परिपक्व और सुलझी हुई टीम की बागडोर संभाली है। भारत के पूर्व कोच शास्त्री का मानना है कि 42 वर्षीय गंभीर अपनी नई भूमिका में तत्काल प्रभाव डाल सकते हैं क्योंकि वह कई खिलाड़ियों के साथ खेल चुके हैं और उनका मार्गदर्शन कर चुके हैं। वह पहले से ही टीम करीब हैं।वामहस्त सलामी बल्लेबाज रहे गंभीर ने इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ सुपर जायंट्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मेंटोर (मार्गदर्शक) की भूमिका निभाई है। शास्त्री ने आईसीसी रीव्यू के नवीनतम एपिसोड में कहा, वह (गंभीर) समकालीन हैं, आईपीएल में उनका सत्र बहुत अच्छा रहा था। मुझे लगता है कि वह सही उम्र है जहां वह युवा है, वह नए विचारों के साथ आएगा। वह आईपीएल टीमों का हिस्सा रहा है ऐसे में खासकर सफेद गेंद प्रारूप के ज्यादातर खिलाड़ियों को जानता हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वह टीम में नयापन लेकर आएगा। उन्होंने कहा, हम गौतम को जानते है, उसे अनुशासन पसंद है। उसके भी अपने विचार होंगे। उसके लिए यह अच्छी बात है कि उसके पास एक परिपक्व टीम है। उनके पास एक सुलझी हुई टीम है। मुझे लगता है कि भले ही आप सोचते हों कि आप परिपक्व हैं, आपको कुछ नए विचारों से फायदा हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि यह दिलचस्प समय होगा। शास्त्री का मानना है कि खिलाड़ियों, खासकर गेंदबाजों का कार्यभार प्रबंधन गंभीर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। उन्होंने कहा, जाहिर तौर पर, एक कोच के रूप में खिलाड़ी प्रबंधन महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि वह कैसे आगे बढ़ता है। मुझे लगता है कि उसके पास इसका तरीका और अनुभव है। भारत के कोच के रूप में गंभीर का पहला कार्यभार श्रीलंका में सफेद गेंद की श्रृंखला है जो शनिवार को पल्लेकेले में तीन मैचों की टी20 श्रृंखला के साथ शुरू होगी। पिछले महीने की टी20 विश्व कप जीत के बाद दिग्गज रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा के सबसे छोटे प्रारूप से संन्यास लेने के कारण गंभीर को इन खिलाड़ियों का विकल्प ढूंढना होगा। शास्त्री ने कहा, वहां बहुत सारे खिलाड़ी हैं और यह सिर्फ यह सही मिश्रण पाने के बारे में है। मुझे लगता है कि इस टी20 विश्व कप को जीतने वाले कई खिलाड़ी लगभग दो साल बाद (2026 टी20 विश्व कप में) भी टीम में होंगे। उन्होंने कहा, आपने उन तीन खिलाड़ियों का उल्लेख किया जो संन्यास ले चुके है लेकिन उन्हें छोड़कर, मुझे लगता है कि अधिकांश खिलाड़ी भारत में दो साल बाद होने वाले टी20 विश्व कप टीम में शामिल होने के लिए फिट होंगे।

मुक्केबाजी में निकहत और लवलीना पर टिकी रहेंगी भारत की निगाहें

पेरिस (भाषा)। विश्व चैंपियनशिप की पदक विजेता निकहत ज़रीन, लवलीना बोरगोहेन और निशांत देव ओलंपिक खेलों में शनिवार से शुरू हो रही मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मुश्किल ड्रॉ से पार पाकर भारत को पदक दिलाने की कोशिश करेंगे। भारत ने मुक्केबाजी में अभी तक तीन ओलंपिक पदक जीते हैं।7 इनमें विजेंदर सिंह एकमात्र पुरुष मुक्केबाज हैं। उन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। इसके चार साल बाद लंदन में एमसी मैरीकॉम और 2021 में तोक्यो ओलंपिक में लवलीना ने कांस्य पदक हासिल किया था।पेरिस ओलंपिक में भारत के छह मुक्केबाज भाग ले रहे हैं जिन्हें कठिन ड्रॉ मिला है। इनमें जरीन को पदक का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। इस 28 वर्षीय खिलाड़ी को 50 किग्रा भार वर्ग में चीन की वू यू, थाईलैंड की चुथामत रक्सट और उज्बेकिस्तान की सबीना बोबोकुलोव की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जरीन रविवार को जर्मनी की मैक्सी क्लॉटजर के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी, जिसके बाद उनका सामना एशियाई खेलों की शीर्ष वरीयता प्राप्त और मौजूदा फ्लाईवेट विश्व चैंपियन वू से हो सकता है। अगर जरीन यह बाधा पार कर लेती हैं, तो उनका सामना आठवीं वरीयता प्राप्त और एशियाई खेलों की रजत पदक विजेता रक्सट या बोबोकुलोवा से हो सकता है।

हम एशिया कप फाइनल में भी इसी लय को जारी रखना चाहते हैं: रेणुका

दाम्बुला। तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ने कहा कि भारतीय टीम अभी तक महिला एशिया कप में निरंतर क्रिकेट खेल रही है और फाइनल में भी इसी लय को जारी रखते हुए रविवार को ट्रॉफी उठाना चाहेगी। भारत ने शुक्रवार को यहां सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेट से रौंदकर फाइनल में जगह बनाई जिसमे प्लेयर ऑफ द मैच रेणुका ने चार ओवर मे एक मेडन से 10 रन देकर तीन विकेट का शानदार स्पैल डाला। रेणुका ने मैच के बाद प्रेस कांफ्रेंस मे कहा, हम अच्छा और निरंतर क्रिकेट खेलना चाहते है जैसा हम अभी तक टूर्नामेंट मे खेल रहे है। उम्मीद है कि हम एशिया कप जीतने मे कामयाब होगे। भारत खिताबी भिड़ंत मे पाकिस्तान और मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरे सेमीफाइनल के विजेता के सामने होगा। उन्होने कहा, यह मायने नही रखता कि हम फाइनल मे किसके खिलाफ खेल रहे है।

उद्घाटन समारोह में एथलीट परेड में हिस्सा लेगा 78 सदस्यीय भारतीय दल

भाषा। पेरिस

पेरिस ओलंपिक

पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान शुक्रवार को पीवी सिंधू और अचंत शरत कमल की अगुआई वाला भारतीय दल एथलीट परेड में हिस्सा लेगा जिसमें 12 प्रतिस्पर्धाओं के 78 एथलीट और अधिकारी शामिल होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने कहा कि जिन सभी खिलाड़ियों ने खुद को उद्घाटन समारोह के लिए उपलब्ध कराया है, वे परेड का हिस्सा होंगे।आईओए ने कहा, आईओए अध्यक्ष पीटी ऊषा और दल प्रमुख गगन नारंग ने एथलीट परेड में दल की संरचना में खिलाड़ियों को शीर्ष प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा, कई खिलाड़ियों की शनिवार को प्रतिस्पर्धा है और आईओए ने उनकी तैयारियों को प्राथमिकता देने और उद्घाटन समारोह में हिस्सा नहीं लेने के फैसले का सम्मान किया है। ध्वजवाहक सिंधू और शरत कमल के अलावा अन्य महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में तीरंदाज दीपिका कुमारी, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन, टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना शामिल हैं। नौकाचालक बलराज पंवार की शनिवार सुबह रेस है तो वह एथलीट परेड का हिस्सा नहीं बनेंगे। ट्रैक एवं फील्ड, भारोत्तोलन और कुश्ती की टीम अभी तक पेरिस नहीं पहुंची हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम का भी शनिवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच है तो केवल तीन रिजर्व खिलाड़ी ही समारोह में शामिल होंगे। भारत का 117 खिलाड़ियों का दल ओलंपिक में हिस्सा ले रहा है जिसमें 47 महिलाएं हैं। ओलंपिक इतिहास में पहली दफा उद्घाटन समारोह स्टेडियम में नहीं हो रहा बल्कि यहां सीन नदी के किनारे पर होगा। 90 नौकाओं में 6,500 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे।

पेरिस ओलंपिक के स्पर्धा के पहले दिन का भारतीय कार्यक्रम

पेरिस।(भाषा) पेरिस ओलंपिक के स्पर्धा के पहले दिन (शनिवार) का भारत का कार्यक्रम (भारतीय समयानुसार)

बैडमिंटन: पुरुष एकल ग्रुप मैच: लक्ष्य सेन बनाम केविन कॉर्डन (ग्वाटेमाला) (शाम 7:10 बजे), पुरुष युगल ग्रुप मैच: सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी एवं चिराग शेट्टी बनाम लुकास कोर्वी एवं रोनन लाबर (फ्रांस) (रात आठ बजे) महिला युगल ग्रुप मैच: अश्विनी पोनप्पा एवं तनीषा क्रास्टो बनाम किम सो एओंग एवं कोंग ही योंग (कोरिया) (रात 11:50 बजे)

मुक्केबाजी: महिलाओं के 54 किग्रा शुरुआती दौर का मुकाबला: प्रीति पवार बनाम थी किम अन्ह वो (वियतनाम) (रात 12:05 बजे)

हॉकी: पूल बी मैच: भारत बनाम न्यूजीलैंड (रात नौ बजे)

नौकायन: पुरुष एकल स्कल्स: पंवार बलराज (दोपहर 12:30 बजे)
टेबल टेनिस: पुरुष एकल पहला दौर: हरमीत देसाई बनाम जैद अबो (यमन) (शाम 7:15 बजे)

टेनिस: पुरुष युगल के पहले दौर का मैच: रोहन बोपन्ना एवं एन श्रीराम बालाजी बनाम एडवर्ड रोजर-वैसलीन और फैबियन रेबौल (फ्रांस) (दोपहर 03:30 बजे)

निशानेबाजी: 10 मीटर मिश्रित टीम क्वालिफिकेशन: संदीप सिंह I इलावेनिल वालारिवन, अर्जुन बबूता I रमिता जिंदल (दोपहर 12:30 बजे), 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष क्वालिफिकेशन: अर्जुन सिंह चीमा और सरबजोत सिंह (दोपहर दो बजे), 10 मीटर एयर पिस्टल महिला क्वालिफिकेशन: मनु भाकर और रिदम सांगवान (शाम चार बजे)

भारतीय हॉकी टीम पदक की प्रबल दावेदार बस अपना स्वाभाविक खेल दिखाएं : हरेंद्र

नई दिल्ली (भाषा)। कैरियर की शुरूआत से अब तक के उनके सफर को करीब से देखने वाले अनुभवी कोच हरेंद्र सिंह का मानना है कि भारतीय हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक में पदक की प्रबल दावेदार है। उनकी टीम को एक ही सलाह है, बस अपना स्वाभाविक खेल दिखाओ। अप्रैल 2024 में भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच बनने के बाद भाषा को दिए पहले इंटरव्यू में हरेंद्र ने कहा , मैं उन्हें यही सलाह दूंगा कि अपना स्वाभाविक खेल दिखाओ। भारतीय टीम पदक जीतने में सक्षम है। मैं पदक के रंग को लेकर कयास नहीं लगाऊंगा लेकिन पदक मिलेगा और यह मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं भारतीय हूं। उन्होंने कहा , भारत के पास अच्छी फॉरवर्ड लाइन है , शानदार मिडफील्डर और गोलकीपर पी आर श्रीजेश के रूप में भारतीय हॉकी की दीवार है। इसके अलावा हरमनप्रीत जैसा कूल कप्तान है। अमेरिका की पुरूष टीम के मुख्य कोच रहे 55 वर्ष के हरेंद्र ने कहा , क्रेग फुल्टोन शानदार कोच हैं और ओलंपिक पदक विजेता रह चुके हैं। उन्हें पता है कि चैम्पियन टीम बनने के लिए क्या चाहिए और दबाव के हालात से कैसे निपटना है। उन्हें यूरोपीय और भारतीय हॉकी का काफी अनुभव है। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हरेंद्र 2000 सिडनी ओलंपिक, 2005 जूनियर विश्व कप, 2006 विश्व कप, 2006 एशियाई खेल, 2009 एशिया कप और 2010 पुरूष हॉकी विश्व कप में विभिन्न भूमिकाओं में भारत की सीनियर और जूनियर टीमों के कोचिंग स्टाफ का हिस्सा रह चुके हैं। वह 2016 में लखनऊ में जूनियर विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के कोच थे। पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत 2016 की जूनियर टीम का हिस्सा थे। हरेंद्र ने 2015 में ही भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन वह भारत के कप्तान बनेंगे।1990 एशियाई खेलों के पदक विजेता ने कहा , हरमनप्रीत शानदार कप्तान है।

भारत के 12 साल के पदक सूखे को खत्म करने को तैयार निशानेबाज

शेटौरॉक्स (फ्रांस)।(भाषा) ओलंपिक में पदार्पण करने वाले निशानेबाजों से भरी टीम पिछले प्रदर्शन के बोझ से मुक्त होकर शुक्रवार को फ्रांस के शेटौरॉक्स में निशानेबाजी प्रतियोगिता में होने वाली परीक्षा में सफल होने का लक्ष्य बनाएगी। भारत ने अभी तक निशानेबाजी में कुल चार ओलंपिक पदक जीते हैं लेकिन पिछले दो ओलंपिक में खाता खाली रहा जिससे रिकॉर्ड 21 सदस्ईय भारतीय दल पर उम्मीदों का अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है। भारतीय राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ (एनआरएआई) टीम चुनने के लिए मौजूदा फॉर्म को तरजीह दी है और उसे उम्मीद है कि इस बार वे यहां पदक जीतेंगे। इसलिए ही कोटा विजेताओं को भी ट्रायल में उतारा गया जिसमें कम अनुभवी संदीप सिंह ने 2022 के विश्व चैम्पियन स्त्रांक्ष पाटिल को पछाड़ दिया जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में भारत के लिए कोटा हासिल किया था। पाटिल ने एनआरएआई को पत्र लिखकर ट्रायल में बरकरार रखने की बात रखी, लेकिन महासंघ अपने फैसले पर अड़ा रहा। मनु भाकर, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, अंजुम मौदगिल और इलावेनिल वलारिवान को छोड़कर अन्य सभी निशानेबाज पहली बार ओलंपिक मंच का अनुभव करेंगे। भारत 15 निशानेबाजी स्पर्धाओं में हिस्सा लेगा। विश्व स्पर्धाओं में कई पदक जीत चुकी 22 वर्षीय मनु तोक्यो ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालीफिकेशन में पिस्टल में आई खराबी से उबर नहीं सकी थीं। लेकिन इस बार वह बेहतर प्रदर्शन करना चाहेंगी, वह तीन स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगी जिसमें 10 मीटर एयर पिस्टल, 25 मीटर पिस्टल और 10 मीटर पिस्टल मिश्रित टीम शामिल हैं। भारत को मुख्य रूप से चुनौती चीन से मिलेगी जो विभिन्न स्पर्धाओं में 21 निशानेबाज उतार रहा है। एक अन्य महिला निशानेबाज सिफत कौर सामरा पर भी सबकी नजर होंगी जिन्होंने एशियाई खेलों में 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता था।

खेल महाशक्ति बनाने के लिए और नायक बनाने की जरूरत

नई दिल्ली (भाषा)। मुक्केबाज से नेता बने विजेंदर सिंह का मानना है कि अगर भारत को 2047 तक खेल महाशक्ति बनना है तो उसे क्रिकेट से इतर और नायकों की जरूरत है जो भावी पीढ़ियों को प्रेरित कर सकें। पूर्व ओलंपिक और विश्व चैम्पियनशिप के कांस्य पदक विजेता विजेंदर का मानना है कि ए नायक ज्यादा से ज्यादा युवाओं को खेल को पेशे के तौर पर अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। भाजपा नेता विजेंदर ने यहां पीटीआई के मुख्यालय में संपादकों से बातचीत में यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार का 2047 तक भारत को खेल महाशक्ति बनाने का लक्ष्य यथार्थवादी है तो उन्होंने कहा, हमें इस संस्कृति में बदलाव के लिए नायक बनाने होंगे। उन्होंने तोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा का जिक्र करते हुए कहा, पिछले कुछ साल में हमारे युवाओं, विशेषकर ग्रामीण इलाकों के युवाओं में अच्छा प्रदर्शन करने की भूख बढ़ती जा रही है। जब वे नीरज चोपड़ा को देखते हैं तो वे उनके जैसा बनना चाहते हैं। वे वह सब कुछ पाना चाहते हैं जो उनके पास है और यही उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। विजेंदर ने कहा, जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं केवल एक सरकारी नौकरी चाहता था। लेकिन आज एथलीट और अधिक चाहते हैं। भिवानी के इस मुक्केबाज ने यह भी कहा कि समग्र प्रगति सुनिश्चित करने के लिए देश के खेल बुनियादी ढांचे में सुधार महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, हमारे पास अच्छा बुनियादी ढांचा या अच्छे स्टेडियम नहीं हैं। अगर हम गंभीर हैं तो हमें इसमें सुधार करने की जरूरत है। आप सिर्फ एक क्रिकेट स्टेडियम बनाकर नहीं छोड़ सकते। आपको अन्य खेलों के लिए भी ट्रेनिंग सेंटर बनाने की जरूरत है। विजेंदर ने कहा कि बदलाव बुनियादी स्तर पर स्कूलों में शुरू होना चाहिए जहां पर बच्चों को सिर्फ एक पीरियड खेल के लिए मिलता है। क्रिकेट के साथ तुलना करते हुए देश के पहले मुक्केबाज विजेंदर ने कहा कि महान कपिल देव को भी 1983 विश्व कप जीतने से पहले लोग नहीं जानते थे। उन्होंने कहा, कितने लोग कपिल देव के बारे में जानते थे? विश्व कप जीतने से पहले बहुत से लोग उन्हें नहीं जानते थे। अब हम उस स्थिति में हैं जब अगर किसी क्रिकेटर की ऊंगली में चोट भी लग जाती है तो वो खबर बनती है। लेकिन जब किसी मुक्केबाज का जबड़ा टूटता है तो आपको शोर सुनाई नहीं देता, यह खबर नहीं बनती। विजेंदर ने कहा कि ओलंपिक पदक विजेताओं का भी उसी तरह स्वागत होना चाहिए जैसा कि इस महीने की शुरुआत में टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आयोजित विजय परेड के दौरान हुआ था। उन्होंने कहा, हमें (क्रिकेटर से इतर खिलाड़ियों को) बुरा लगता है क्योंकि हम भी देश के लिए पदक जीतते हैं। हमें भी मुंबई में हुए स्वागत के समान ही स्वागत का अधिकार है। विजेंदर ने कहा, ओलंपिक पदक विजेता का भी इसी तरह का स्वागत होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होगा। पदक विजेता का हवाईअड्डे पर मालाओं से स्वागत होगा, एक दिन टीवी पर दिखाया जाएगा और फिर वे प्रतियोगिता में वापस उतरेंगे। इस साल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से भाजपा में आए विजेंदर ने कहा कि अगर उन्हें भविष्य में खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाती है तो वह बतौर एथलीट अपने अनुभव का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा, अगर मैं खेल मंत्री बनता हूं तो मैं भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) को मजबूत बनाऊंगा। मुझे साइ से बहुत सहयोग मिला था, मैं इसे मजबूत बनाना चाहूंगा। भारत 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी का अधिकार हासिल करने के लिऐ बोली लगाने की योजना बना रहा है।

सीएमवाईके प्रिंटेक के लिए तथा उसी की ओर से मुद्रक एवं प्रकाशक शोबोरी गाँगुली द्वारा टिन टिन प्रिंटेक प्रा.लि. सी-33 अमौसी इंडस्ट्रियल एरिया, नादरगंज लखनऊ से मुद्रित एवं चौथी मंजिल, सहारा शापिंग सेंटर, फैजाबाद रोड, लखनऊ (फोन: 0522-4036600) से प्रकाशित। प्रधान सम्पादक: शोबोरी गाँगुली, स्थानीय सम्पादक: विजय प्रकाश सिंह। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं।